लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

[Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं)
(Vol. LIX contains Nos. 21—32)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया।

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 28, शुक्रवार, 2 सितम्बर, 1966/11 भाद्र, 1888 (शक)

No. 28, Friday, September 2, 1966/Bhadra, 11 1888 (Saka)

विषय SUBJECT

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			पृष्ठ/PAGES
808.	चलचित्रों के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Films	1—3
809.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था से ऋण	Loan from U. S. Agency for International Development ..	3—5
810.	दिल्ली में शटल गाड़ियों के चलने का समय	Timings of Shuttle Services in Delhi	6—8
811.	औद्योगिक विकास	Industrial Development	8—13
812.	हैवी इंजीनीयरिंग कारपोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ..	13—16
813.	कपड़े के दाम	Prices of Cloth ..	16—19
815.	अमृतसर से लाहौर तक रेलवे लाइन	Railway Line from Amritsar to Lahore	19—20
816.	कृषिजन्य वस्तुओं का निर्यात	Agricultural Exports ..	20—21
818.	कच्चे माल के भण्डार (बैंक)	Raw Materials Bank ..	21—24
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. Nos.			
22.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कलमस्सेरी (केरल)	Industrial Training Institute, Kalamassery (Kerala) ..	24—26
23.	केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों की पदावनति	Reversion of Executive Engineers in C. P. W. D.	26—32

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

814. चाय प्रतिनिधिमंडल का विदेशों का दौरा — Tea Delegation's Tour to Foreign Countries .. 32

817. राष्ट्रीय कोयला बोर्ड — National Coal Board .. 32

819. चाय पर निर्यात शुल्क — Export Duty on Tea .. 33

820. आयातित सामान पर विक्री कर — Sales Tax on Imported Stores 33

821. राज्य व्यापार निगम के पास आयातित अखबारी कागज — Imported Newsprint with S. T. C. 33—34

822. गाजियाबाद शाहदरा और दिल्ली के बीच विशेष रेल गाड़ियों के लिए मांग — Demand of Special Trains between Ghaziabad—Shahdara and Delhi 34

823. गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग — Industries in the Private Sector 34—35

824. वस्त्र नीति — Textile Policy .. 35

825. राजस्थान में घग्घर नदी में आई बाढ़ के कारण क्षति — Damage caused by Floods in Ghaggar River in Rajasthan 35—36

826. पंजाब में मुनाफाखोरों के विरुद्ध अभियान — Campaign against Profiteers in Punjab .. 36

827. उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उद्योग — Industries in the Eastern Districts of U.P. .. 36—37

828. भारत अफगानिस्तान व्यापार — Indo-Afghanistan Trade .. 37

829. बर्मा को नारियल जटा का निर्यात — Export of coir Yarn to Burma 38

830. ऊनी होजरी के लिए निर्यात संवर्धन योजना — Export Promotion Scheme for Woollen Hosiery .. 38

831. कपड़ा मिलों का बन्द होना — Closure of Textile Mills 38—39

832. फतहपुर और चुरू (राजस्थान) के बीच रेल यात्रा का किराया — Passenger Fare between Fatehpur and Churu (Rajasthan) 39

833. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड — Indian Iron and Steel Company, Limited .. 40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
834. रेलवे के अतिरिक्त इंजन	Extra Railway Engines ..	40
835. रेलगाड़ियों में पंखे और प्रकाश की व्यवस्था	Fans and Lights in Trains ..	41
836. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर पेट्रोल के टैंकरों का फट जाना	Explosion of Petrol Tankers on N. E. F. Railway ..	41—42
837. शामगढ़ रेलवे पर काम करने वाले कर्मचारियों को अनाज का दिया जाना	Supply of Foodgrains to Employees working at Shamgarh Railway Station ..	42
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4094. व्यासरपाडी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment at Vyasarpadi Station (S. Railway) ..	42—43
4095. हावड़ा बम्बई मेल की ट्रक से टक्कर	Truck Howrah Bombay Mail Collision ..	43
4096. मद्रास के निकट दुर्घटना	Accident near Madras ..	43
4097. दिल्ली और रोहतक के बीच रेलगाड़ी	Train between Delhi and Rohtak	44
4098. लखनऊ नाका रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	Over-bridge at Lucknow Naka Railway crossing	44
4099. अविकारी इस्पात से कपड़ा बुनना	Weaving of Stainless Steel into Textiles ..	45
4100. नेपाल से चावल	Rice from Nepal ..	45
4101. ट्रैक्टरों के मूल्य	Prices of Tractors ..	45—47
4102. दिल्ली और फीरोजपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में भीड़	Rush in Trains running between Delhi and Ferozepur ..	47
4103. बहादुरगढ़ स्टेशन पर यात्री प्लेटफार्म के ऊपर छत	Shelter at Bahadurgarh Railway ..	47—48
4104. कारों और स्कूटरों का नियतन	Allotment of Cars and Scooters ..	48
4105. गुजरात राज्य में छोटी (नैरो गेज) रेलवे लाइन	N. G. Railway Lines in Gujarat State	48

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4106. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के क्षेत्रीय काम करने के भत्तों की बकाया राशि	Arrears of Field Establishment Allowances for Employees of Geological Survey of India ..	48—49
4107. मत्स्य भोजन का निर्यात	Export of Fish Meal ..	49
4108. रेल किराये की वापसी के दावे	Claims for Refund of Railway Fare ..	49
4109. दिल्ली किशनगंज तथा शकूर-बस्ती स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन को दोहरा बनाना	Doubling of Railway Line between Delhi Kishanganj and Shakurbasti Stations ..	50
4110. रूज पाउडर की आवश्यकता और उत्पादन	Requirement and Manufacture of Rouze Powder ..	50—51
4111. उत्तर रेलवे के भण्डार नियन्त्रक तथा भण्डार उपनियन्त्रक	Controller and Deputy Controller of Stores of Northern Railway ..	51
4112. उत्तर रेलवे के मुख्यालय के कार्यालय की इमारत	Northern Railway Headquarters Office Buildings ..	51—52
4113. छत्तरपुर (रीवा) के एक मकान में विस्फोट	Explosion in House in Chattarpur (Rewa)..	52
4114. नागालैण्ड का सर्वेक्षण	Survey of Nagaland ..	52—53
4115. पंजाब में अखबारी कागज परियोजना	Newsprint Product in Punjab	53
4116. इलाहाबाद के निकट भारी पम्प और कम्प्रेशर सन्यन्त्र	Heavy Pumps and Compressor Plan near Allahabad ..	53
4117. अल्मोनियम संयन्त्र	Aluminium Plants ..	54
4118. विदेशों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Foreign Countries ..	54
4119. बीकानेर रेलवे स्टेशन	Bikaner Railway Station ..	55
4120. रेल की पटरी से फिश प्लेटों का हटाया जाना	Removal of Fish Plates from Railway Track ..	55
4121. खादी भवन	Khadi Bhawans	56
4122. इस्पात और मशीनों का निर्यात	Export of Steel and Machinery ..	56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4123. जोराई के निकट विस्फोटक पदार्थों का पकड़ा जाना	Seizures of Explosives near Jorai	57
4124. सिकन्दराबाद में रेलवे सिग्नल वर्कशाप	Railway Signal Workshop at Secundarabad..	57
4125. नई दिल्ली स्टेशन पर एक आदमी की मृत्यु	Death of a man at New Delhi Station	57—58
4126. कपड़ा मिलों को बैंकों द्वारा ऋण	Issue of Bank Advances to Textile Mills ..	58
4127. कोयला खानों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Coal Mines	58—59
4128. बस्तर में रेलवे लाइनों का विकास	Development of Railway Lines in Bastar ..	59
4129. जगदलपुर में कताई मिल	Spinning Mills at Jabalpur ..	59—60
4130. निर्यात संवर्धन पुरस्कार	Export Performance Awards ..	60
4131. पूना मिरज मालगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment of Poona Miraj Goods Train ..	60—61
4132. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कच्चे पानी की कमी	Shortage of unfiltered Water at New Delhi Railway Station	61
4133. तार बनाने वाला दूसरा कारखाना	Second Cable Factory	61—62
4134. हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल में बेकार पड़ी क्षमता	Idle Capacity in Heavy Electricals, Bhopal	62
4135. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यालय में आग लगने की घटना	Fire in N. C. D. C. Office	62—63
4136. इण्डियन इंजीनियरिंग वर्क्स इन्दौर	I. E. W., Indore ..	63
4137. पंचकुडा हल्दिया लाइन	Panchkura Haldia Line	64
4138. बिजली के सामान के दाम	Prices of Electrical Goods	64—65
4139. अम्बोडला स्टेशन के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment of Goods Train near Ambodala Station ..	65

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4140. काश्मीर में पोदार नीलम की खानें	Podar Sapphire Mines in Kashmir ..	65—66
4141. खनिज सलाहकार बोर्ड	Mineral Advisory Board	66
4142. रायवाला जंक्शन पर पेय जल	Drinking Water at Raiwala Junction	66
4143. भदोही (उत्तर रेलवे) में इंजन का पटरी से उतरना	Derailment at Bhadohi (N. Rly.) ..	67
4144. प्रस्फोटकों के संदूकों का लूटा जाना	Looting of Detonator Boxes ..	67
4145. भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार	Indo-Yugoslav Trade ..	68
4146. चोर बाजार में कार का पुन: विक्रय	Re. Sale of Car in Black Market	68
4147. प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार	G. A. T. T.	68—69
4148. भारवारी स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर लूट की घटना	Looting Incident at Bharwari Station (Northern Railway) ..	69
4149. सारवडी और जालना स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment between Sarwadi and Jaina Stations ..	69
4150. चक्रधरपुर डिवीजन में छंटनी	Retrenchment in Chakradharpur Division ..	69—70
4151. लखनऊ आगरा एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का प्रयास	Attempt to derail Lucknow Agra Express ..	70
4152. फोटोग्राफी के कागज की कमी	Shortage of Photographic Paper ..	71
4153. बरेली में कागज मिल	Paper Mill at Bareilly	71
4154. भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production at Bhilai Steel Plant ..	71—72
4155. भिलाई इस्पात कारखाने में बने माल का निर्यात	Export of Bhillai Steel Plant Products ..	72
4156. नेपाल का प्रतिनिधि मंडल	Delegation from Nepal ..	72—73

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4157. दियासिलाई के दाम	Prices of Match Boxes	73
4158. घड़ियों का निर्माण	Manufacture of Watches ..	73
4159. आसाम में ऐसी चट्टानों का मिलना जिनमें सोना मिलता है	Find of Gold Bearing Rocks in Assam	74
4160. कलकत्ता के निकट बाली स्टेशन पर डाकुओं की गिरफ्तारी	Arrest of Dacoit at Bali Station near Calcutta ..	74
4161. चमन लाल एण्ड ब्रादर्स	Chaman Lall and Brothers	75—76
4162. जस्ते की चादरों की मांग और पूर्ति	Demand and Supply of Zinc Sheets	76—77
4163. प्याज का निर्यात	Export of Onion	77
4164. पाकिस्तान से मछली तथा चावल का आयात	Import of Fish and Rice from Pakistan	77
4165. लालगढ़ में रेलवे अस्पताल का निर्माण	Construction of Railway Hospital at Lalgarh	78
4166. जयपुर में उद्योग	Industries in Jaipur	78
4167. हिन्दूमलकोट और श्रीगंगा-नगर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Hindu Malkote and Sri Ganga Nagar	78—79
4168. एक्स रे के उपकरणों का निर्माण	Manufacture of X-Ray Appliances ..	79
4169. व्यापार बोर्ड (बोर्ड आफ ट्रेड)	Board of Trade	79
4170. पश्चिमी बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in West Bengal ..	80
4171. ईरान को इस्पात की वस्तुओं का निर्यात	Export of Steel Goods to Iran	80
4172. वाराणसी में रेलवे फायरमैन	Railway Fireman in Varanasi	80—81
4173. ओवलटीन का उत्पादन	Manufacture of Ovaltine	81—82
4174. भूतत्वीय कार्यक्रमों संबंधी बोर्ड	Geological Programming Board ..	82
4175. साइकिल टायरों की कमी	Shortage of Cycle Tyres ..	82—83

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4176. सुपारी का आयात	Import of Arecanut ..	83
4177. दिल्ली में सुपर बाजार	Super Bazars in Delhi	83
4178. खेतरी परियोजना में उत्पादन	Production in Khetri Project	84
4179. सिमरा में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Simra	84
4180. उड़ीसा में भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey in Orissa	84—85
4181. रेजर ब्लेडों का निर्माण	Production of Razor Blades ..	85
4182. इंजिनियरी उद्योग के लिए उपयुक्त इस्पात	Matching Steel for Engineering Industry ..	86
4183. तीन पहियों वाली गाड़ी उद्योग	Three Wheeler Vehicle Industry	86—87
4184. काली मिर्च का निर्यात मूल्य	Export Prices of Black Pepper	87
4185. पूर्वोत्तर रेलवे के सिगनल विभाग के कर्मचारी	Employees of Signal Deptt. of the North Eastern Railway	87
4186. पूर्वोत्तर रेलवे में ड्यूटी रोस्टर	Duty Roster in the North Eastern Railway..	87—88
4187. वाराणसी के रेलवे सफाई कर्मचारी	Railway Sanitary Staff of Varanasi	88
4188. उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर पीने का पानी	Drinking Water at Stations on Northern Railway ..	88
4189. काजू उत्पादक	Cashew Growers ..	89
4190. पश्चिमी रेलवे के महाप्रबन्धक का कार्यालय	Office of the General Manager, Western Railway ..	89
4191. कोला खानों का बन्द किया जाना	Closure of Coal Mines	89—90
4192. सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries	90
4193. हावड़ा मद्रास एक्सप्रैस के एक डिब्बे में शव का मिलना	Dead body in a compartment of Howrah Madras Express ..	90—91
4194. मोटर से चलने वाली नौकाएं (मोटर लांच)	Motor Launches ..	91
4195. लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में कर्मचारी	Staff position in Iron and Steel Control Office ..	91—92

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4196. दक्षिण रेलवे में गैंगमैन और गेट कीपर	Gangmen and Gate keepers in Southern Railway	92—93
4197. इंजीनियरी कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Engineering Staff	93
4198. भारतीय कपड़े का निर्यात	Export of Indian Textiles	93—94
4199. भारतीय कपड़ा संवर्धन एकक	Indian Textiles Promotion Unit ..	94
4200. अत्यावश्यक वस्तुओं की सूची	List of Essential Commodities ..	94—95
4201. श्रीनगर को भेजे गये गेहूं का खराब हो जाना	Damage to Wheat transported to Srinagar ..	95
4202. कानपुर से आगे रेलवे का विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन)	Electrification beyond Kanpur	95—96
4203. दुर्गापुर में धातुमिश्रित इस्पात कारखाना	Alloy Steel Plant at Durgapur ..	96
4204. लघु उद्योग	Small Scale Industries ..	96
4205. चीनी मिट्टी के बरतनों का निर्यात	Export of Ceramics	97
4206. लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का कार्यालय	Office of the Iron and Steel Controller ..	97
4207. बल्गारिया के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Bulgaria	97—98
4208. डनलप टायर और ट्यूब	Dunlop Tyres and Tubes ..	98
4209. दिल्ली और बुलंदशहर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line Between Delhi and Bulandshahr ..	98
4210. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्	National Productivity Council ..	98—99
4211. भिलाई के लिये सलीपर प्रेसिंग प्लांट का आयात	Import of Sleeper Pressing Plant for Bhilai ..	99
4212. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा क्रयादेश	Export Orders by Hindustan Steel Ltd. ..	99—100
4213. इस्पात का निर्यात	Export of Steel ..	100
4214. इस्पात पिंडों का निर्यात	Export of Steel Ingots ..	100—101

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4215. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा अमरीका को कुंडलियों (कुआएल) का विक्रय	Sale of Coils by Hindustan Steel Ltd. to the United States	101
4216. साइकिलों का निर्यात	Export of Bicycles ..	102
4217. फर्मों का पंजीयन	Registration of Firms ..	102—103
4218. साइकिलों के निर्यातक	Exporters of Bicycles ..	103—104
4219. नारियल की आवश्यकता	Requirement of Coconut	104
4220. रबड़ का आयात	Import of Rubber ..	104—105
4221. जम्मू तथा काश्मीर में रबड़ के कारखाने	Rubber Factories in J. & K. ..	105—106
4222. रबड़ अनुसंधान संस्था	Rubber Research Institute ..	106
4223. रूस को जूतों का निर्यात	Export of Footwear to USSR ..	106—107
4224. भारतीय लोहा तथा इस्पात कम्पनी में नियुक्त विदेशी लोग	Foreign Personnel Employed in IISCO ..	107—108
4225. इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कार्य करने वाले भारतीय तकनीशन	Indian Technical Employed in IISCO ..	108
4226. औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र	Applications for Industrial Licences	109
4227. महाराष्ट्र के लिये सीमेंट का आवंटन	Allotment of Cement for Maharashtra ..	109
4228. महाराष्ट्र के लिये नालीदार जस्ता चढ़ी चादरों का नियतन	Allotment of C. G. I. Sheets for Maharashtra ..	109—110
4229. पांडिचेरी में जनता को नालीदार जस्ता चढ़ी लोहे की चादरों का दिया जाना	Allotment of C. G. I. Sheets for Public at Pondicherry	110
4230. पांडिचेरी के लिये सीमेंट का आवंटन	Allotment of Cement for Pondicherry ..	110—111
4231. रेलवे सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा चुने गये तृतीय वर्ग के कर्मचारी	Class III Employees selected by Railway Service Commission Allahabad ..	111

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4232. महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में खानों से खनिज पदार्थ निकालना	Exploitation of Mines in Maharashtra and Madhya Pradesh	..	111—112
4233. भारत में बनाये जाने वाले संश्लिष्ट (सिंथेटिक) सूत का दाम	Price of Synthetic Yarn Produced in India		112
4234. डिलक्स और सदर्न एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के बेरे	Bearers of De-luxe and Southern Express Trains	..	113
4235. माल्ट मिश्रित दुग्ध खाद्य पदार्थ (माल्टिड मिल्क फूड) का निर्माण	Manufacture of Malted Milk Food	..	113—114
4236. नारियल जटा से बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Coir Goods		114
4237. अंग प्रक्षालन कागज (टायलेट पेपर) का आयात	Import of Toilet Paper	..	114
4238. रबड़ का आयात	Import of Rubber	..	114—115
4239. डीजल लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी में भेजा गया पुराना माल	Second Hand Material supplied to Diesel Locomotive Works, Varanasi	..	115
4240. अनुसन्धान डिजाइन तथा मानक संस्था	Research, Design and Standard Organisation	..	115—116
4241. पारे का आयात	Import of Mercury	..	116—118
4242. अफगानिस्तान को चाय का निर्यात	Export of Tea to Afghanistan		118
4243. रेलवे कर्मचारियों द्वारा नगरपालिका के चुनाव लड़ना	Contest of Municipal Elections by Railway Employees	..	118—119
4244. चप्पलों और बीड़ियों का निर्यात	Export of Chappals and Bidis		119
4245. कोयले का उत्पादन	Coal Production	..	119—120
4246. मैसूर खादी बोर्ड	Mysore Khadi Board	..	120—121
4247. मैसूर में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Mysore	..	121—122
4248. मैसूर में रेशम उद्योग का विकास	Development of Sericulture in Mysore	..	122

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4249. मलूर में रेलवे पुल	Railway Bridge at Malur ..	122—123
4250. मैसर्स श्रीराम राम निरन्जन, बोम्बे द्वारा रेलवे को स्लीपरों की जाली सप्लाई	Bogus Supply of Sleepers to Railways by M/s. Shriram Ram Niranjan Bombay..	123
4251. इटारसी रेलवे स्टेशन	Itarsi Railway Station ..	123—124
4252, आयातित टेलीविजन सेट	Imported T. V. Sets ..	124
4253. सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार	Public Sector Monopoly ..	124—125
4254. खण्ड निरीक्षक (ब्लाक इंस्पेक्टर)	Block Inspectors ..	125
4255. उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना	Tractor Factory in U. P. ..	126
4256. फिएट कारों का आवंटन	Allotment of Fiat Cars	127
4257. बंगाल जूट मिल्स, हावड़ा	Bengal Jute Mills, Howrah ..	127—128
4258. दक्षिण-पूर्व रेलवे के वर्कशाप तथा अनुसचिवीय कर्मचारियों के पदों का ऊंचा किया जाना	Upgrading of Workshop and Ministerial Staff on S. E. Railway ..	128
4259. केरल में काफी बागान	Coffee Plantation in Kerala ..	129
4260-क. शिमला के कुछ भागों का धंसना	Sinking of Parts of Simla	129
अता० प्र० संख्या 787 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to U. S. Q. No. 787 ..	129—130
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention Notice to Matter of Urgent Public Importance—	
पाकिस्तान को अमरीकी सेबर जेट विमानों का दिया जाना	Supply of U. S. Sabre Jets to Pakistan ..	130—133
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa ..	130
वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)	The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) ..	130—131
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	133—134
सदस्य की गिरफ्तारी (श्री बीरेन दत्त)	Arrest of Member— (Shri Biren Dutta)	134

सदस्य की पेरोल पर रिहाई (श्री याज्ञिक)	Release on Parole of Member— (Shri Indulal Yajnik)	.. 135
त्रिपुरा में उपद्रवों के बारे में	Re. Disturbances in Tripura	.. 135—138
खाद्य, मंत्री द्वारा अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये खाद्यान्नों में लोहे के टुकड़े तथा कंकड़ आदि के पाये जाने के बारे में दी गई जानकारी के सम्बन्ध में वक्तव्य तथा इस बारे में मंत्री महोदय का उत्तर	Statement Re. Information given by Food Minister on presence of Foreign matter in Foodgrains from USA under PL 480 and Minister's Reply thereto	.. 139—140
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	139
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	140
आर डिगनम एण्ड कम्पनी पर छापों के बारे में	Re. Raids on the Premises of Orr Dignum and Co.	.. 141
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	Representation of the people (amendment) Bill	141—151
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to Refer to Joint Committee	.. 141
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	.. 142—144
श्री उमा नाथ	Shri Umanath	.. 145—146
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	.. 146—147
श्री त्यागी	Shri Tyagi	147
श्री बड़े	Shri Bade	.. 147—148
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	.. 148—149
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravartty	.. 149—151
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	151
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति पचानवेंवां प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions— Ninety-fifth Report	151
योजनाओं के पुनर्विन्यास के बारे में संकल्प	Resolution Re. Reorientation of Plans	151—163 & 165—168
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	.. 151—154
श्री उमा नाथ	Shri Umanath	.. 155—156
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Sidheshwar Prasad	.. 156—157
श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	.. 157

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री श्रीनारायनदास	Shri Shree Narayan Das	.. 157—158
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	.. 158—159
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	.. 159—160
डा. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	.. 160—161
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	.. 161—162
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	162
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	163
श्री रंगा	Shri Ranga	.. 165—166
श्री अशोक मेहता	Shri Ashoka Mehta	166—167
स्वर्ण नियन्त्रण में ढील देने के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Relaxation of Gold Control—	
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	.. 163—164
मद्रास के लिये पीने के पानी सम्बन्धी योजना के बारे में संकल्प—	Resolution Re. Scheme for Drinking water for Madras—	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	.. 168

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 2 सितम्बर, 1966/11 भाद्र, 1888 (शक)
Friday, September 2, 1966/ Bhadra 11, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चलचित्रों के लिए विदेशी मुद्रा

*808. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशी मुद्रा की कमी का फिल्म उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है जिसके फलस्वरूप काफी कम चलचित्र बन रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस गत्यावरोध को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). फिल्म उद्योग के लिए कच्ची फिल्मों, स्टूडियो उपकरणों तथा अन्य सहायक वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन में कमी नहीं की गई है । वर्तमान स्थिति को देखते हुए और अधिक विदेशी मुद्रा देना संभव नहीं है ।

Shri Yashpal Singh : May I know the amount of money being spent on the import of foreign films ?

Shri Manubhai Shah : Foreign films are imported in different ways. A very small amount is, however, paid in cash under our agreement with the American Exporters Association, the whole amount payable to them is blocked. Out of this money certain percentage is spent by us on film production and certain percentage on development here and the rest small amount is allowed to be taken out of this country by instalments.

Shri Yashpal Singh : When Government think that there is acute shortage of foreign exchange and this problem cannot be solved, why foreign scenes are included in films as has been done in the case of the film called "Love in Tokyo" ? Is there no good scenery here ?

Shri Manubhai Shah : It so happens that when we want to show to the foreigners any acceptable thing, we have to go by their taste. It is also not correct to think that all the good things of the world are available in India alone. When we want to export any film worth two or four crores of rupees, we have to see what they like.

श्री शशिरंजन : अवमूल्यन के पश्चात कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और उसमें से फिल्म उद्योग को किस अनुपात से दी गई ?

श्री मनुभाई शाह : अभी हमने दो करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जारी की है। यथा समय दो करोड़ रुपये की और विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर 4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई है और आशा है कि फिल्मों के निर्यात से 4-5 करोड़ रुपये की आय होगी। इस प्रकार ये निर्यात-आयात परस्पर प्रतिसंतुलित हो जायेंगे।

डा० रानेन सेन : विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण विदेशों से फिल्मों के आयात में कमी हो गई है। क्या यह सच है कि कई मामलों में उत्पादकों की अच्छी फिल्में, जो न केवल भारत में ही लोक-प्रिय हों परन्तु उनका निर्यात भी किया जा सके, बनाने की क्षमता का पता लगाये बिना फिल्मों के लिये आयात लाइसेंस दिये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इस प्रकार से लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं। कोरी फिल्मों का आयात निर्यात से होने वाली आय से संबद्ध होता है। रंगीन तथा काली एवं सफेद फिल्मों के आयात पर निर्यात से होने वाली आय का क्रमश: 75 प्रतिशत तथा 37.5 प्रतिशत खर्च किया जाता है। इस खर्च का निर्यात से होने वाली आय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। उत्पादकों में कोरी फिल्मों का वितरण फिल्म सलाहकार समिति की सलाह से किया जाता है जिसमें मुख्य फिल्म उत्पादकों के संघों के प्रतिनिधि होते हैं। हमें ऐसे किसी मामले की शिकायत नहीं मिली है जिसमें कोई कह सके कि वितरण ठीक प्रकार से नहीं हुआ है।

श्री दी० चं० शर्मा : इस वर्ष किस फिल्म कम्पनी को अधिकतम विदेशी मुद्रा दी गई ? इस कम्पनी को इतनी अधिक विदेशी मुद्रा क्यों दी गई और किस फिल्म के लिये दी गई ?

श्री मनुभाई शाह : मुझे वैयक्तिक फिल्म-उत्पादकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी उत्पादक का, जिसके बारे में वह जानना चाहते हैं, नाम बता सकें तो मैं यह जानकारी दे सकता हूं। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, किसी उत्पादक के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता है। मंत्रालय द्वारा कोरी फिल्मों का वितरण दी इण्डियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन तथा विभिन्न प्रादेशिक संघों के प्रतिनिधियों की सलाह से किया जाता है।

Shri Bade : Has the attention of Government been drawn to the criticism appeared in the "Dharma Yuga" that a lot of money is spent on films like "Love in Tokyo" and other exportable films. An assurance had heen given that foreign exchange of Rs. 3 crores would be given to India whereas only Rs. 2 crores have been received in foreign exchange and thus we have incurred a loss of Rs. 1 crore. Is it a fact ?

Shri Manubhai Shah : No such assurances were given. The people go on presuming such things. If there is anything in any contract it is this that 75 per cent. of their earning would be sent to us.

Shri Bade : Has there been any loss in it or not ?

Shri Manubhai Shah : There has been no loss.

Shri Tulsidas Jadhav ; Is it not the policy of the Government that less and less amount should be spent on this industry in view of the shortage of foreign exchange ?

Shri Manubhai Shah : There is no such policy. Lakhs of people are engaged in the film industry. Moreover in order to maintain the cultural life of India and also to amuse the cinema-goers and the artists, certain amount of film industry is very essential.

श्री हेम बरुआ : महोदय, मेरे माननीय मित्रों ने माननीय मंत्री का ध्यान "लव इन टोकियो" नामक फिल्म की ओर दिलाया है । यद्यपि भारत में प्यार के लिये काफी स्थान है तथापि इसमें टोकियो का दृश्य दिया गया है और यह फिल्म जापान के केवल सुन्दर दृश्यों तथा वास्तुकला की सुन्दरता प्रस्तुत करने में सफल रही है । यह फिल्म किसी भी सूचना विभाग के लिये उपयुक्त है यदि जापान में ऐसा कोई विभाग हो । इस सन्दर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार विदेशी मुद्रा का आवटंन करते समय निर्माता द्वारा निर्मित की जाने वाली फिल्म की लिपि तथा उसके प्रकार के बारे में अपना समाधान कर लेती है ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां, जहां तक फिल्म उद्योग का सम्बन्ध है, इसकी देख रेख मेरे माननीय साथी सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा की जाती है। मेरा सम्बन्ध केवल कोरी फिल्मों पर आने वाली आयात-लागत से है । यदि माननीय सदस्य के पास किसी फिल्म विशेष के बारे में कोई निश्चित जानकारी है तो इस कार्य को देखने के लिये एक पूरा मंत्रालय है और प्रश्न उससे पूछा जा सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था से ऋण

+

*809. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री दिगे :**

क्या **रेलवे** मंत्री 15 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1153 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डीजल इंजन बनाने के लिये उपकरणों का आयात करने के हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था के साथ ऋण के बारे में हुई प्रारम्भिक बातचीत को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और आयात-निर्यात बैंक दोनों से प्रारम्भिक बातचीत के बाद, अब वाशिंगटन के आयात-निर्यात बैंक से ऋण मांगा गया है। ऋण के आवेदन-पत्र पर बैंक विचार कर रहा है।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know the amount of loan sought by the Government of India from this Agency ?

Shri Sham Nath : We have had talks with the Export Import Bank and it is hoped that an amount of 12.5 million dollors would be made available to us by them as loan.

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether this imported equipment would be utilised in the existing diesel locomotives factory or any other factory would be set up for this purpose as there is shortage of Diesel Locomotives in India ?

Shri Sham Nath : There is no such thing. The capacity of the factory at Varanasi is adequate and there as many locomotives can be manufactured as are required by us.

श्री प्रिय गुप्त : क्या भारत सरकार अथवा रेलवे मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करेगा कि इन उपकरणों का, जिनके लिये हमें विदेशी ऋण का उपयोग करना पड़ रहा है, भारत में ही निर्माण हो जिससे इस ऋण का उपयोग उचित ढंग से किया जा सके और इसका उपयोग केवल अंश सामग्री का आयात करने पर ही न करना पड़े ?

श्री शाम नाथ : देश में उपकरणों का निर्माण करने के लिये पूरा पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। इस समय 30 प्रतिशत उपकरण यहीं बनाये जाते हैं। आशा है कि अगले वर्ष तक 44 प्रतिशत उपकरण यहीं पर तैयार होने लगेंगे और तत्पश्चात उत्तरोत्तर अधिक उपकरण यहीं बनने लग जायंगे। इसमें कुछ समय लगेगा।

श्री प्रिय गुप्त : महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस ऋण में से कुछ राशि देश में अंश-उपकरणों का निर्माण करने पर खर्च की जायेगी ?

श्री शाम नाथ : इस ऋण का उपयोग मुख्यतः कुछ पुर्जों तथा कुछ मशीनी उपकरणों का आयात करने के लिये किया जायेगा।

Shri Bhagwat Jha Azad : I congratulate Shri Patil for getting a loan from America. But is it not a fact that when a high level delegation of Government Officials had visited America before he went there, the American moneylenders refused to give any loan because the diesel locomotive factory had been set up at Varanasi and said that instead diesel engines could be imported from America. May I know whether his attention has also been drawn to any such thing there ?

The Minister of Railways (Shri S. K. Patil) : There is no truth in it.

श्रीमती सावित्री निगम : बैंक द्वारा कितना ब्याज लिया जाता है ? इसे कितने वर्षों में लौटाना होगा ? क्या निर्यात से आय में वृद्धि करने के हेतु डीजल इंजिनों के निर्यात करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कितनी राशि के इंजिनों का निर्यात किया जायेगा ?

श्री शाम नाथ : अब तक लगभग 17.15 करोड़ रुपये के दो ऋण लिये गये हैं। इन्हें लगभग 12 वर्षों में लौटाया जाना है। इन पर ब्याज की दर $5\frac{3}{4}$ प्रतिशत तथा $5\frac{1}{4}$ प्रतिशत है। निर्यात-आयात बैंक से मिलने वाले ऋण सम्बन्धी शर्तों के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया।

Shri U. M. Trivedi : Has this been brought to the notice of Government that metre gauge locomotives are not available and is it not a fact that a lot of difficulty is being experienced as a result thereof and that ghat sections cannot work with W. P. engines as there are daily derailments ? If so, whether the requisite type of locomotives would be manufactured for these sections also ?

Shri Sham Nath : At present, mostly the broad gauge engines are being manufactured.

श्री अ० प्र० शर्मा : हमें कितने डीजल इंजिनों की आवश्यकता है और इनमें से कितने देश में ही बनाये जाते हैं और कितने बाहर से मंगाये जाते हैं ?

श्री शाम नाथ : जुलाई, 1966 तक हम 62 इंजिन बना सके थे। इसके अलावा अमरीका से प्राप्त हुए 12 इंजनों को समवेत भी किया गया था। इस समय हम एक महीने में 5 इंजिनों का निर्माण कर सकते हैं परन्तु इसको बढ़ाकर एक वर्ष में 100 इन्जिनों का निर्माण किया जा सकता है।

श्री अ० प्र० शर्मा : हमारी वर्तमान आवश्यकता कितनी है ?

श्री शाम नाथ : प्रतिवर्ष 60-70 इंजिन।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the terms for the repayment of these loans ?

श्री शाम नाथ : मैंने पहले ही बता दिया है कि इन्हें 12 वर्षों में लौटाया जायेगा। ब्याज की दरें भी बता दी गई हैं। इन ऋणों के सम्बन्ध में अन्य शर्तें बताने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In what form these loans are to be repaid ?

श्री शाम नाथ : डालरों में।

Shri Tulsidas Yadhav : There is overcrowding on narrow gauge lines and the engines which are provided there often, go out of order. Do Government propose to supply diesel engines for these narrow gauge lines and if so, when ?

Shri Sham Nath : The question relates to diesel locomotives. So far as narrow gauge and metre gauge lines are concerned, at present steam locomotives are being used. If there is any defect in them, efforts are always made to remove it.

दिल्ली में शटल गाड़ियों के चलने का समय

+

*810. **श्री बागड़ी :** **श्री मौर्य :**
श्री किशन पटनायक : **श्री राम सेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री मधु लिमये :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में दफ्तरों तथा दुकानों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों से, जो कि दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों में रह रहे हैं, ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली तथा उपनगरों के बीच चलने वाली 'शटल' गाड़ियों के चलने के समय ठीक नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दफ्तरों में काम करने वाले इन लोगों की सुविधानुसार गाड़ियों के चलने के समय में परिवर्तन करने का है और भारी भीड़ को देखते हुये क्या सरकार का विचार अतिरिक्त शटल गाड़ियां चलाने का भी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) नं० 2 डी पी और 4 डी पी पानीपत-दिल्ली शटल गाड़ियों के वर्तमान अनुसूचित समय में यात्रियों की आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तन करने की व्यावहारिकता पर विचार किया जा रहा है । अपेक्षित लाइन क्षमता और पर्यन्त सुविधाओं के अभाव में इस समय दिल्ली क्षेत्र में कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

Shri Bagri : The Hon. Minister has simply stated in his reply that it is under consideration. I want to submit to the Hon. Minister that inconvenience is generally experienced by the class of persons to which he himself belongs. Is the Hon. Minister in a position to give an assurance that expeditious action will be taken in this regard ?

Dr. Ram Subhag Singh : So far as the question of taking expeditious action is concerned, a complaint has also been received for amending the Time Table. At present two trains come from Panipat side : One arrives here at 9.45 a.m. and the other at 10.25 a.m. The people have requested to run these trains a little earlier. We are considering to change the arrival timings of these two trains to 8.45 and 9.25 respectively. This will give them much relief. To what extent passenger amenities should be provided in other trains running between Delhi, New Delhi and Meerut or between Delhi, New Delhi and Ghaziabad or in trains coming from Rohtak or Faridabad sides, is also under consideration. By November the socond bridge over Jamuna will be opened for goods traffic. By the diversion of goods traffic to the other side, the capacity between Sahibabad and Delhi will be released and accordingly efforts will be made to give adequate facilities.

Shri Bagri : Are Government arranging to run a new train for the convenience of these passengers and if so, by what time it will be pressed into service ?

Dr. Ram Subhag Singh : That is what I have stated that we are considering all the aspects to solve the problems of Delhi passengers. Until the second bridge is opened, it will

not be possible to run a new train. At present in all 34 trains are running, in some of which new coaches have been added and some are new trains. But that has not solved the entire problem. We will further consider it after the opening of the second bridge.

Shri Bagri : When will it be opened ?

Dr. Ram Subhag Singh : In November. Only two months remain.

Shri Kishen Pattnayak : The conveyance in Delhi is the worse and costlier as compared to that in the other cities of India. Are Government in a position to accept the suggestion that the railway officers and bus transport officers should draw a coordinated plan for Delhi with a view to providing facilities to the people of Delhi ?

Dr. Ram Subhag Singh : We shall consult the D. T. U. officers in this connection and also try to find out solution to the problems of the passengers.

Shri A. P. Sharma : For what periods the income of the railway from local passengers is calculated. Are these facilities provided on the basis of the sale of tickets or on any other basis ?.

Dr. Ram Subhag Singh : As a matter of fact the sale of tickets is also one of the basis. Side by side other factors are also taken into consideration in the matter of providing facilities, sueh as volume of traffic, the growth of population, the importance of Delhi city and of others adjoining towns. The reason for this is that the boys of Delhi go to the colleges of almost every neighbouring district. In addition to this the goods and cattle traffic is also taken into consideration. A census of all these things is held periodically.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : For the last four years we have been repeating our demand for running a train between 11.10 A. M. to 4.45. P. M. between Delhi and Jind. I do not know for how long you will consider this question. It is my submission that this being a military area a train to and from Delhi-Jind be provided at an early to relieve the passengers of this area. This will also result in increased earnings to the Railway.

Dr. Ram Subhag Singh : We will also consider this. Towards Haryana side recently a new Haria Express train ....

Shri Jagdev Singh Siddhanti : That goes via Rewari.

Dr. Ram Subhag Singh : Rohtak is also a part of Haryana. Jind is situate on Delhi-Rohtak route— I have already stated this in answer to Shri Bagri's question.

Shri Kashi Ram Gupta : On the metre gauge Rewari line of Northern Railway the students, going from Patel Nagar to Gurgaon in the morning, have to travel without ticket in the first class by the 4-Down Express train in the absence of any train for their return. This is happening almost daily. Do Government propose to take any measures to relieve them of their difficulties. What steps have been taken to check this travelling by first class without ticket ?

Dr. Ram Subhag Singh : We shall give due thought to the students difficulties and see what facilities can be given to them. But the Hon. Member should also exhort the students to travel with ticket and only in that class for which they purchase the ticket. If they want we can give them the facility of seasonal tickets. I would also request the College

authorities to see that the students travel with ticket in the relevant class. We shall try to meet their legitimate demands.

Shri Kashi Ram Gupta : Except one train there is no other train for them. That train does not stop at Patel Nagar. Therefore they have to resort to it. What arrangements are being made to run a new train ?

Mr. Speaker : That will also be considered.

Industrial Development

*811. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether adequate attention is being paid to the fact that regional imbalances are not created while formulating programmes for industrial development; and

(b) the steps taken to keep the production costs of the various industries within a certain limit from the point of view of the international market ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). जानकारी देने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) पिछले कुछ वर्षों से स्वेच्छा से आधुनिक तकनीक अपना कर और अलग अलग एककों का आकार क्षमता बढ़ाने की नीति के द्वारा भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा में सुधार करने के लिए प्रयत्न किए गये हैं । अनेक उद्योगों जैसे कागज, सीमेंट, कास्टिक सोडा, गंधक का तेजाब, उर्वरक इत्यादि के औसत आकार पिछले 10 से 15 वर्ष की तुलना में अब काफी बढ़ गये हैं ।

उद्योगों की पूरी क्षमता तथा विशेषकर प्राथमिकता वाले उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से सरकार की वर्तमान नीति उन्हें आवश्यक कच्चे माल का आयात करने के लिए काफी विदेशी मुद्रा देने की है जिससे प्रत्येक एकक के ऊपरी खर्च में कमी की जा सके ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति को स्थिर रखने के लिए तैयार माल के निर्यातकों द्वारा आयातित कच्चे माल के लिए उनके द्वारा दिये गये आयात शुल्क की राशि की वापसी की भी व्यवस्था है । अनेक वस्तुओं के मामले में तैयार माल के निर्यातकों को उत्पादन शुल्क भी नहीं देना पड़ता है ।

Shri Sidheshwar Prasad : In the statement it has not been indicated as to the extent to which the regional imbalance has increased as a result of the industrial development made over these years. In this connection the studies of the Government, Planning Cammission and National Council of Applied Economic Research make it abundantly clear that the regional imbalance has increased in the country. What action Government is taking to counteract this regional imbalance ?

श्री संजीवय्या : पहला कदम अल्प विकसित क्षेत्रों में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित करना है : मैं कुछ का उल्लेख कर सकता हूं : रूरकेला, भिलाई, रांची, भूपाल हैवी इलैक्ट्रीकल्स, निवेली, आदि ।

दूसरा कदम है गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को स्थापित करना ।

तीसरा है औद्योगिक विकास क्षेत्रों की स्थापना, ताकिं उद्योगपति वहां पर सरलता से जा कर उद्योग स्थापित कर सकें ।

चौथे, औद्योगिक विकास निगम के द्वारा सहायता दी जाती है ।

इस तरीके से हम प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने का प्रयत्न करते रहे हैं ।

श्री रंगा : प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा पिछले 19 वर्षों में जो प्रयत्न किये गये हैं उसके बावजूद भी प्रादेशिक असंतुलन बढ़ते गये हैं ।

श्री संजीवय्या : माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद द्वारा दिए गये प्रतिवेदन का उल्लेख किया । मैं निश्चय ही प्रतिवेदन को देखूंगा और यह पता लगाने का प्रयत्न करूंगा कि हम उन पर किस तरह से काबू पा सकते हैं ।

Shri Sidheshwar Prasad: The Statement enumerates the steps taken by Government, over the past years, to bring down the cost of production. May I know whether the cost of production has risen or fallen in comparision to what it was in 1950-51, if due to higher cost of production our products are being rendered uncompetitive in the international market, what action is being taken by Government in this regard ?

श्री संजीवय्या : जी हां, हम अनेक उपाय कर रहे हैं । उदाहरणार्थ, उत्पादन लागत को घटाना, व्यक्तिगत एककों को पूरी क्षमता पर चलाने की अनुमति देना आवश्यक है । कुछ कारखाने क्षमता के 60 या 70 प्रतिशत पर कार्य कर रहे थे । अब उदार आयात नीति के कारण हम उनको कच्चा माल और पुर्जे देने की स्थिति में हैं जिससे कि ये पूरा उत्पादन कर सकेंगे । पहली चीज तो यह है ।

दूसरे कुछ कारखाने ऐसे हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं । अतः हमने कुछ नियम रखे हैं—चाहे चीनी मिल हो या कपड़ा मिल हो—कि किसी भी कारखाने को निम्नतम क्षमता से नीचे काम नहीं करना चाहिए और हम वर्तमान कारखानों के विस्तार की अनुमति दे रहे हैं ताकि वे अधिक कुशलता से कार्य कर सकें । हम उनके लिए आधुनिक टैक्नालोजी की भी व्यवस्था कर रहे हैं । इन सारे प्रयत्नों से लागत में निश्चय ही कमी होगी । परन्तु मैं निश्चित रूप से यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि लागत में किस हद तक कमी हुई है ।

Shri M. L. Dwivedi: In the statement it has been given that the exporting industries are given the facility to import raw materials. But hundreds of hosiery units in Ludhiana are

closing down because the facility to import yarn under the import promotion scheme is not available to them. Since they cannot import yarn their work is being paralysed. About 200 units have been closed down there. What action Government is taking to improve this situation.

श्री संजीवय्या : माननीय सदस्य ने मुझे इसकी जानकारी दी है। मैं वाणिज्य मंत्री से इस मामले पर बातचीत करूँगा।

Shri M. L. Dwivedi : It is their duty to supply raw material to the hosiery industry. The Commerce Minister is also sitting here ; he may tell us in this connection.

Shri Buta Singh : Hosiery industry has made several representations to the Hon. Minister. He says that the information is given by the Hon. Member.

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) . यह जानकारी गलत है। हमने एक लाइसेंस बाद में जारी किया है। शायद वह.....

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं पहले गया था।

श्री मनुभाई शाह : सच तो यह है कि ऊन उद्योग के लिए 12 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा दी गई है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या देश में इस समय उद्योगों की बेकार क्षमता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है और क्या इन उद्योगों की कठिनाइयां केवल कच्चा माल खरीदने की ही हैं जिसके लिए कि नीति बनाई गई है या कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है ? उद्योगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है ताकि वे पूरी क्षमता पर कार्य कर सकें ?

श्री संजीवय्या : एक सर्वेक्षण किया गया है। कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में बिजली की कमी, स्टॉक का जमा हो जाना आदि कारणों से भी उत्पादन में कमी हुई है। ऋण की सुविधाओं को संकुचित कर दिया गया है इसलिए भी उनको ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन सभी पहलुओं पर विचार किया गया है और हम न केवल कच्चा माल देने के लिए अपितु ऋण देने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि कारखानों को बिजली बराबर मिलती रहे ताकि कारखाने पूरी क्षमता पर चलते रहें।

Shri R. S. Pandey : May I know whether Government have conducted a Survey to find out what raw materials are available in the different States in the country, if so with what result ?

श्री संजीवय्या : मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न मेरे साथी खान तथा धातु मंत्री से पूछा जाये।

श्री कपूर सिंह : जानकार लोगों में एक प्रबल धारणा फैली हुई है कि पंजाब को उद्योग के मामले में पिछड़ा हुआ रखने के लिए एक 'मोरगंथो' योजना है। क्या यह सच है।

श्री संजीवय्या : जी नहीं ।

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that the per capita output in our country is lower as compared to that in other countries which accounts for higher cost of production ; if so, the steps being taken by Government in this regard ?

श्री संजीवय्या : यही कारण है कि हमने उत्पादिता बढ़ाने के लिए आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ।

श्रीमती विमला देवी : माननीय मंत्री ने कहा कि असंतुलनों को दूर किया जा रहा है । यदि ऐसा है तो प्रत्येक राज्य में उद्योगों से होने वाली आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री संजीवय्या : मैं इस समय सारा ब्योरा देने की स्थिति में नहीं हूँ । यह जानकारी देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए ।

श्री दाजी : श्रीमन्, यह जानकारी दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा; मैं उनसे कहूँगा ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि यद्यपि ब्रिटिश आयोग ने, मेरा ख्याल है, इस्पात कारखाने को विशाखापटनम में स्थापित करने की सिफारिश की थी, सरकार ने—उसके अपने राजनीतिक उद्देश्य हैं—उस सिफारिश को अभी तक स्वीकार नहीं किया है । तो क्या इसका अर्थ हम यह समझें कि सरकार इन बातों का फैसला तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिश पर करती है या वह गैर-तकनीकी अथवा आंशिक राजनीतिक अथवा पूर्ण राजनीतिक विचारों के आधार पर फैसला करती है ?

श्री संजीवय्या : अच्छा होगा यदि यह प्रश्न लोहा तथा इस्पात मंत्री से किया जाय ।

श्री रंगा : प्रश्न असन्तुलनों के बारे में है । कुछ क्षेत्र हैं जिनका विकास किया जाना है और उनके बारे में सरकार को विशेषज्ञों की राय के अनुसार नीति बनानी है ।

श्री संजीवय्या : यह सर्वविदित है कि सरकार ने पांचवें इस्पात संयंत्र के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है ।

श्री रंगा : इसमें देर क्यों लगाई जा रही है ?

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इस स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पिछली तीन योजनाओं के दौरान प्रादेशिक असंतुलनों में अधिक वृद्धि हुई है, चतुर्थ योजना के दौरान उनमें कमी लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ? क्या यह सच नहीं है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में केन्द्र द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का अनुचित आवंटन इसका एक बड़ा कारण है । उत्तर प्रदेश में जो कि इस सम्बन्ध में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ राज्य है, उन कारखानों को भी—हिन्दुस्तान केबल ऐंड ट्रैक्टर फैक्ट्रीज—अन्य स्थानों पर ले जाया जा रहा है जिनको बरेली के पास रामनगर में स्थापित करने के लिए स्वीकार कर लिया गया था ।

श्री संजीवय्या : यह कहना सही नहीं है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्थापित किये जाने के मामले में प्रादेशिक पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता है। उनको ध्यान में रखा जाता है, उन पर विचार किया जाता, परन्तु कभी-कभी तकनीकी पहलुओं और एक विशिष्ट परियोजना के स्थान के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं पर ध्यान देना आवश्यक बन जाता है।

अब मैं अपने मंत्रालय से सम्बन्धित प्रश्न के दूसरे भाग को लेता हूँ। दूसरे केबल कारखाने के स्थान के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया था। मामला अभी विचाराधीन है।

श्री त्यागी : परन्तु विशेषज्ञों ने तो राय दी थी।

श्री संजीवय्या : विशेषज्ञों की राय उस स्थान के पक्ष में नहीं है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में प्रादेशिक असंतुलन का मुख्य कारण संचार साधनों की कमी है। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या एक बड़ी लाइन के लिये मराथवाडा की निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री का इरादा इस प्रश्न पर सम्बन्धित मंत्रालयों, विशेष रूप से रेलवे से लिखा पढ़ी करने का है?

श्री संजीवय्या : रेलवे मंत्री यहां पर उपस्थित हैं और उन्होंने इसको सुन लिया है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : आप इसको अपने कार्यक्षेत्र में समझते हैं या नहीं?

श्री संजीवय्या : मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उद्योगों के स्थापित किये जाने के मामले में संचार साधनों पर भी विचार किया जाना चाहिये।

Shri Buta Singh : If we draw a comparison between the industry of Punjab and that of Gujarat we will notice that the later has been given more facilities than those given to the former consequent on which the textile and wool industries in Amritsar and Ludhiana are being paralysed. What arrangements are being made by Government to meet this shortage?

श्री संजीवय्या : कुछ कारणों से कुछ कारखाने बन्द कर दिये गये थे। उनको विशेष ऋण सुविधाएं आदि देकर पुनः चालू करने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाये हैं।

श्री बूटा सिंह : मेरे प्रश्न के पहले भाग का क्या बना। गुजरात में उद्योग-पतियों को जो सुविधाएं दी गई हैं उसकी अपेक्षा पंजाब के उद्योग-पतियों को बहुत कम सुविधाएं दी गई हैं···

श्री संजीवय्या : यदि यह प्रश्न है तो मैं यह अवश्य कहूंगा कि इन लघु-उद्योगों के सम्बन्ध में पंजाब अधिक आगे है।

श्री कंडप्पन : ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा दिये गये तथाकथित प्रोत्साहन के बावजूद भी ग्रामीण-क्षेत्रों में पहले के मुकाबिले आय बहुत कम है। सरकार द्वारा अपनाई गई प्रोत्साहन की नीति के परिणाम-स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये गये हैं?

श्री संजीवय्या : शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की हैं। इसके अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग.....

श्री कंडप्पन : मैं इस प्रकार के गोलमाल उत्तर नहीं चाहता। इस नीति के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये उद्योगों के मैं ठोस उदाहरण चाहता हूं।

श्री संजीवय्या : अभी मेरे पास सूची नहीं है। मैं समझता हूं हमने लगभग 45 औद्योगिक बस्तियां स्थापित की हैं। मैं सूची को सभा-पटल पर रख सकता हूँ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

\+

*812. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरी निगम, रांची के कौन-कौन से कारखाने अपने उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति से पीछे रह गये हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) 1965 में कुल कितने मूल्य का उत्पादन हुआ तथा 1966 में कुल कितने मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख). हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के तीन संयंत्रों में से फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट लक्ष्य से पीछे चल रहा है। इसके प्रमुख कारण (1) देश में इससे मिलते जुलते इस्पात खण्डों और निर्मित इस्पात के ढांचों का न मिलना तथा (2) जमीन के कम भार सहन कर सकने के कारण नींव के खम्भे गाड़ने का काम करने की आवश्यकता है।

(ग) उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार है।

परियोजना	मूल्य 1965-66 में	अनुमानित मूल्य 1966-67 में
	(लाख रु० में)	
1. हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	293	748
2. फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट का संयंत्र	67.98	324.22
3. हैवी मशीन टूल्स प्लांट	कुछ नहीं	21.50

Shri Madhu Limaye : I would like to know which particular company was expected to manufacture steel structural and why has it not supplied the material in time ? Are Government Steel factories also to blame for that ?

श्री संजीवय्या : इन ढांचों को भेजने के ठेके सात फर्मों को दिये गये थे। आवश्यक होने पर मैं उन फर्मों के नाम भी पढ़ सकता हूँ।

Shri Madhu Limaye: Wherefrom were these structurals expected ?

श्री संजीवय्या : रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डास लिमिटेड, बम्बई ; ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेस्सोप कंस्ट्रक्शन कम्पनी, कलकत्ता ; ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता ; बर्न एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ; ए० एण्ड जे० मेन कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता ; जेस्सोप एण्ड कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता ; ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड–फर्मों को इस्पात के ढांचे भेजने के ठेके दिये गये थे, किन्तु वे उपयुक्त इस्पात के अभाव में ऐसा न कर सके।

Shri Madhu Limaye: Why do these factories not get the matching steel here ?

Mr. Speaker: Please put another question now.

Shri Madhu Limaye: It is a part the first question because it disposes of one of my supplementaries. If he answers my first question fully, I shall ask another question.

श्री संजीवय्या : ऐसी आशा थी कि हमारे इस्पात के कारखाने अपेक्षित मात्रा में इस्पात दे सकेंगे और इस दिशा में आवश्यक कदम भी उठाये गये। यह सब होते हुए भी, हम इस्पात की अपेक्षित मात्रा नहीं प्राप्त कर सके तथा कुछ इस्पात आयात करना पड़ा।

Shri Madhu Limaye: So the Government have admitted their fault. They are forced to go into the depth and lay the foundation. I would like to know whether it is a fact that a report, to the effect that the land was not suitable for the Foundry Forge Project, was received by the Government and some big people neglected the report and got this land purchased by the Government ? Now it is known that the land is not suitable for the big project. Will Hon. Minister be pleased to give complete details of the amount that was misappropriated in this connection.

श्री संजीवय्या : 1957 में बिहार सरकार ने उन रूसी अधिकारियों, जिन्होंने यहां आकर भूमि का सर्वेक्षण किया, को एक प्रतिवेदन दिया। तीन परियोजनाओं में से, फाउन्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट रूस के सहयोग से तथा हैवी मशीन टूल भी चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से चलने की व्यवस्था है। चैकोस्लोवाकिया के अधिकारी पूर्व-सर्वेक्षण के अभिलेख से सन्तुष्ट नहीं हुये, अतः उन्होंने स्वयं सर्वेक्षण करना चाहा। 1958 में जब होंने सर्वेक्षण करने पर यह अनुभव किया कि भूमि में भार वहन करने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी, अतः वे चाहते थे कि कोई विशेषज्ञ इसकी जांच करे। एक विश्वविख्यात विशेषज्ञ, जो चैकोस्लोवाकिया के ही हैं, प्रो० माइसिलवेक (Mysilvec) से इसका परीक्षण करने का अनुरोध किया गया तथा परीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि साधारण बुनियाद से काम नहीं चलेगा, अपितु भूमि-प्रविष्ट-खम्भों पर बुनियाद (pile foundation) रखना आवश्यक होगा, क्योंकि यह भूमि भार-वहन नहीं कर सकेगी। डा० के० एल० राव, जो उस समय केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के सदस्य थे, की भी यही राय थी।

Shri Madhu Limaye : My question has not been answered. Why was the land chosen, when the Ministers and foreign experts held the view that the land was not suitable ? Was some undue pressure exercised in this connection ?

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई अनुचित दबाव डाला गया ?

श्री संजीवय्या : मुझे ऐसे किसी दबाव की जानकारी नहीं है ।

श्री रंगा : राजनीतिक दबाव ।

Shri Bagri : When the land was not suitable for the project, why was it chosen ? The Hon. Minister has stated that there was no pressure, I would like to know why was this land chosen then ?

श्री संजीवय्या : मैंने आरंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि रूसियों की दृष्टि में प्रतिवेदन सन्तोषजनक था, किन्तु चैकोस्लोवाकिया वालों, जिनके सहयोग से इस परियोजना को चलाया जाना था, ने इसका परीक्षण किया और इसमें कुछ कमी पाई । अतः उन्होंने निरीक्षण द्वारा विशेषज्ञों की राय ली ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The Hon. Minister has given the reasons for the low output of the Foundry Forge but why has he forgotten the Government Servants in Bihar retired or otherwise, who were posted over there, and who were responsible for setting the forests on fire, raising the quarrels amongst labourers and were again promoted on high salaries, and who have ruined this project ? What steps have the Government taken to punish these Government Servants ?

श्री संजीवय्या : सभी अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारियों की निन्दा करना उचित नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : बिहार में और देश भर में यह बात सभी जानते हैं ।

श्री संजीवय्या : मैंने कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों की निन्दा करना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी हो सकते हैं । मैं नहीं समझता कि किसी अधिकारी विशेष के कारण इस योजना को स्थगित करना पड़ा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि पिछले दिनों योजना-मंत्री जिनके साथ कि इस निगम के उच्च अधिकारी भी थे, की रूस यात्रा के दौरान इस परियोजना की तीव्र आलोचना हुई और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में रूस सरकार ने कोई निश्चित सुझाव दिये ?

श्री संजीवय्या : मुझे इस सम्बन्ध में न तो कोई प्रतिवेदन ही मिला और न मुझे इन परियोजनाओं की कमियों के बारे में व्यक्तिगत रूप से बताया गया कि योजना मंत्री की रूसी विशेषज्ञों के साथ किन विषयों पर बात चीत हुई ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : आश्चर्य की बात है ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि रूसी लोग एच० ई० सी० (HEC) का उपयोग किये जाने पर असन्तुष्ट हैं और इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों का एक दल यह मालूम करने के लिये कि इस परियोजना का कितना अच्छा उपयोग किया जा सकता है, रूस गया तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री संजीवय्या : जी हां; इस विषय में विचार हो रहा है कि हम इसका उपयोग कितने अच्छे ढंग से कर सकते हैं ? इन परियोजनाओं को सामान भेजने के लिये जो आदेश दिये गये थे वे पर्याप्त नहीं थे और इसीलिये इस बात पर विचार हो रहा है कि क्या रांची के कारखाने से बोकारो जैसे कारखानों के लिये आवश्यक मशीनें प्राप्त हो सकती हैं ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि हो सकता है कि कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ी की हो; क्या सरकार को ऐसे कुछ अधिकारियों का पता है तथा गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री संजीवय्या : यह प्रश्न सर्वथा भिन्न है; इस पर पहिले भी प्रकाश डाला गया था ।

कपड़े के दाम

+

*813. **श्री बागड़ी** :
श्री मौर्य :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 6 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1529 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता में बनी हुई समिति ने कपड़े के दामों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उप-पत्तियां क्या हैं और उन-पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) . एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता में एक समिति ने, कपड़े की नियंत्रित किस्मों के सम्बन्ध में, मिल से चलते समय की कीमत पर 20 प्रतिशत के व्यापारिक लाभ को, थोक तथा खुदरा व्यापारियों के मध्य सांविधिक विभाजन के प्रश्न पर विचार किया । समिति ने अब अपना प्रतिवेदन दे दिया है ।

समिति ने अनुभव किया कि सांविधिक विभाजन करना व्यावहारिक नहीं है। उसका यह विचार था कि व्यापार के विभिन्न क्षेत्र, विशेषतः थोक तथा क्रियान्वयन समितियां, खुदरा

व्यापारियों को 10 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने का प्रयत्न करें। अतः समिति ने क्रियान्वयन समितियों की शीघ्र स्थापना और समितियों के कार्य के दो महीने बाद मामले के पुनर्विचार की सिफारिश की।

क्रियान्वयन समितियों ने पहिले ही सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। सरैया समिति की सिफारिशों के आधार पर उनके कार्य की समीक्षा की जा रही है और शीघ्र ही मामले पर पुनर्विचार किया जायगा।

Shri Bagri : Mr. Speaker, it appears from the statement that the retailers will get 10% but as to how will the margin that is there between 20% and 10% be apportioned, is not mentioned in the statement. The Hon. Minister may please throw light on this.

Shri Shafi Qureshi : The Hon. Member knows that previously there was a difference of 18% between Mill price and the retail price which used to go to the intermediary whole-salers or retailers. The Government thought over this and increased it by 2% and every effort has been made to see that the retailer gets 10%.

Shri Bagri : My question has not been answered. Where has 10% that is there between 20% and 10% gone ? When the price of the cloth has not been increased, where has the 10% gone ?

Shri Shafi Qureshi : This 20% is regularly apportioned amongst whole-salers, semi-whole-salers and retailers.

Shri Bagri : Formerly it was 20%, now it is 10% and thus there is a saving of 10% its a result price of cloth should have come down. I would like to know whether there is fall in prices or the profit has been increased on the contrary ?

वाणिज्य-मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : प्रश्न मिल से चलते समय की कपड़े की कीमत तथा खुदरे मूल्य में 20 प्रतिशत के अन्तर का है। मेरे माननीय सहयोगी ने जो बयान सभा पटल पर रखा उसमें खुदरे व्यापारियों के लिये 10 प्रतिशत निम्नतम दिखाया गया है। समिति इस विषय में सहमत नहीं हो सकी कि क्या अर्ध-थोक व्यापारियों और विभाजकों के बीच संतुलित, स्थानीय बंटवारा हो सकना संभव है। प्रश्न अभी भी विचाराधीन है। अभी तक इस अन्तर की प्रतिशत राशि को सम्बन्धित पक्षों में बांटना सम्भव नहीं हो पाया।

Shri Bagri : This is my first question.

Mr. Speaker : Three questions have been disposed of and the Hon. Member says that it is his first question.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या मंत्री महोदय को पता है कि भूतपूर्व वित्त-मंत्री, जिन्होंने मध्यम दर्जे के कपड़े के उत्पादन कर में कुछ-कुछ रियायतें घोषित करने की कृपा की थी, इस्तीफा देने के बाद ही एक और समिति ने अनेक किस्म के सूती कपड़ों के उत्पादन मूल्यों में वृद्धि की सिफारिश की थी जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता को उसी किस्म के कपड़े के लिये

अधिक मूल्य चुकाना पड़ेगा और सरकारी कोष को भी दी गई रियायतों की हानि उठानी पड़ी ? मुझे यह 'सुरैया समिति' 'गो-हत्या पर कसाई-आयोग' से भी बदतर मालूम होती है। इन्होंने खुदरे-मूल्य की कहां तक सिफारिश की ?

श्री मनुभाई शाह : यह सर्वथा निराधार है, क्योंकि भार बढ़ाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न यह है कि 20 प्रतिशत के अन्तर को विभाजकों के चार पक्षों यानी थोक व्यापारियों, अर्ध-थोक व्यापारियों, विभाजकों और खुदरे व्यापारियों में किस प्रकार बांटा जाये। (**व्यवधान**) अतः भार बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय सदस्य को गलत सूचना मिली है क्योंकि यह 20% पिछले 18 महीनों से चला आ रहा है। अतः यह कहना कि हम मूल्य स्थिर रखेंगे, वित्त-मंत्री के वक्तव्य के विरुद्ध नहीं है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मेरा प्रश्न इस 20 प्रतिशत के बाहर था। मैं विशेषतया यह जानना चाहता था कि क्या एक मंत्री सूती कपड़े पर कुछ रियायतें घोषित करते हैं और दूसरे मंत्री के अधीन दूसरी समिति समान मूल्य वृद्धि की सिफारिश करती है, और इसी प्रश्न पर मंत्री महोदय मौन हैं ?

श्री मनुभाई शाह : प्रश्न यह है कि समिति गुणक-परिकलन (calculation of multiplier) के लिए नहीं थी। सभा को ज्ञात है कि गुणक (Multiplier) के लिए पिछले ढाई सालों में उन्होंने तकनीकी तथा वैज्ञानिक आधार पर कच्चे माल, वेतन दरों आदि पर विचार किया। इसका 20% से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस समिति का काम यह था कि यह 20% किस प्रकार विभाजकों की विभिन्न श्रेणियों में खुदरे व्यापार के स्तर पर उचित ढंग से बांटी जाये।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : अध्यक्ष महोदय, मेरी सहायता कीजिए। मेरे प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं आया। प्रश्न साधारण है : एक समय में एक मंत्री महोदय रियायत की घोषणा करते हैं और दूसरे मंत्री गुणक का मूल्य बढ़ाते हैं और.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री बनर्जी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कपड़े की सभी किस्मों यानी सुपर फाइन, फाइन तथा मीडियम कपड़े के मूल्य दशहरा, दिवाली और ईद के त्यौहारों पर कुछ बढ़ाये गये हैं या बहुत बढ़ाये गये हैं तथा क्योंकि अब दशहरा आने ही वाला है, क्या सरकार ने मूल्य स्थिर रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : पहली बात यह है कि कपड़े की नियंत्रित किस्मों में कोई मूल्य-वृद्धि नहीं हुई है। सरकार ने धोती, साड़ी, पौपलिन, लट्ठा तथा ड्रिल जैसे कपड़ों की बड़े पैमाने पर खपत की जिम्मेवारी ली है। हम अनियंत्रित किस्मों के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। इस दिशा में हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है कि दशहरा और दिवाली के लिए बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा दूसरे उन केन्द्रों को जो उत्पादन केन्द्रों से दूर हैं कपड़े के पर्याप्त स्टाक भेजे जायें। कपड़ा

पर्याप्त मात्रा में जमा है और हम राज्यों के मुख्य-मंत्रियों से सम्पर्क बनाये हुए हैं कि यदि कहीं कपड़े की कमी हो तो वहां कपड़ा फौरन भेजा जाए ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, उन्होंने मेरे प्रश्न विशेष का उत्तर नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

Railway line from Amritsar to Lahore

*815. **Shri Bibhuti Mishra**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the railway line from Amritsar to Lahore in Pakistan has not yet been opened to traffic ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The reluctance of Pakistan to normalise relations with India is holding up the re-establishment of the interrupted rail links between the two countries.

Shri Bibhuti Mishra : How many railway employees and railway coaches were taken away by Pakistanis and how many of them have so far been returned by them ?

Dr. Ram Subhag Singh : Despite Tashkent declaration, not a single coach has so far been returned by Pakistan ; only railway employees have come back. Our four engines (three of metre gauge and one of broad gauge), 30 passenger coaches (6 of metre-gauge and 24 of broad-gauge) have also been detained by them.

Shri Bibhuti Mishra : Which railway lines connect India with East and West Pakistan and what are the difficulties which are being experienced in regard to their operation ?

Dr. Ram Subhag Singh : Actually three zones are linked with Pakistan. Eastern Railway is linked at two places and here the trains were running from Ranaghat to Darsana of Pakistan and from Bongaon to Benapol of Pakistan. On Northern Railway, trains were running from Amritsar to Lahore and from Munbao to Khokhropar in Pakistan. North East Frontier Railway is connected at five places viz. from Maishasan to Kulaura, from Gee Taldah to Lal Maniharghat, from Haldibari to Parvatipur, from Chaugrabandh to Boorimari and from Radhikapur to Parvatipur.

Shri Onkar Lal Berwa : Have any people, engines, coaches etc. of Pakistan been detained by us and if so the number thereof and what Government intend to do in regard to their release ?

Dr: Ram Subhag Singh : We have got three broad-gauge engines and nine broad-gauge coaches of Pakistan.

Shri Sheo Narain : Will these coaches be returned when talks between the Railway Ministers of both the countries are held ?

Dr. Ram Subhag Singh : A Ministerial delegation consisting of three persons went there under the leadership of the Minister of Foreign Affairs but no agreement could be reached.

Shri Gulshan : Before introducing train service between Amritsar and Lahore, have Government taken into this consideration that smugglers and spies will enter India through this route and if so, the arrangements made to check them ?

Dr. Ram Subhag Singh : This is looked after by the Ministry of Home Affairs.

Shri Yashpal Singh : When it has been decided under the Tashkent Declaration that both the countries should try to come close to each other, why a direct train service upto Rawalpindi is not introduced ?

कृषिजन्य वस्तुओं का निर्यात

+

*816. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन में आमतौर पर कमी हो जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 1965 में कृषिजन्य वस्तुओं का निर्यात कम हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो कृषि उत्पादन में कमी न आने देने तथा कृषिजन्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या अवमूल्यन के फलस्वरूप कृषि को बढ़ावा देने तथा निर्यात को बढ़ाने में सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) 1965 में कृषिगत वस्तुओं का निर्यात 272.3 करोड़ रु० मूल्य का हुआ जबकि 1964 में यह निर्यात 303.8 करोड़ रु० का हुआ था। 1965-66 में हुए इन वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु पिछले वर्ष देश में मानसून के सामान्यत: न आने और सूखा पड़ने के कारण वे काफी कम थे।

(ख) उर्वरकों तथा उन्नत बीजों के अधिक उपयोग, पौध संरक्षण उपायों और सिंचाई की बढ़िया सुविधाओं आदि से श्रम-प्रधान और भूप्रधान खेती के द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। उत्पादन के बढ़ने के साथ निर्यात के भी बढ़ने की आशा है।

(ग) जी, हां। यदि कृषि, बागान, खनिज और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन को गहन किया जाय तो निर्यात बढ़ सकता है।

श्री रा० बरुआ : खाद्य-फसलों पर लगाये गये विभिन्न प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए क्या नकदी-फसलों के उत्पादन में कोई वृद्धि होने की सम्भावना है और क्या सरकार इनमें सन्तु-

लन बनाये रखने की बात सोच रही है जिससे नकदी फसलों की अधिक खेती करने से खाद्य-फसलों पर कोई प्रभाव न पड़े ?

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता है । किसी भी अवस्था में सरकार विभिन्न प्रकार की फसलों के बीच सदा सन्तुलन बनाये रखती है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत खाद्य-क्षेत्र में अभी आत्म-निर्भर नहीं हुआ है, क्या खाद्य-वस्तुओं के निर्यात को घटाकर खाद्य-उत्पादन की ओर सारा ध्यान देना वांछनीय है ?

श्री मनुभाई शाह : जितना खाद्यान्न का उत्पादन आवश्यक है, उतना ही खाद्य-पदार्थों का निर्यात भी आवश्यक है । राष्ट्रीय नीति यह है कि चौथी योजना में कृषि की सभी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाये ।

श्री दाजी : अवमूल्यन के फलस्वरूप कृषि-वस्तुओं के निर्यात की सम्भावना में कितनी अनुमानित वृद्धि हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : इस समय कोई पूर्वानुमान लगाना तो बहुत कठिन है, परन्तु हमने अभी 5700 करोड़ रुपये का वही पुराना लक्ष्य रखा है जिसका अवमूल्यन के फलस्वरूप परिवर्तित मूल्य 8,030 करोड़ रुपये है । हम आशा करते हैं कि हम पुनः निर्धारण तथा कृषि और अन्य क्षेत्रों में भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप इससे भी अधिक निर्यात कर सकेंगे ।

श्री स्वैल : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि अवमूल्यन के पश्चात् कृषि-वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावना है । पश्चिमी बंगाल तथा आसाम जैसे कमी वाले क्षेत्रों में कमी का एक कारण यह है कि वहां पर अधिकाधिक भूमि में नकदी फसलें अथवा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं उगाई जाती हैं । इस संदर्भ में वह यह कैसे आशा करते हैं कि खाद्य-फसलों के बदले में नकदी फसलों के लिए भूमि में वृद्धि किये बिना निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : विस्तृत कृषि की बजाय सघन खेती द्वारा ।

कच्चे माल का भण्डार (बैंक)

\+

*818. **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट : **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात उद्योगों की आवश्यकता की अत्यावश्यक औद्योगिक सामग्री के भण्डार बनाने के लिए एक कच्चे माल के बैंक की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का अन्तिम रूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). निर्यात उद्योगों के लिए अत्यावश्यक औद्योगिक सामग्री के भण्डार बनाने के लिए एक कच्चे माल के बैंक की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

श्री श्रीनारायण दास : इस प्रयोजन के लिये वित्तीय आवश्यकताओं का क्या कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : बहुत अधिक वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। हम पहले निर्यात उद्योगों के लिये 8 करोड़ रुपये का भण्डार स्थापित कर रहे हैं ?

श्री श्रीनारायण दास : इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : शीघ्र। सभी निगमों को सचेत कर दिया गया है। एम० एम० टी० सी० तथा एस० टी० सी० कच्चे माल की डिविजनें खोल रहे हैं। कच्चे माल की एक सूची तैयार कर ली गई है। निर्यात-उद्योगों के लिये देशीय कच्चे माल का आवंटन करने का एक हरा फार्म तैयार कर लिया गया है।

श्री काशी राम गुप्त : क्या इस प्रयोजन के लिये सारी पूंजी सरकार द्वारा दी जायेगी अथवा अन्य अभिकरण भी इसके लिये पूंजी देंगे ?

श्री मनुभाई शाह : कच्चे माल के इस भण्डार की देख-रेख सरकार द्वारा की जायेगी और सारी पूंजी सरकार द्वारा ही लगाई जायेगी।

श्रीमती सावित्री निगम : विभिन्न उद्योगों को इस कच्चे माल का उचित ढंग से वितरण कैसे किया जायेगा क्योंकि यह वितरण अभिकरण ही है जो उद्योगों विशेषकर छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये काफी कमी पैदा कर देता है ?

श्री मनुभाई शाह : कच्चे माल का वितरण निर्यात की मात्रा के आधार पर किया जायेगा। इस भण्डार से सामान्य वितरण नहीं किया जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : महोदय, सरकार अन्य देशों से विचार प्राप्त करने में बहुत निपुण है। यह विचार कहां से लिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : भारत से।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि उस देश में कच्चे माल के भण्डारीकरण की व्यवस्था इतनी सफल नहीं रही है क्योंकि पहले इसके कि उसका वितरण किया जाता, वह सड़ने लग गया ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में माननीय सदस्य ठीक ही कहते हैं। यहां पर भण्डार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। भण्डारीकरण का वास्तव में अर्थ यह है कि राष्ट्र की सारी

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कच्चा माल एक वर्ष, दो वर्ष अथवा तीन वर्ष तक रखा जाये। परन्तु हमने तो निर्यातकों की सहायता करने के लिये केवल कुछ मात्रा में अत्यावश्यक कच्चे माल को एक केन्द्रीय स्थान पर रखना है।

श्री कृ० चं० पंत : यह भण्डारीकरण किस आधार पर किया जा रहा है, क्या यह उद्योग की एक वर्ष अथवा छः महीने की आवश्यकताओं के लिये होगा और क्या भण्डारीकरण के लिये पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य को भण्डारीकरण की क्षमता के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्यात संवर्धन के हेतु कुछ वस्तुओं का भण्डार रखने के लिये दो निगमों को 8 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

श्रीमती विमला देशमुख : इस कार्य को करने के लिये संगठन सम्बन्धी ढांचा क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : राज्य व्यापार निगम तथा एम० एम० टी० सी०।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : किन उद्योगपतियों को क्षमता से अधिक मात्रा में कच्चा माल लेने की सुविधा होगी ?

श्री मनुभाई शाह : क्षमता से अधिक मात्रा में कच्चा माल लेने के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई।

श्री दाजी : निर्यात-संवर्धन के सन्देहात्मक पूर्ववृतान्त को ध्यान में रखते हुये क्या यह बैंक वास्तविक निर्यात अथवा प्रत्याशित निर्यात के आधार पर कच्चा माल दिया करेगा ?

श्री मनुभाई शाह : अधिकांशतः वास्तविक निर्यात के आधार पर।

तारांकित प्रश्न संख्या 832 और 833 के बारे में
Re: Starred Question Nos. 832 and 833

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न-काल समाप्त होता है। अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : Mr. Speaker, I have made a request in connection with Question No. 832.

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय प्रार्थना करते हैं तो मैं निश्चय ही इसकी अनुमति दे दूंगा।

डा० राम सुभग सिंह : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं मजबूर हूं। माननीय सदस्य की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न-काल के पश्चात केवल मंत्री महोदय ही अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं कि वह प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : If the reply is ready then he should have no objection.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : महोदय, आप प्रश्न संख्या 833 के बारे में नहीं पूछ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री उत्तर देना चाहते हैं तो मैं अनुमति दे दूंगा ।

लोहा तथा इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल आपत्ति का प्रश्न ही नहीं है । उन्हें इसके लिये प्रार्थना करनी होगी, तभी मैं उसे उत्तर देने की अनुमति दूंगा । अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम यह है कि जब किसी प्रश्न को अल्प सूचना प्रश्न समझा जाता है—क्योंकि आप समझते हैं कि यह इतना महत्व-पूर्ण है कि इसका उत्तर उसी दिन दिया जाये जिस दिन के लिये इसे सूची में शामिल किया गया है–तो इसे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं कि इसे पहली प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिये, यदि यह इतना महत्वपूर्ण है तो इसे वह प्राथमिकता दी जानी चाहिये । जब मंत्री महोदय ने इसे प्राथ-मिकता नहीं दी है तो मैं क्या कर सकता हूं ।

Shri Onkar Lal Berwa : They are charging double fare. Even then this question has no importance. The area of India is going on decreasing and railway fares are going on doubling. For how long the people of Rajasthan will bear this injustice ?

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या आपने मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : आपने मंत्री महोदय से प्रश्न संख्या 832 के बारे में तो पूछा है परन्तु क्या आपने उनसे प्रश्न संख्या 833 के बारे में भी पूछा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 833 के बारे में वह कहते हैं कि वह प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं । अब अल्प सूचना प्रश्न ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कलमस्सेरी (केरल)

अ० सू० प्र० संख्या 22. श्री मणियंगाडन : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से विद्यार्थियों को केरल में कलमस्सेरी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कक्षाओं में आने से रोक दिया गया है और यदि हां, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं;

(ख) क्या विद्यार्थियों को छात्रावास से निकाल दिया गया है और यदि हां, तो इस प्रकार कितने विद्यार्थी निकाले गये हैं और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह संस्था अब बन्द है; और

(घ) संस्था में सामान्य स्थिति पुनः उन्पन्न करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क), (ख), (ग) और (घ). औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र कलमस्सेरी के लगभग 230 प्रशिक्षणार्थी किसी प्रकार की मांग प्रस्तुत किये बगैर अथवा कोई शिकायत बताये बिना, दिनांक 13 अगस्त, 1966 को गैर-हाजिर रहे। 85 प्रशिक्षणार्थियों को, जिनमें 3 होस्टल के छात्र भी शामिल हैं, अपनी गैरहाजिरी का संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ रहने के कारण मुअत्तिल कर दिया गया था। होस्टल में रहने वाले 3 छात्रों को निकाल दिया गया। यह कार्यवाही अनुशासन बनाये रखने के लिए की गई थी। मुअत्तिल या निकाले गये सभी 85 प्रशिक्षणार्थियों को जिनमें 3 होस्टल के छात्र भी शामिल हैं, प्रशिक्षण केन्द्र में पुनः भर्ती कर लिया गया है। दिनांक 22 अगस्त, 1966 से प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य सामान्य रूप से चल रहा है।

श्री मणियंगाडन : उन विद्यार्थियों को निलम्बित करने और उनको होस्टल से निकालने का क्या कारण था ?

श्री शाहनवाज खां : अनुशासनहीनता, कक्षाओं में उपस्थित होने और सामान्यतः आदेशों को पालन करने से इन्कार करना।

श्री मणियंगाडन : वे उस समारोह में उपस्थित नहीं हुए जहां पर कि एक प्रशासनिक कक्ष का उद्घाटन किया जा रहा था। क्या यह अनुशासनहीनता का कार्य है ? विद्यार्थियों के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने कक्षाओं में उपस्थित होने से इन्कार कर दिया। किन आधार पर उन्हें पुनः दाखिल किया गया। यदि उनको यह दण्ड दिया गया था तो इसको वापस क्यों लिया गया।

श्री शाहनवाज खां : समारोह संस्था के स्थान पर आयोजित किया गया था और कुछ लोगों को उद्घाटन सत्र में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया था। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किये गये विभिन्न मॉडलों को भी प्रदर्शन के लिए रखा गया था। उनका इस समारोह में भाग लेने से इन्कार करना निश्चय ही एक अनुशासनहीनता और असहयोग का कार्य था। उनको निलम्बित किया गया था परन्तु जब उन्होंने अपनी गलती को समझा और खेद व्यक्त किया तो हमने उन्हें क्षमा कर दिया।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that before taking recourse to an act of indiscipline they had stated their demands to the higher authorities there, in writing? Is it not a fact that they had to resort to that action because their demands were not accepted? What are their demands ?

Shri Shah Nawaz Khan : Even if the demands have been given in writing, there is no reason why the orders should not be obeyed; but in this particular case they had not given any demand in writing.

Shrimati Ram Dulari Sinha: Is it not a fact that since the imposition of President's rule in Kerala, the atmosphere there is surcharged with workers resorting to strikes, industrialists resorting to lockouts and students resorting to acts of indiscipline ; if, so, whether the Government have tried to go into its causes and if so, whether any solution is being evolved to put an end to this problem ?

Shri Shah Nawaz Khan: It is a wide question. I can only say that no such atmosphere has been prevailing there.

केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग में एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की पदावनति

अ० सू० प्र० संख्या 23 **श्री नम्बियार :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री शिंकरे :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राजाराम :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री बीरेन दत्त :
श्री दशरथ देब :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री प्र० के० देव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के सात एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की, जो 8 से 13 वर्ष तक सेवा कर चुके हैं और भारत के विभिन्न भागों तथा अन्दमान में कार्य कर रहे हैं; हाल में सहायक इंजीनियरों के रूप में पदावनति कर दी गई है;

(ख) क्या इन पदावनतियों के आदेश सीधे भर्ती किये गये प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को पद उपलब्ध करने के लिए दिये गये;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों पर, अर्थात्, उनकी पदोन्नति से पहले 5 से 8 वर्ष तक की सेवा होनी चाहिए, विचार किया गया था; और

(घ) क्या इसी प्रयोजन के लिए और भी बहुत-सी पदावनतियां की जायेंगी ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां । यह ठीक है कि सात स्थानापन्न सहायक इंजीनियर जो कि सितम्बर, 1965 में या उसके बाद अस्थाई रूप से पदोन्नत हुए थे, सहायक इंजीनियरों के रूप में प्रत्यावर्तित हो गये हैं ।

(ख) सम्बन्धित सात अधिकारियों के प्रत्यावर्तन का आदेश निम्नांकित कारणों से दिया गया था;

(i) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये 3 अधिकारी अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि को पूरा करके मूल विभाग में वापस आ गये ।

(ii) 2 अधिकारी छुट्टी से वापस आ गये ।

(iii) कार्य के पूरा हो जाने पर एक प्रभाग (डिवीजन) बन्द कर दिया गया जिससे एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर अधिक (सरप्लस) हो गया; तथा

(iv) एक सहायक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रथम श्रेणी ने अपने ग्रेड में निर्धारित सेवा पूरी कर ली तथा उसे पदोन्नत करना होगा ।

अतएव एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए जगह करने को केवल एक अधिकारी प्रत्यावर्तित हुआ है ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर गोविन्द रेड्डी स्टैडी टीम ने सिफारिश की थी कि प्रथम श्रेणी के सहायक एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नत होने के लिए पात्रता की अवधि जो कि पहले पांच वर्ष थी तथा जिसे बाद में तीन वर्ष के लिए छूट दे दी गई थी, उसे पुनः पांच वर्ष निर्धारित कर दिया जाय । इसी प्रकार टीम ने यह सिफारिश की थी कि श्रेणी दो के सहायक इंजीनियरों को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नत होने के लिए आठ वर्ष की पात्रता की पहली अवधि जिसे कि बाद में पांच वर्ष की छूट दे दी गई थी, उसे भी पुनः पहले ही की आठ वर्ष की अवधि कर दिया जाय । सरकार के द्वारा यह सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, किन्तु योग्यता प्राप्त अधिकारियों की कमी के कारण, प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी दोनों में, ये सिफारिशें केवल धीरे-धीरे कार्यान्वित की जायेंगी ।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना को विभाग के द्वारा समय-समय पर लिए गये निर्माण तथा अनुरक्षण के कार्यभार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है । यदि सिविल निर्माण के खर्चे में बचत की आवश्यकता के फलस्वरूप कार्यभार कम होता है तो स्थापना को उसी के अनुसार समायोजित (एडजस्टेड) किया जाता है ।

श्री नम्बियार : माननीय उपमंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि 6 पद उन व्यक्तियों को दिये गये थे जो दूसरे विभागों से या अवकाश समाप्त करके लौटे थे । क्या इन व्यक्तियों के लिए अन्य रिक्त स्थान भी उपलब्ध थे परन्तु जिनको इसलिए नहीं भरा गया था कि वे प्रथम श्रेणी के उन अधिकारियों के लिए रक्षित थे जिन्होंने उस समय तक 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी ?

श्री भगवती : ऐसी बात नहीं है । वास्तव में एक बड़ी संख्या में सहायक इंजीनियरों को पदोन्नति दी गई है अर्थात्, स्वीकार्य कोटा के अतिरिक्त श्रेणी दो, एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के रूप में पदोन्नति दी गई है । 250 सहायक इंजीनियरों को एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के रूप में अस्थायी रूप में पदोन्नत किया गया है जबकि श्रेणी एक की ओर से 68 को ही पदोन्नत किया गया है यद्यपि निर्धारित कोटा के अनुसार अधिक पदों के लिए हकदार हैं ।

श्री नम्बियार : अध्ययन दल की सिफारिश बहुत स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के लिए सहायक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के रूप में 5 वर्ष की सेवा और सहायक इंजीनियर के रूप में 8 वर्ष की पात्रता की अवधि को यथा-शीघ्र पुनः रखा जाना चाहिए। यह सिफारिश संख्या 20 है, जिसे माननीय मंत्री कहते हैं स्वीकार कर लिया गया है। यदि ऐसा है तो इन प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों को एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के रूप में पदोन्नत करने से पूर्व सेवा के पांच वर्ष पूरा करने की अनुमति देने के मार्ग में क्या बाधा है ?

वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिसे कि अनुभवहीन व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता।

श्री भगवती : सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। परन्तु माननीय सदस्य कृपया इस बात पर ध्यान दें कि उदारता की कसौटी श्रेणी एक और श्रेणी दो, दोनों के अधिकारियों पर लागू होती है। इस उदार कसौटी को उन अधिकारियों पर लागू किया जाता था जिनको एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया जाता था। अब जबकि हम सामान्य कसौटी लागू कर रहे हैं, हो सकता है कुछ समय के बाद यह दोनों श्रेणियों के अधिकारियों पर लागू की जाय। अतः श्रेणी एक या श्रेणी दो के किसी भी अधिकारी को हानि नहीं पहुंचेगी।

श्री नम्बियार : पदावनत एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को अब नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों के रूप में उन्हें पहले ही पदोन्नत कर दिया गया है और वे उन पदों पर हैं, परन्तु अब उन्हें उन पदों को छोड़ना होगा।

श्री भगवती : वह तो है ही। ऐसा इसलिए है कि उनको भी उदार कसौटी की सुविधा दी गई थी। जब उनको पदोन्नत किया गया था तो उनकी सेवा के आठ वर्ष पूरे नहीं हुए थे। यदि हमने सामान्य कसौटी का पालन किया होता तो पदोन्नति से पहले उनको आठ वर्ष पूरे करने पड़ते। सामान्य कसौटी के अनुसार श्रेणी दो के अधिकारियों को सेवा के आठ वर्ष पूरे करने पड़ते और श्रेणी एक के अधिकारियों को सेवा के पांच वर्ष।

Shri Yashpal Singh : All the world over good work is credited by giving promotions. The engineers who did marvelous work have been denoted. May I know the manner in which a sense of security is sought to be instilled amongst the engineers in such circumstances that they will be allowed to stick to their posts and that their chances of promotion will not be hampered ?

श्री भगवती : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है। उनके विरुद्ध हमें कुछ नहीं कहना है। परन्तु उनकी पदावनति आवश्यक हो गई है क्योंकि इस समय कोई रिक्त स्थान नहीं है।

जैसा कि आप जानते हैं पिछले 10 वर्षों में इस विभाग में काम काफी बढ़ गया था।

इसके अतिरिक्त अन्य विभागों ने भी उनके अपने निर्माण कार्य के लिये लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की सेवाएं अर्जित की थीं। परन्तु अब काम घट गया है। 1966-67 के बजट में इस मंत्रालय के नये निर्माण कार्य के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। फिर, बजट की राशि में लगभग 50 लाख रु० की कटौती की गई है। अतः इस वर्ष काम घट गया है, और मैं नहीं समझता कि बाद में क्या स्थिति होगी। अब, हमारे पास प्रतिरक्षा मंत्रालय का कुछ काम है, अतः हम फालतू कर्मचारियों को उसमें लगा रहे हैं। परन्तु यदि हमें काम नहीं मिलता तो निश्चय ही स्थिति का पुनरीक्षण करना होगा।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अन्तर्गत अनेक परियोजनाएं चालू हैं। क्या इन इंजीनियरों को उन्हीं पदों पर अन्य परियोजनाओं में नहीं लगाया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो उन्होंने कहा है।

श्री भगवती : जब कोई अवसर होता है तो हम निश्चय ही उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारी सहानुभूति है और हम यथासंभव उनको समायोजन करना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सही नहीं है कि इन सात एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को, जिन्हें पदावनत किया जा रहा है, लगभग 250 अधिकारियों की छानबीन करने के बाद केवल आठ या दस मास पूर्व नियुक्त किया गया था; जब इन सात व्यक्तियों को सक्षमता और योग्यता और संतोषजनक सेवा के आधार पर चुना गया था ? यदि हां, तो उस समय इस बात का क्यों अनुमान नहीं लगाया गया कि इस प्रकार की आकस्मिकता, जिसका माननीय मंत्री ने अब उल्लेख किया है, बाद में हो सकती थी और इन व्यक्तियों की छानबीन और चयन क्यों किया गया और अब केवल कुछ प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किये गये अधिकारियों के लिये स्थान पैदा करने के लिये उनसे पदोन्नत होने के लिये क्यों कहा जा रहा है ?

श्री भगवती : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बहुत थोड़े से समय के लिये काम हो सकता है और कोई ऐसी परियोजना हो सकती है जिसका काम बहुत तेजी से करना होता है। फिर, हमें प्रभाग बनाने होंगे और लोगों को अस्थायी रूप से नियुक्त करना होगा। ये सब अस्थायी अधिकारी हैं। ये पद हमें अस्थायी अवधि के लिये बनाने पड़े थे, केवल कुछ महीनों के लिये, क्योंकि कुछ महीनों के लिये भी हमें अधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं; हमें कुछ प्रभाग बनाने होते हैं और इन एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को नियुक्त करना होता है, चाहे वह केवल अस्थायी अवधि के लिये ही क्यों न हो। परन्तु इस कारण से हम उनको स्थायी आधार पर नहीं रख सकते।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि यह कहना गलत है कि श्रेणी एक के अधिकारियों के लिए

जगह बनाने के लिए उन सबकी पदावनति कर दी गई है। श्रेणी एक के अधिकारियों के लिए जगह बनाने के लिए उनमें से केवल एक को ही पदावनत किया गया है। अन्य छः व्यक्तियों को इसलिए पदावनत किया गया है कि कुछ प्रतिनियुक्ति पर थे और वे अब वापस आ रहे हैं, और फिर काम घट रहा है और इसलिए उनमें से कुछ वापस आ रहे हैं ; दो अवकाश पर थे और वे भी वापस आ रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका तो पहले से ही पता था।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं यह जानता हूं। आज स्थिति यह है : यदि कुछ अधिकारियों को पदोन्नति देनी होती है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि हमें उनके मार्ग में बाधा बननी चाहिए। इससे मेरा सद्भाव सिद्ध होता है। उनके अच्छे रिकार्ड को हम ध्यान में रखते हैं, परन्तु जब कोई स्थान नहीं होता तो उनको वापस आना होता है। पदावनति का अर्थ उनको हटाने से नहीं है।

श्री नम्बियार : फिर भी यह आवश्यक है कि सीधे रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों को पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : मुख्य इंजीनियर के 19 अगस्त, 1966 के पत्र के उद्धरण से यह प्रतीत होता है कि "निम्न एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को उनकी भारावमुक्त की तिथि से सहायक इंजीनियरों की श्रेणी में पदावनत करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के अन्तर्गत, इन सातों के सातों अधिकारियों को पदावनत कर दिया गया था, परन्तु उनके मूल विभाग में वापस जाने या प्रतिनियुक्ति पर जाने आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्या यह सच है कि ये सातों अधिकारी स्नातक हैं और पद के लिये वे पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त हैं? क्या उनके स्थान पर मिलती जुलती अर्हताओं के व्यक्तियों को लिया गया है या जो व्यक्ति अब भर्ती किये गये हैं उनकी अर्हता इन अधिकारियों से कम है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : दो प्रकार के अधिकारी हैं, अर्थात् श्रेणी एक और श्रेणी दो के अधिकारी। श्रेणी एक के अधिकारी के लिये 5 वर्ष की अवधि है और श्रेणी दो के अधिकारियों के लिए आठ वर्ष की अवधि है। हम उस नियम में शिथिलता लाये थे क्योंकि अधिकारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं थे। श्रेणी एक के अधिकारियों के लिए 3 वर्ष और श्रेणी दो के अधिकारियों के लिए 5 वर्ष का उदार नियम दोनों श्रेणियों पर लागू होता है। यदि मैं, श्रेणी दो के अधिकारियों के लिए 8 वर्ष के सामान्य नियम पर टिका रहता तो गत वर्ष उनमें से एक की भी पदोन्नति नहीं हो सकती थी।

दूसरे, ये अधिकारी मेरे अधिकारी हैं.....

श्री रंगा : क्या वे आपके घर का काम कर रहे हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जी हां, वे मेरे घर का काम करते हैं ; यह ठीक है।

श्री रंगा : वे सरकारी अधिकारी हैं ; वे आपके अधिकारी नहीं हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : ऐसा लगता है श्री रंगा को इस शब्द से चिड़ है । मैं इस मंत्रालय का कार्य भारी हूं, और वे निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के अधिकारी हैं.....(**व्यवधान**)

श्री रंगा : आप उनको डांटिये ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वे मंत्रालय के अधिकारी हैं ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : हमारे अधिकारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं ; उदाहरणार्थ, वे डाक और तार विभाग में जाते हैं, और भारत सरकार के अन्य विभागों में भी जाते हैं ; खाद्य विभाग में वे उस विभाग के लिये विशेषीकृत कार्य करते हैं । यदि काम घट जाता है, तो उन अधिकारियों को अपने मूल मंत्रालय को लौटना होता है, और फिर, यदि वे काफी वरिष्ठ हैं तो उनके लिए पद ढूंढ़ने होते हैं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या मंत्रालय द्वारा, किसी अधिकारी के पद के स्तर को गिराने के लिये संघ लोक सेवा आयोग की सम्मति प्राप्त करने की एक अत्यन्त अस्वस्थ प्रथा अपनाई जाने लगी है, जो कि निश्चित रूप से एक अनुशासनीय मामला है ? क्या माननीय मंत्री यह भी जानते हैं कि ऐसा केवल उन अधिकारियों द्वारा लिखे गये गोपनीय प्रतिवेदनों के आधार पर ही किया जाता है जिन्हें कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही आरम्भ करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है ?

श्री भगवती : ऐसा प्रशासनिक कारणों से किया जाता है । अनुशासनिक कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किये गये श्रेणी एक के अधिकारियों के लिए स्थान बनाने के लिए केवल एक अधिकारी की पदावनति की गई है । क्या इस मामले के विशेष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उस अधिकारी को बराबर के स्थान की पेशकश करने के प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : श्रेणी एक के दो अधिकारियों और श्रेणी दो के एक अधिकारी का कोटा नियत है । यदि हम उनको प्रत्यक्ष रूप से भर्ती नहीं करते या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं करवाते, तो श्रेणी के अधिकारी को श्रेणी दो के अधिकारियों में से ले लिया जाता है । परन्तु ज्योंही श्रेणी का कोई अधिकारी उपलब्ध हो जाता है, वह अनुपात बनाये रखना होता है ।

श्री नम्बियार : उसने पांच वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसको आप अब नहीं उठा सकते ।

श्री जोकीम आल्वा : सरकार द्वारा जिन भवनों का निर्माण किया गया है और जिनका

अनुमोदन किया गया है वे पूर्ण रूप से घटिया हैं, और इस काम में वास्तव में ठेकेदारों की चांदी है। इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए क्या परीक्षाएं रखी गई हैं? क्या कोई जांच समिति है जो पद के लिए उनके चरित्र और उनकी सक्षमता की जांच करे इसके पहले कि उनको भवन निर्माण कार्य दिया जाये, ताकि वे ऊपर मंत्रियों को और नीचे ठेकेदारों को भ्रष्ट न करें ?

श्री भगवती : प्रतियोगी परीक्षाओं और उनके घोषित परिणामों के आधार पर अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चाय प्रतिनिधिमंडल का विदेशों का दौरा

*814. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत जून में एक चाय प्रतिनिधि-मंडल ब्रिटेन, अमरीका तथा कनाडा के दौरे पर भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल के मुख्य विचार क्या हैं और उसने अपने दौरे के बाद सरकार को क्या सिफारिशें प्रस्तुत की हैं; और

(ग) उसकी सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) . एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-7002/66]**

राष्ट्रीय कोयला-बोर्ड

*817. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला बोर्ड तथा कोयला नियंत्रक के वर्तमान संगठनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कोयला-बोर्ड की स्थापना कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कोयला बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा क्या है ; और

(ग) इस विलय से क्या लाभ होने की आशा है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) :(क) से (ग). कोल बोर्ड एवं कोल कंट्रोलर कार्यालय के कार्य को वैज्ञानिक रूप से सम्पन्न करने के लिये दोनों के विलय का प्रस्ताव है जिससे कार्यों का अतिच्छादन न हो, कार्य में अधिक समन्वय हो तथा नियंत्रणकार्यों के अतिरिक्त विकास कार्यों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

चाय पर निर्यात शुल्क

*819. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय संस्था ने सरकार से प्रार्थना की है कि चाय पर लगे हुए निर्यात शुल्क की दर तुरन्त दो रुपये से घटा कर डेढ़ रुपया प्रति किलोग्राम कर दी जाये क्योंकि चाय के निर्यात में कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) जी, हां ।

(ख) कोई कमी करना सम्भव नहीं है । परन्तु शुल्क के यथामूल्य परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है यदि कोई विशेष प्रस्ताव किये जायं ।

आयातित सामान पर विक्री कर

*820. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिये गये इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि आयातित सामान पर विक्रीकर नहीं लगाया जा सकता, सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय सम्भरणकर्त्ताओं से विक्री कर वसूल कर रहा है, जो पिछले बिलों पर पहले ही दिया जा चुका है, और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सम्भरणकर्त्ताओं ने पहले ही राज्य सरकारों के पास विक्री-कर की राशि जमा करा दी है, केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्भरणकर्त्ताओं को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया): (क) जी, हां ।

(ख) कानूनी स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है और आगामी ऐसी कार्यवाही जो जरूरी होगी, विधि मंत्रालय की सलाह प्राप्त होने पर, की जाएगी ।

राज्य व्यापार निगम के पास आयातित अखबारी कागज

*821. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन के समय राज्य व्यापार निगम के पास आयात किया गया अखबारी कागज कितना था ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम उस कागज के लिए भी अवमूल्यन के बाद के दाम वसूल कर रहा है ;

(ग) क्या सरकार को समाचार-पत्रों से इसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-7003/66]

गाजियाबाद-शाहदरा और दिल्ली के बीच विशेष रेल गाड़ियों के लिये मांग

*822. **श्री पन्नालाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री बृजवासी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्री सुविधा संस्था ने मांग की है कि गाजियाबाद-शाहदरा और दिल्ली के बीच दो विशेष रेल-गाड़ियां चलाई जायें जिससे कि गाड़ियों में भीड़ को कम किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय गाजियाबाद-शाहदरा-दिल्ली खण्ड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इस खण्ड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता का अभाव है और दिल्ली/नई दिल्ली में पर्यन्त सुविधाएं नहीं हैं । अतिरिक्त सुविधाओं की योजना बनायी गयी है और जैसे ही ये सुविधाएं दिल्ली क्षेत्र में उपलब्ध होंगी, अतिरिक्त उपनगरीय गाड़ियां जिनमें दिल्ली-गाजियाबाद खण्ड की गाड़ियां शामिल हैं, चलाने के काम को हाथ में लिया जायेगा ।

गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योग

*823. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को धन की कमी के कारण हानि उठानी पड़ रही है क्योंकि अधिकतर धन सरकारी क्षेत्र में लगाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ये उद्योग अपना विस्तार कर सकें और उत्पादन को बढ़ा सकें ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क)और(ख). साधनों में कमी गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में जितनी पूंजी लगने की आशा थी उसकी तुलना में बचत में हुई कमी को बताती है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र में साधनों की कमी आर्थिक साधनों के भारी मात्रा में सरकारी क्षेत्र में चले जाने के कारण हुई है। घाटे की अर्थ व्यवस्था को दूर करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के खर्च में कमी की जा रही है तथा बैंकिंग प्रणाली के द्वारा ऋण को बढ़ने से रोकने पर कठोर नियंत्रण रखना भी उतना ही आवश्यक है। साथ ही पूंजी लगाने के लिए उपलब्ध साधनों के सीमा के अन्तर्गत उन वित्तीय संस्थाओं से जिनकी स्थापना पिछले कुछ वर्षों में गैर-सरकारी उद्योगों के लिये आर्थिक साधनों की व्यवस्था करने के लिए की गई थी, प्राथमिकता वाले उद्योगों की क्षमता बढ़ाने और उनका विस्तार करने के लिये सहायता करती रहेंगी।

वस्त्र नीति

*824. **श्री दे० जो० नायक :** **श्री भा० दा० देशमुख :**
श्री छोटू भाई पटेल : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के लिये अपनी वस्त्र नीति अन्तिम रूप से तय कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो कपास की आवश्यकता कितनी है और कपास की उपज कितनी है ; और

(ग) वस्त्र सलाहकार समिति की सिफारिशें क्या थीं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-7004/66]

Damage Caused by Floods in Ghaggar River in Rajasthan

*825. **Shri P. L. Barupal :** **Shri N. R. Laskar :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Prakash Vir Shastri:**
Dr. L. M. Singhvi : **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Daljit Singh : **Shri J. R. Mehta :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that much damage is caused to the Railway lines and other property every year by floods in the Ghaggar river in Sri Ganga Nagar Dirstrict, Rajasthan ;

(b) if so, the nature of damage caused thereby and the expenditure incurred by Railway Administration in this connection each year separately during the last five years ;

(c) whether this year also there have been breaches in the railway tracks at several places and the traffic has been completely paralysed ;

(d) whether some permanent measures are being adopted by Government to avoid such losses to the Railway Administration every year ; and

(e) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (e). The Railway lines in Shri Ganga Nagar District of Rajasthan suffer damage whenever floods occur in the Ghaggar river.

The damage to railway line takes place in the shape of breaches due to overtopping of the track at various places. The expenditure incurred for restoration of traffic during each of the last five years is : Rs. 1.61 lakhs in 1961-62, Rs. 2.61 lakhs in 1962-63, Rs. 1.82 lakhs in 1963-64 Rs. 2.85 lakhs in 1964-65 and Rs. 1.07 lakhs in 1965-66.

This year also breaches and overtopping of bank has occurred, between Hanumangarh and Hanumangarh Town, between Suratgarh and Rangmahal, between Rangmahal and Pilibangan, between Suratgarh and Sarupsar and between Sarupsar and Anupgarh.

The Governments of Rajasthan and Punjab, under the auspices of the Central Water and Power Commission are arranging to divert the Ghaggar waters into the sand dunes and construct canals on either side of the Otta reservoir after strengthening it. These works are in hand. The Railway has to build two bridges on the diversion channel, one of which has been completed and the other one will be completed in the coming working season.

Campaign against Profiteers in Punjab

*826. **Shri Yudhvir Singh :** **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Daljit Singh**
Shri Kashi Ram Gupta : **Shri Sadhu Ram :**
Shri Nambiar : **Shri Hem Raj :**
Shri Solanki :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of arrests made so far under the campaign launched by the Governor of Punjab against the traders indulging in profiteering, hoarding and adulteration ;

(b) the quantity of goods recovered as a result thereof ;

(c) whether corrupt Government officials have also been arrested under this campaign ; and

(d) if so, the number thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No LT-7005/66]**

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उद्योग

*827. **श्री राजदेव सिंह :** **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री विश्राम प्रसाद : **श्री गहमरी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के एकसम विकास के हित में उद्योगपतियों पर किसी प्रकार का

प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार कर रही है जिससे कि उद्योग केवल बड़े नगरों में ही स्थापित न किये जायें ;

(ख) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को अत्यधिक गरीबी और पिछड़ेपन के बारे में पटेल अध्ययन दल की सिफारिशों के बारे में जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन जिलों में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) यद्यपि सरकार का नियंत्रण लगाने का कोई विचार नहीं है फिर भी सरकार औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए योजनाओं को लाइसेंस देते समय इस बात को ध्यान में रखती है कि उद्योग बड़े शहरों में ही केन्द्रित न हो जायें ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश/उत्तरी बिहार क्षेत्र में कागज तथा लुगदी बनाने का एक कारखाना लगाने की संभावना पर कागज निगम द्वारा विचार किया जा रहा है लेकिन यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है और इस बारे में निश्चित निर्णय विस्तृत तकनीकी आर्थिक अध्ययन के मिलने पर ही किया जा सकेगा । लघु उद्यमियों को ऋण देने तथा इन जिलों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के लिए विशेष कार्रवाही की गई है ।

भारत-अफगानिस्तान व्यापार

*828. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान भारत-अफगानिस्तान व्यापार में रुकावट डालने और इसको अस्त-व्यस्त करने के लिये निश्चित रूप से प्रयत्न कर रहा है और क्या पाकिस्तान केवल अफगानिस्तान से भारत आने वाली वस्तुओं के लिये ही हवाई मार्ग देने के लिये सहमत हुआ है और न कि भारत से अफगानिस्तान जाने वाली वस्तुओं के लिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पाकिस्तान ने भारत तथा अफगानिस्तान के मध्य सभी सामान को कराची के रास्ते से लाने-ले जाने की अनुमति दे दी है । हाल ही में अफगानिस्तानी ताजे फलों को हुसैनीवाला सीमा चौकी के रास्ते से भारत लाने के लिये भी पाकिस्तान द्वारा अनुमति दी गयी है । फिर भी, पाकिस्तान ने हुसैनीवाला के रास्ते से, भारत से अफगानिस्तान को माल ले जाने की अनुमति नहीं दी है ।

(ख) सरकार, भारत-अफगानिस्तान व्यापार के लिये स्थल-मार्ग खोलने हेतु पाकिस्तान से अनुरोध कर रही है ।

बर्मा को नारियल जटा का निर्यात

*829. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जून, 1966 से पहले के रुपयों में किये गये करार सम्बन्धी मूल्य पुनः निर्धारित कर देने से बर्मा सरकार द्वारा इन्कार किये जाने के कारण नारियल जटा के भारतीय निर्यातकों को भारी हानि हो रही है ;

(ख) क्या सरकार को केरल के नारियल जटा के निर्यातकों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) इन मामलों पर बातचीत करने के लिए एक उच्च शक्तियुक्त प्रतिनिधिमण्डल शीघ्र ही बर्मा के लिए रवाना होने वाला है ।

ऊनी होजरी के लिए निर्यात संवर्धन योजना

*830. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** **श्री बड़े :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी होजरी के लिए निर्यात संवर्धन योजना की घोषणा कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). ऊनी होजरी के लिए निर्यात संवर्धन योजना घोषित नहीं की गई है । फिर भी पंजीकृत निर्यातकों के लिए सभी कच्चे माल की सुविधाएं दोनों आयातित तथा स्वदेशी उपलब्ध की जायेंगी ।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

*831. **श्री बूटा सिंह :** **श्री गुलशन :**
श्री रामसेवक यादव : **श्री मधु लिमये :**
श्री प० ह० भील :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में बन्द हुई कपड़ा मिलों, तकुओं तथा करघों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी मिलें पुरानी तथा अलाभप्रद हैं;

(ग) कितनी कपड़ा मिलें अब सरकार द्वारा नियुक्त नियन्त्रकों द्वारा चलाई जा रही हैं ; और

(घ) चालू वर्ष में इन मिलों को चलाने से कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) देश में लगभग 164 लाख तकुओं तथा 2 लाख करघों वाली लगभग 600 मिलों में से लगभग तीन लाख तकुओं तथा 4388 करघों वाली 11 मिलें जनवरी 1966 से बन्द हो गई हैं। जनवरी 1966 से भी पहले बन्द हुई 6 मिलें अभी तक बन्द पड़ी हैं।

(ख) दो।

(ग) बारह।

(घ) 12 में से केवल 7 मिलों का प्रबन्ध गत सात या आठ महीनों से अधिकार में ले लिया गया है और चालू वर्ष में इन चालू मिलों तथा अन्य मिलों के वित्तीय परिणाम अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं परन्तु बहुत सी मिलें मुनाफा कमा रही हैं। जिन मिलों को अधिकार में लिया गया है उनमें से कुछ घाटे पर भी चल रही हैं।

Passenger Fare Between Fatehpur and Churu (Rajasthan)

*832. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Y. D. Singh :
Shri Gulshan :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the distance between Fatehpur and Churu (Rajasthan) is 24 miles while the passenger fare is charged for 54 miles ;

(b) if so, whether fare for additional distance is being charged from the passengers on any other sections also ; and

(c) if so, whether his Ministry propose to take any steps to remove this discrepancy ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The actual distance between Fatehpur and Churu is 27 miles (or 43.5 kilometres) and chargeable distance is 54 miles (or 87 kilometres).

(b) Yes, Sir.

(c) There is no discrepancy in view of the answer to Part (b) of the question. Moreover, even with the levy of rates and fares on an inflated distance basis an economic return is not obtained on the capital cost of the line.

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड

*833 **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन के इस वक्तव्य, जैसा कि 12 अगस्त, 1966 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है, की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा उसकी बैलेंसिंग प्लांट स्कीम को स्वीकृत देने में बहुत अधिक विलम्ब किये जाने के कारण देश में 3,00,000 टन इस्पात का अतिरिक्त उत्पादन नहीं हो सका और इसके परिणामस्वरूप इस अवयध अवधि में देश को प्रति वर्ष 26·27 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत नहीं हो सकी; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1962 में पेश की गई योजना को मई, 1966 से पहले स्वीकृत न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) और (ख). जी, हां। विस्तार योजना, जिसे आरम्भ में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने जून 1962 में प्रस्तुत किया था, सरकार द्वारा अप्रैल 1963 में अनुमोदित की गई थी। तत्पश्चात कम्पनी द्वारा मूल प्रस्थापनाओं में किये गये कुछ संशोधनों तथा समय-समय पर दिये गये संशोधित प्राक्कलनों की जांच की गई। अधिक देरी इसलिये हुई कि कम्पनी कम क्षमता का एक पावर प्लांट लगाने पर जिद कर रही थी जो मितव्ययी नहीं था और जो विस्तार-कार्यक्रम के लिए आवश्यक भी न था तथा कई बार लागत-प्राक्कलनों में संशोधन करने के कारण हुई।

रेलवे के अतिरिक्त इंजन

*834. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान ('ब्लिट्ज' दिनांक 18-6-66 में प्रकाशित) इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि :

"यह जानने के लिए कि रेलवे ने इतने अतिरिक्त इंजन किस प्रकार प्राप्त किये हैं किसी भी व्यक्ति को ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं होती है;"

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में रेल इंजनों की खरीद का जो आरोप लगाया गया है, उसका कोई आधार नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में पंखे और प्रकाश की व्यवस्था

*835. **श्री मधु लिमये :** **श्री बागड़ी :**
श्री किशन पटनायक : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि रेलगाड़ी के डिब्बों में पंखे तथा बिजली बार-बार खराब हो जाते हैं;

(ख) क्या इस बारे में भी शिकायतें मिली हैं कि विभिन्न स्टेशनों पर प्रायः निशुल्क सफाई की व्यवस्था नहीं होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) कभी-कभी, बत्ती और पंखे खराब होने की शिकायतें मिली हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार अनुरक्षण का ऊंचा स्तर बनाये रखने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और समय-समय पर अनुरक्षण के तरीकों की समीक्षा और उपस्करों का नवीकरण करके सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर पेट्रोल के टेंकरों का फट जाना

*836. **श्री प्र०चं० बरुआ :** **श्री गुलशन :**
श्री बड़े : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री कृष्णपाल सिंह :**
श्री हरि विष्णु कामत : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री कपूर सिंह : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 जून, 1966 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर अलीपुर और सुधानी स्टेशनों के बीच कटिहार जाने वाली एक माल गाड़ी में पेट्रोल के कुछ टेंकरों में आग लग गई और वे फट गये;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). 13-6-1966 को नं० 902 डाउन पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी सुधानी और अलीपुर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गयी।

इस कारण से धातु में जो रगड़ पैदा हुई उससे चिनगारियां निकलीं और पेट्रोल की चार टंकियों में आग लग गयी । लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 4,92,675 रुपये का नुकसान पहुंचने का अनुमान है ।

Supply of Foodgrains to Employees Working at Shamgarh Railway Station

* 837. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that there are no proper arrangements for the supply of foodgrains to nearly 4,500 persons comprising of the employees working at Shamgarh Railway station and their family members ;

(b) whether it is also a fact that they are apprehended by the Police if they bring foodgrains from other places ;

(c) whether it is also a fact that the licence of the shop set up by them on cooperative basis has been cancelled ; and

(d) if so, the arrangements being made for the supply of foodgrains to them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Proper arrangements for the supply of foodgrains to 505 Railway staff headquartered at Shamgarh exist through the fair price shop run by the local Railwaymen's Consumer Cooperative Society.

(b) Yes Sir. They are liable to be apprehended by the Police as per restrictions imposed by the Madhya Pradesh Government on inter-district movement of foodgrains by rail within Madhya Pradesh State. No such case however, has come to the notice of the Railway Administration so far.

(c) Licence was not cancelled but taken away by the Food Inspector, Garoth, on 14.8.66 as per instructions given by Tehsildar and returned to the Society on 15.8.66.

(d) Does not arise.

व्यासरपाडी रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

4094. **श्री राम हरख यादव :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े : **श्री यु० द० सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 जुलाई, 1966 को दक्षिण रेलवे पर व्यासरपाडी रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी का इंजन और दो डिब्बे पटरी से उतर गये जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों को चोट पहुंची;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या ब्योरा है; और

(ग) यदि जान-माल की कोई हानि हुई है तो उसका क्या ब्योरा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). जी नहीं। लेकिन उस दिन जब नं० 350 सिक लोकल गाड़ी पेरम्बूर और व्यासरपाडी आटोमेटिक ब्लाक सेक्सन के बीच अप धीमी लाइन के व्यासरपाडी सिगनल नं० 74 पर इन्तजार कर रही थी तो कोचिंग ट्रायल गाड़ी जो पेरम्बूर पश्चिम से चली थी, उससे टकरा गई। इससे कोचिंग ट्रायल गाड़ी के इंजन का टेण्डर और सिक लोकल गाड़ी का ब्रेक यान और डमी ट्रक पटरी से उतर गये। इससे पांच रेल कर्मचारियों को चोटें आयीं।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई। रेल सम्पत्ति को लगभग 12,550 रुपये की क्षति का अनुमान है।

हावड़ा-बम्बई मेल की ट्रक से टक्कर

4095. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई जाने वाली हावड़ा मेल 21 जुलाई, 1966 की प्रातः दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा, नागपुर सेक्सन पर झारसुगुडा रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना ग्रस्त हो गई;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या ब्योरा है; और

(ग) यदि जान-माल की कोई हानि हुई है; तो उसका क्या ब्योरा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). 21-7-66 को, जब गाड़ी नं० 2 अप हावड़ा-बम्बई डाक झारसुगुडा और इब स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो वह किलोमीटर 515/10-11 पर बिना चौकीदार वाले समपार पर एक मोटर ट्रक से टकरा गयी।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई। रेल सम्पत्ति को लगभग 75 रुपये की हानि का अनुमान है।

मद्रास के निकट दुर्घटना

4096. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 जुलाई, 1966 को दक्षिण रेलवे पर मद्रास के निकट पल्लावरम और क्रामपेट उपनगरीय स्टेशनों के बीच एक महिला और उसके तीन बच्चे कांचीपुरम फास्ट पैसेंजर रेलगाड़ी के नीचे आ गये; और

(ख) यदि हां, तो इस दुखद घटना का क्या ब्योरा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). 28-7-66 को लगभग 18.40 बजे पल्लावरम् और ताम्बरम स्टेशनों के बीच किमी० 25/1 पर अनधिकृत रूप से लाइन पार करते समय 1 महिला और उसके 3 बच्चे गाड़ी नं० 647 मद्रास बीच-कांजीवरम् सवारी गाड़ी के नीचे आ गये।

Train between Delhi and Rohtak

4097. **Shri Jagdèv Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Government employees working in offices travel between Delhi and Rohtak by No. 1-D.K.S. and 342-Down trains ;

(b) whether it is also a fact that these two trains generally run late ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether any scheme has been formulated to run trains according to schedule so that the employees who travel by these trains might be able to attend office in time ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a). Yes.

(b) and (c). An analysis of punctuality performance of 1 DKS and 342Dn from April to July, 66 has shown that while the running of the former wasquite sa tisfactory, its punctuality being more than 95%, that of 342 Down–a long distance train–was not so good, due to displaced crossings on the single line section between Ferozepore and Delhi caused by Control interruptions, signal failures. etc.

(d) Instructions have been issued to the staff that these trains should be given priority in running over other trains including even Mail/Express trains, in the suburban area. A special watch is being kept on the running of these trains and every endeavour is being made to ensure their punctual running.

Over-Bridge at Lucknow Naka Railway Crossing

4098. **Shri Rananjai Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a scheme for the construction of an over-bridge for traffic purposes at 'Lucknow Naka' railway crossing of Sultanpur, Northern Railway is under consideration ;

(b) if so, when the work is likely to be completed ;

(c) whether an over-bridge is also proposed to be constructed at Aish Bagh railway crossing in Lucknow ; and

(d) if so, when the same is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) A proposal was received from the Lucknow Nagar Mahapalika for construction of a sub-way only in replacement of the existing level crossing at Aish Bagh west-end, but as the gradients of the approach roads in this proposal were found to be too steep and not in accordance with the recommendations of the Indian Roads Congress, the Nagar Mahapalika are now examining an alternative proposal, the details of which are awaited by the Railway.

(d) It is too early to say as the scheme is only in a preliminary stage of investigation.

अविकारी इस्पात से कपड़ा बुनना

4099. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविकारी इस्पात से जाली और कपड़ा बुनने के अमरीकी आविष्कार की जानकारी सरकार को है;

(ख) यदि हां, तो इस आविष्कार का ब्योरा क्या है; और

(ग) पोशाक के रूप में इसकी वाणिज्यिक उपयोगिता कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). ज्ञात हुआ है कि सं० रा० अमेरिका की ब्रन्जविक कारपोरेशन, कम्बलों, काम के समय के कपड़ों, बच्चों के कपड़ों और सैनिक कपड़ों को मजबूत बनाने के लिये धात्विक रेशों पर प्रयोग कर रहा है। इसकी वाणिज्यिक उपयोगिता के बारे में अभी कोई राय नहीं दी जा सकती है ।

नेपाल से चावल

4100. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नेपाल भारत को शीघ्र ही बड़ी मात्रा में चावल बेचने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) यह चावल किस किस्म का और कितना होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). नेपाल सरकार ने भारत को कुछ चावल बेचने का प्रस्ताव किया है। इसके सम्बन्ध में बातचीत चल रही है ।

ट्रैक्टरों के मूल्य

4101. **श्री वै० तेवर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन से पूर्व मैसी फर्गुसन, हिन्दुस्तान, एस्कार्ट्स और रूस से आयात किये गये ट्रैक्टरों (छोटे तथा बड़े) के मूल्य क्या थे;

(ख) इस समय इन ट्रैक्टरों के मूल्य क्या हैं और पुनरीक्षित मूल्य कब से लागू किये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के कारण 6 जून के बाद बने ट्रैक्टरों के वर्तमान बढ़े हुए मूल्यों के लिए अनुमति दी गई है यद्यपि उनके पुर्जे अवमूल्यन से पहले आयात किये गये थे; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त ट्रैक्टरों के निर्माण में कितने प्रतिशत आयात किये गये पुर्जे लगाये जाते हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) . मैसी फर्गुसन, हिन्दुस्तान, एस्कोर्ट तथा आयातित रूसी ट्रैक्टरों के अवमूल्यन से पहले के तथा वर्तमान मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

ट्रैक्टर का नाम	अवमूल्यन से पहले का मूल्य	वर्तमान मूल्य	टिप्पणी
मैसी फर्गुसन	16,446 रु०	21,401 रु० (6 जून 1966 से)	ये वे मूल्य हैं जिनपर इस समय ट्रैक्टर बेचे जाते हैं।
एस्कोर्ट 34 अश्व शक्ति	15,400 रु०	17,300 रु० (6 जून, 1966 से)	इन ट्रैक्टरों के लागत की जांच वित्त मंत्रालय के लागत लेखा विभाग द्वारा हाल ही में पूरी की गई है। इस लागत जांच के परिणामों पर आधारित इन ट्रैक्टरों के उचित विक्रय मूल्य का निश्चय शीघ्र ही किया जायेगा।
हिन्दुस्तान 50 अश्व शक्ति	17,650 रु०	20,237·50 (12-8-66 से)	यह वह मूल्य है जिस पर निर्माता को उस समय तक बेचने के लिए कहा गया है जब तक लागत की जांच न हो जाय तथा जिसके लिए आवश्यक विवरण मांगा गया है। लेकिन निर्माता ने इसके विरुद्ध एक अभ्यावेदन दिया है तथा इस पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना की है।
रूसी डी०टी०-14 बी उच्च शक्ति के रूसी ट्रैक्टरों का अब आयात नहीं किया जा रहा है।	5,800 रु०		अवमूल्यन के बाद इन ट्रैक्टरों का अभी आयात नहीं हुआ है अतः इनके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) कुछ मामलों में निर्माताओं ने सम्भरण कर्त्ताओं के साथ भुगतान की व्यवस्था को स्थगित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वास्तव में अवमूल्यन से पूर्व आयात किए गए पुर्जों के मूल्य का भुगतान अवमूल्यन से बाद की विनिमय दर पर किया जायेगा । अवमूल्यन के कारण बढ़े मूल्यों के लिये निर्माताओं के इस दावे को ध्यान में रखा गया है ।

(घ) स्वदेश में निर्मित उपरोक्त ट्रैक्टरों में आयातित पुर्जों का अनुपात निम्न प्रकार है ?

(I) मैसी फर्गुसन	40 प्रतिशत
(II) एस्कार्टस 34 अश्व शक्ति	50 प्रतिशत
(III) हिन्दुस्तान 50 अश्व शक्ति	38 प्रतिशत

Rush in Trains running between Delhi and Ferozepur

4102. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any complaint has been received regarding the inadequate number of third class compartments and excessive rush in 341-UP and 342-Down trains running between Delhi and Ferozepur ;

(b) if so, the steps taken to remove this difficulty ; and

(c) whether a definite number of seats of different classes are provided in one and the same bogie ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, representations have been received about overcrowding on No. 342 Dn, Ferozpur Delhi Passenger.

(b) As per April, 66 census, some overcrowding was noticed on Rohtak-Delhi section on 342 Dn Ferozpur-Delhi passenger train, which was then running short by one third class coach. Action has since been taken to ensure that this train runs with full composition of 9 coaches. The feasibility of augmenting its load further is also under examination.

(c) The designs of composite coaches have now been standardised providing for a specified number of berths/seats in each class of accommodation.

Shelter at Bahadurgarh Railway Station

4103. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3091 on the 1st April, 1966 and state :

(a) whether the shelter over the passenger platform at the Bahadurgarh railway station has since been constructed ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) when the work is expected to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) The work of erection of shelter would be started as soon as the steel fabrication work, which is now in progress, is completed.

(c) The work is expected to be completed by December, 1966.

Allotment of Cars and Scooters

4104. **Shri Vishram Prasad :**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the number of Government Officers and employees who got cars or scooters on priority basis from Government quota, or otherwise, during the last 10 years ; and

(b) the number of persons among them who have either applied for the purchase of cars or scooters or have purchased the same for second time ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The allotment of cars from the Central Government quota is being made since 1959 and of scooters since 1960. Complete information about the allotments actually issued during this period is not available at one place and has to be collected from numerous files. It is felt that the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the results.

गुजरात राज्य में छोटी (नैरो गेज) रेलवे लाइन

4105. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य (पश्चिम रेलवे) क्षेत्र में नैरो गेज रेलवे लाइनों को निकट भविष्य में ही बन्द करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य के लिये कौन सी अन्य योजनायें बनाई गई हैं तथा छोटी (नैरो गेज) रेलवे लाइन को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) पश्चिम रेलवे पर छोटी लाइनों को बन्द करने का अभी कोई विचार नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के क्षेत्रीय काम करने के भत्तों की बकाया राशि

4106. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग (जिसका नाम पहले भारतीय खान ब्यूरो था) की खोज शाखा के कर्मचारियों को अगस्त, 1962 से क्षेत्रीय काम करने के भत्तों की मंजूर की गई बकाया राशि का अभी तक भगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) बकाया राशि का भुगतान कब किया जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). 850 अधिकारियों ने जो अध्यर्थनाएं दी थीं उनमें से केवल 65 निलम्बित हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 20 अध्यर्थनाएं लेखा परीक्षक के कार्यालय में अधिकरण के लिए निलम्बित हैं। इन अध्यर्थनाओं का फैसला करने में देरी होने का कारण यह है कि ये भत्ता केवल कुछ विशिष्ठ शर्तों को पूरा करने पर ही दिया जा सकता है। लेखा परीक्षक के परामर्श से विस्तृत कार्याविलि इन अध्यर्थनाओं को पेश करने के विषय में बनाई गई थी। इस कारण अवश्यमेव कुछ समय लग गया।

(ग) आशा है कि सब निलम्बित अध्यर्थनाओं पर अक्तूबर, 1966 के अंत तक फैसला हो जायगा।

मत्स्य भोजन का निर्यात

4107. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा कमाने के लिये मत्स्य भोजन (फिश मील) का निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). सीमित उत्पादन तथा भारी आन्तरिक मांग के कारण मत्स्य भोजन का वर्तमान निर्यात नगण्य है।

रेल किराये की वापसी के दावे

4108. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंशिक रूप से की गई यात्रा के परिणामस्वरूप बची रेल किराये की बाकी राशि की वापसी के सम्बन्ध में कितने दावे पिछले छः महीने और एक साल से अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) आंशिक रूप से की गयी यात्रा के परिणामस्वरूप बची रेल किराये की बाकी राशि की वापसी के सम्बन्ध में 30-6-1966 को पिछले छः महीने और एक वर्ष से अनिर्णीत पड़े दावों की संख्या क्रमशः 24 और 28 थी।

(ख) विलम्ब का कारण यह है कि दावेदारों ने शुरू में अपर्याप्त और गलत विवरण दिया और अन्य सम्बन्धित रेलों से लेखा सम्बन्धी विवरण नहीं मिला।

(ग) रेलों को कहा गया है कि इन मामलों को जल्द निबटाने के लिए कारगर कदम उठायें।

Doubling of Railway Line Between Delhi-Kishanganj and Shakurbasti Stations

4109. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 889 on the 25th February, 1966 and state :

(a) whether the work relating to the doubling of the railway line between Delhi-Kishanganj and Shakurbasti Stations has been started ;

(b) if not, the reasons, therefor ; and

(c) when this work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) and (b). The work is provided for in the Budget for 1966-67. Preliminary arrangements have been finalised and the work is expected to be taken in hand shortly.

(c) The work is planned to be completed by March, 1968, subject to the availability of funds.

रूज पाउडर की आवश्यकता और उत्पादन

4110. **श्री ज० रा० मेहता :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : निम्नलिखित वस्तुओं की (एक) भारत में वार्षिक मांग कितनी है; (दो) देश में कितना उत्पादन होता है; (तीन) कितनी मात्रा में आयात किया जाता है; और (चार) विभिन्न देशों से कितने मूल्य का आयात किया गया :

1. रूज पाउडर
2. सिलिका जेल
3. सिन्थेटिक आइरन आक्साइड पाउडर (लाल)
4. सिन्थेटिक आइरन आक्साइड पाउडर (काला)
5. प्लास्टिक स्टील
6. आइरन सीमेंट
7. मैग्नेटिक केक पता लगाने वाली स्याही ।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (एक) तथा (दो). निम्नलिखित मदों को छोड़ कर आवश्यक वार्षिक परिमाण और देश में उत्पादन के संबंध में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है :—

(1) **सिन्थेटिक आइरन आक्साइड (लाल)**

1964-65 में इस मद का उत्पादन 4.50 मी० टन हुआ ।

(2) **आइरन सीमेंट**

उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1962	40 मी० टन
1963	14.5 मी० टन

(तीन) तथा (चार) : भारतीय व्यापार वर्गीकरण में सिलिका जेल तथा आइरन आक्साइड को छोड़कर इन मदों का अलग से वर्गीकरण नहीं किया गया है, अतः प्रत्येक के आयात के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें 1965-66 में इन दो मदों के देशवार आयात (परिमाण तथा मूल्य) दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-7006/66]

उत्तर रेलवे के भंडार नियन्त्रक तथा भंडार उपनियन्त्रक

4111. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 के मध्य में सेवानिवृत्ति की आयु से पहले सेवानिवृत्त किये गये उत्तर रेलवे के मुख्यालय के भूतपूर्व भण्डार नियंत्रक तथा भण्डार उपनियंत्रक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले हैं; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ आरोप अनिर्णीत पड़े हुए हैं जो जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए:—

(i) क्रियाविधि सम्बन्धी उन त्रुटियों को यथासंभव दूर किया जा रहा है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार के कामों में सहायता पहुंचती है।

(ii) सतर्कता सम्बन्धी कार्यों के निवारक पहलू पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और क्षेत्रीय रेलों के सतर्कता अधिकारियों और रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय द्वारा भी अचानक जांच की जाती है।

उत्तर रेलवे के मुख्यालय के कार्यालयों की इमारत

4112. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के मुख्यालय के कार्यालय की इमारत में हाल में आरम्भ किये गये भित्ति चित्रों की रचना और सामग्री पर कितना खर्च हुआ; और

(ख) श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन, और श्रेणी चार के कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण पर कितना खर्च हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह): (क) 50,000 रुपये।

(ख) दिल्ली क्षेत्र में निवास के वर्तमान मान के अनुसार विभिन्न टाइप के कर्मचारी-क्वार्टरों की प्रति यूनिट अनुमानित लागत इस प्रकार है:—

	रुपये
(i) श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के प्रवर वेतन-मान और अवर वेतन-मान अधिकारियों के लिए	20,600
(ii) श्रेणी 3 के प्रवर कर्मचारियों के लिए	14,200
(iii) श्रेणी 3 के अवर कर्मचारियों के लिए	10,700
(iv) श्रेणी 4 के कर्मचारियों के लिए	6,300

Explosion in House in Chattarpur (Rewa)

4113. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three persons died owing to the explosion in a house in Chattarpur (Rewa Division) ;

(b) if so, the cause of the explosion ; and

(c) the extent of loss in terms of money and property?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes, Sir.

(b) The exact cause of the explosion could not be ascertained.

(c) As the tiled roof of the mud and thatched building only had collapsed, the loss in terms of money and property could not be appreciable.

Survey of Nagaland

4114. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No, 1690-A on the 13th May, 1966 and state :

(a) whether it is a fact that the original records relating to the survey conducted by Mr. Cyril Fox in those areas is missing ;

(b) whether it is also a fact that Mr. Fox took those survey records with him while leaving India ; and

(c) if so, the person responsible and the action taken in the matter ?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) and (b). No, Sir, Dr. Cyril Fox of the Geological Survey of India visited some of the coalfields of Upper Assam in 1926-27 but no regular survey was carried out by him and, therefore, he did not submit a

report for that work. His observations were, however, published in the General Report of the Geological Survey of India for the year 1927 and also in the Brochure on "Economic Mineral Resources of Assam", published by the Government of Assam in 1947.

(c) Does not arise.

पंजाब में अखबारी कागज परियोजना

4115. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री सोनावने :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री दलजीत सिंह :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मई, 1966 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब के पुनर्गठन के कारण 20 करोड़ रुपये की लागत से अखबारी कागज की मिल स्थापित करने की एक बहुत बड़ी परियोजना खटाई में पड़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है कि यह परियोजना क्रियान्वित हो ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी, हां; लेकिन माननीय सदस्य सम्भवतः 25 मई, 1966 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार का उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि उस पत्र के 28 मई, 1966 के अंक में ऐसा कोई भी समाचार प्रकाशित नहीं हुआ है ।

(ख) इस योजना को खटाई में नहीं डाला गया है लेकिन पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों का प्रस्तावित पुनर्गठन किये जाने के कारण आगे की कार्यवाही तब तक के लिए रोक दी गई है जब तक नई व्यवस्था नहीं कर ली जाती ।

इलाहाबाद के निकट भारी पम्प और कम्प्रेशर संयंत्र

4116. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री 13 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1666 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद के निकट रूस के सहयोग से पम्प तथा कम्प्रेशर संयंत्र स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अल्मोनियम संयंत्र

4117. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने अल्मोनियम संयंत्र चल रहे हैं;

(ख) कितने अल्मोनियम संयंत्रों के लिए लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) मैसूर राज्य के बेलगांव जिले में लगाये जाने वाले प्रस्तावित अल्मोनियम संयंत्रों में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इन संयंत्रों में कब उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) आवश्यक सूचना का एक विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7007/66]**

(ख) निजी क्षेत्र की एक कम्पनी को जुलाई 1964 में मैसूर राज्य में 30,000 मीटरी टन प्रति वर्ष क्षमता का एक नया प्रद्रावक लगाने का अभिप्राय पत्र जारी किया गया था। कंपनी ने अब बेलगांव (मैसूर राज्य में) प्रद्रावक स्थापित करने का स्थान चुन लिया है, महाराष्ट्र के दक्षिणी कोल्हापुर क्षेत्र में स्फोदिज निक्षेपों का अनुसंधान किया है तथा आवश्यक विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए मैसूर राज्य अधिकारियों के साथ एक समझौता कर लिया है। परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा तथा विदेशी सहयोग प्राप्त करने के कम्पनी के प्रस्तावों को भारत सरकार ने अनुमोदन दे दिया है। आशा है 1969 में एल्यूमिनियम प्रद्रावक उत्पादन आरम्भ कर देगा।

विदेशों में उद्योगों की स्थापना

4118. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री उन देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनके साथ भारत ने वर्ष 1965 में तथा जून, 1966 तक विदेशों में उद्योग स्थापित करने के लिए इक्विटी शेयरों में सहयोग दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): समीक्षाधीन अवधि में भारत सरकार ने भारतीय निजी पार्टियों द्वारा निम्न देशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यम स्थापित करने में इक्विटी पूंजी-निवेश के लिए स्वीकृति दी है :—

नाइजीरिया, इथोपिया, केनिया, तान्जानिया, लंका, ईरान, सऊदी अरब, कोलम्बिया, कनाडा, ब्रिटेन, मलयेशिया, हांगकांग और फिलीपीन।

बीकानेर रेलवे स्टेशन

4119. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री मौर्य :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री 29 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4641 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच बीकानेर रेलवे स्टेशन को उसके वर्तमान स्थान से हटाकर और नगर की नगरपालिका सीमा के भीतर रेलवे फाटक पर ऊपरी और निचला पुल बनाने के बारे में निश्चय कर लिया गया है;

(ख) क्या विश्राम कक्ष और जलपान गृह की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) जी नहीं। इस मामले पर अभी राजस्थान सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और राज्य सरकार के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

रेल की पटरी से फिश प्लेटों का हटाया जाना

4120. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 मई, 1966 को रावलगंज रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के समीप रेल की पटरी से फिश प्लेटें हटाई हुई पाई गईं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह): (क) जी हां।

(ख) छपरा की सरकारी रेलवे पुलिस ने 20-5-1966 को भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अधीन एक मामला अपराध सं० 5 दर्ज किया है। अब तक दो गैंगमैन गिरफ्तार किये गये हैं। पुलिस मामले की अभी जांच कर रही है। खुफिया विभाग का एक अफसर इस मामले की जांच के काम में सहायता कर रहा है।

खादी भवन

4121. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली तथा अन्य बड़े नगरों में खादी भवनों के किरायों तथा कर्मचारियों आदि पर एक बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन भवनों में कार्य धीमी गति से हो रहा है तथा उसमें सेवा की भावना नहीं है; और

(ग) इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित नयी दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, कलकत्ता, गोआ और भोपाल स्थित खादी ग्रामोद्योग भवनों की संस्थापन और किराये जिसमें दरें तथा कर शामिल हैं, पर 1964-65 में क्रमशः कुल 11.45 लाख रु० तथा 2.43 लाख रु० व्यय हुआ और इन भवनों में उस वर्ष 175.39 लाख रु० की बिक्री हुई । संस्थापन और किराये पर हुआ खर्च कुल बिक्री का 7.91 प्रतिशत था ।

(ख) जी, नहीं । खादी आयोग के अधिकारियों द्वारा इन भवनों के कार्य-पालन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Export of Steel and Machinery

4122. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any efforts have been made to explore markets for Indian steel and machinery ;

(b) if so, the extent of success achieved ; and

(c) the precautions being taken to ensure that our goods may stand well in international competition ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir. Foreign markets are being surveyed for Indian Steel and machinery through trade delegations, study teams. Engineering Export Promotion Council's foreign offices and the Indian Trade Representatives abroad and other Commercial Agencies.

(b) Exports of steel and machinery have risen from Rs. 2.82 crores and Rs. 3.49 crores in 1964-65 to Rs. 5.53 crores and Rs. 4.36 crores respectively in 1965-66.

(c) Pre-shipment inspection and other quality control measures have been taken, to ensure quality of the goods exported.

Seizures of Explosives Near Jorai

4123. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a box full of explosives was seized near Jorai Railway Station ;

(b) if so, the country to which this material belonged as also its quantity ; and

(c) the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No. However, on 1-5-66, a small detached mechanical part 2" in length and 1¼" in diameter was found near the railway track of Jorai Railway Station. The recovered article appeared to be a mechanical fitting resembling air breather normally fitted in engine crank ease or gear box.

(b) and (c). Do not arise.

Railway Signal Workshop at Secunderabad

4124. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a proposal for the setting up of a signal workshop at Secunderabad is under consideration of Government ;

(b) if so, when it will be commissioned ;

(c) the amount of foreign exchange likely to be saved thereby ; and

(d) the names of the countries from where the material was used to be imported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) It is planned to complete the work in 1968.

(c) Rs. 50 to 100 lakhs per annum.

(d) Mostly from U. K, U. S. A., Japan, West Germany, Sweden and France.

Death of a man at New Delhi Station

4125. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a 30 year old young man was crushed to death by a train at the New Delhi Railway Station on the 30th May, 1966 ;

(b) if so, the circumstances in which the man was run over by the train ;

(c) the name of the place to which the youngman belonged ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) and (b). According to the Government Railway Police a 70 year old man is reported to have been run over and killed by some train or engine while crossing the railway line near 'A' Cabin of New Delhi station on 30-5-66.

(c) Since the dead body could not be identified its particulars could not be ascertained.

कपड़ा मिलों को बैंकों द्वारा ऋण

4126. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्री बागड़ी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कठिनाई-ग्रस्त कपड़ा मिलों को बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने के बारे में महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के साथ चल रहे स्टेट बैंक के विवाद को हल कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) तथा (ख). कठिनाई-ग्रस्त कपड़ा मिलों को ऋण देने के बारे में एक ओर स्टेट बैंक और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार के बीच कोई विवाद नहीं है । सम्बद्ध मिलों की वित्तीय स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक सूती कपड़ा मिलों को ऋण देता है ।

कोयला खानों का आधुनिकीकरण

4127. **श्री मधु लिमये :** **श्री ब० कु० दास :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण चौथी योजना में कोयला खानों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को समाप्त करने का है अथवा उसे कम करने का है;

(ख) क्या आधुनिकीकरण की इन परियोजनाओं के लिए कोई सहायता मांगी जा रही है; और

(ग) इसके बारे में विभिन्न देशों ने क्या उत्तर दिया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) नये खनन यंत्रों की आवश्यकताओं के

अधिकांश के देश में ही उपलब्ध होने के कारण विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों से कोयला खानों के नवीकरण के रुकने की सम्भावना नहीं है। विदेशी मुद्रा देने के लिए तभी विचार किया जाता है जब यंत्र ऐसे हों जिन्हें आयात करना पड़े और वह नितांत आवश्यक है।

(ख) नहीं, महोदय।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बस्तर में रेलवे लाइनों का विकास

4128. **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री मधु लिमये :

श्री लखमू भवानी :

क्या **रेलवे** मंत्री बस्तर तथा उसके आस-पास के आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे विकास के लिए तैयार किया गया कार्यक्रम सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे और यदि अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): बस्तर और आस-पास के आदिवासी क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए अभी तक कोई विशिष्ट योजना नहीं बनाई गयी है। दंडकारण्य क्षेत्र में उद्योगों के समेकित विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों के सन्दर्भ में कुछ नयी रेलवे लाइनें बनाने के लिए छानबीन की जा रही है। चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए बहुत थोड़ी रकम निर्धारित किये जाने के कारण यह कहना असामयिक होगा कि लौह अयस्क के निर्यात, बन्दरगाहों के विकास और देश की परिवहन प्रणाली के सामरिक महत्व से सम्बन्धित अन्य योजनाओं की तुलना में इन रेलवे लाइनों को कितनी प्राथमिकता दी जायेगी।

जगदलपुर में कताई मिल

4129. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों की गिरती हुई दशा तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टि में रखते हुए जगदलपुर में शीघ्र कताई मिलों की स्थापना करने के लिए कोई विशेष उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों में उत्पादन कब आरम्भ होने लगेगा;

(ग) इन मिलों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(घ) आदिवासियों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) से (घ). उद्योग पुनस्संस्थापन निगम लि० कलकत्ता ने, जो कि श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के

अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जगदलपुर में, इस क्षेत्र का विकास करने तथा दण्डकारण्य में पुनर्वसित पूर्वी पाकिस्तान के प्रवासियों को रोजगार देने के दोहरे उद्देश्य से सूत कातने की एक मिल स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके अनुसार जगदलपुर में 25,000 तकुओं वाली सूत कातने की एक नई मिल स्थापित करने के लिए, निगम को, एक औद्योगिक लायसेंस दिनांक 9-9-65 को प्रदान किया गया था। मिल के स्थापित हो जाने तथा उत्पादन करने लगने पर सभी वर्गों के लगभग 963 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा।

2. किन्तु ज्ञात हुआ है कि निगम के निदेशक मण्डल की पिछली बैठक में कुछ समय के लिए इस प्रायोजना को और आगे न बढ़ाने का निर्णय किया गया है। निगम द्वारा किये गए इस निर्णय सम्बन्धी ब्योरे की प्रतीक्षा की जा रही है और उसके मिल जाने पर सरकार मामले पर और आगे विचार करेगी।

निर्यात संवर्धन पुरस्कार

4130. **श्री मौर्य :** **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री बागड़ी : **श्री मोहम्मद कोया :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 6 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1528 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन पुरस्कार आरम्भ करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) "विशिष्ट निर्यात सम्पादन के लिए सार्वजनिक मान्यता पुरस्कार" नामक योजना का मसौदा वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा बनाया गया है और इस पर सम्बद्ध अधिकारियों की सहमति ली जा रही है।

(ख) योजना की मुख्य रूपरेखा, 6 मई, 1966 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० 1528 के संदर्भ में सदन की मेज पर रखी गयी टिप्पणी में दी जा चुकी है।

पूना-मिरज मालगाड़ी का पटरी से उतरना

4131. **श्री मौर्य :** **श्री तुलाराम :**
श्री बागड़ी : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री कपूर सिंह :**
श्री सोनावने : **श्री बूटा सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 मई, 1966 को मिरज से पूना जा रही एक मालगाड़ी

पटरी से नीचे उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का क्या कारण था;

(ग) जान और माल का अनुमानतः कितना नुकसान हुआ; और

(घ) क्या इस दुर्घटना की जांच करने का कोई आदेश दिया गया है; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) 28-5-1966 को मिरज से पूना जाते हुए कोई अप मालगाड़ी दुर्घटना-ग्रस्त नहीं हुई । लेकिन, उस दिन जब एक डाउन मालगाड़ी पुरसंगी और आलन्दि स्टेशनों के बीच जा रही थी तो उसका एक डिब्बा पटरी से उतर कर अपने आप पटरी पर फिर से चढ़ गया ।

(ख) और (घ). जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 360 रुपये की हानि का अनुमान है । किसी की मृत्यु नहीं हुई ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कच्चे पानी की कमी

4132. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लोको शेडों में कच्चे पानी की कमी हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । लेकिन असाधारण रूप से सूखा पड़ने के कारण जब यमुना नदी में पानी की सतह नीची हो गयी थी तो उस समय पम्पिग स्थल पर गन्दा पानी आजाने से लोकोशेड को सप्लाई किया जाने वाला बिना छना पानी कुछ दूषित हो गया था ।

(ख) लोकोशेड सहित नयी दिल्ली की रेल आवश्यकताओं के लिए नल-कूप का पानी सप्लाई करने के उद्देश्य से द्वितीय यमुना रेलवे पुल के आर-पार रेलवे के अपने नल-कूपों की व्यवस्था करने की योजना पर विचार किया जा रहा है ।

तार बनाने वाला दूसरा कारखाना

4133. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केबल्ज लिमिटेड भूमिगत तार बनाने के लिए एक

दूसरा कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यह नया कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) क्या परियोजना का कार्यक्रम और प्राक्कलन तैयार कर लिए गये हैं और यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना व्यय किया जायेगा और इसकी क्षमता क्या होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) 8,000 किलो मीटर प्रति वर्ष ड्राई बोर केबिल बनाने की परियोजना पर लगभग 996 लाख रु० (बस्ती को निकाल कर) लागत आने का अनुमान है ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल में बेकार पड़ी क्षमता

4134. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल की बेकार पड़ी क्षमता को प्रयोग में लाने का कोई प्रयास किया गया है ;

(ख) इस क्षमता का प्रयोग करने के लिए कहां से आर्डर प्राप्त किये गये हैं ; और

(ग) इस बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग कितनी देर तक नहीं किया गया तथा क्या इस कारण कोई नुकसान हुआ है ।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) रेलवे रक्षा प्रतिष्ठान तथा अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठन ।

(ग) हैवी इलैक्ट्रिकल्स भोपाल जैसे उद्योगों को पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक का समय लगता है । यह दीर्घ अवधि उन उत्पादों के मिले जुले और पेचीदा होने के कारण लगती है और वस्तुतः देश में इनका उत्पादन पहली बार ही किया जा रहा है । उत्पादन का क्रमिक विकास होने में आंशिक रूप से फालतू क्षमता के अवसर आ जाते हैं । इस कारण यथासंभव जहां तक इनके उपयोग किये जाने का सम्बन्ध है कोई विशेष हानि नहीं हुई है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यालय में आग लगने की घटना

4135. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मई, 1966 को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लेखा कार्यालय में

आग लग गई थी ;

(ख) क्या कुछ फाइलें तथा दस्तावेज जल गये थे तथा क्या इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई थी ;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यकरण की जांच करते समय कुछ कागज पकड़े हैं तथा कुछ और कागज मांगे हैं ; और

(घ) क्या आग लगने की घटना का केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की जा रही जांच से किसी प्रकार का सम्बन्ध है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय। लेखा कार्यालय के एक कमरे में थोड़ी आग लग गई थी ;

(ख) हां, महोदय। कुछ फाइलें तथा कागजात जल गये थे। इसकी रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई थी ;

(ग) केन्द्रीय जांच विभाग राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के मामलों की ऐसी कोई जांच नहीं कर रहा। यह मामला विशेष पुलिस स्थापना द्वारा निगम के मुख्य सतर्क अधिकारी के परामर्श से किये जा रहे मामलों से अलग है। अत: केन्द्रीय जांच विभाग के द्वारा कुछ कागज पकड़े जाने तथा इस प्रसंग में और मांगे जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) नहीं, महोदय।

इण्डियन इंजीनियरिंग वर्क्स, इन्दौर

4136. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन इंजीनियरिंग वर्क्स, इन्दौर में सरकार ने कितना धन लगाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस फर्म ने चार वर्षों में केवल सात मेज के पंखे बनाये हैं जबकि इसी अवधि के लिए उसकी निर्धारित क्षमता सात हजार से अधिक की है ; और

(ग) क्या सरकारी धन के इस अत्यधिक अपव्यय के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

पंचकुड़ा-हल्दिया लाइन

4137. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचकुड़ा-हल्दिया लाइन बनाने के काम की गति धीमी हो गयी है ?

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पंचकुड़ा से हावड़ा तक तीसरी लाइन का निर्माण-कार्य भी उसी तरह धीमी गति से चल रहा है ; और

(घ) निर्माण कार्य की ऐसी स्थिति कब तक चलती रहेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). जी नहीं। यह लाइन हल्दिया के नये बन्दरगाह और वहां स्थापित होने वाले उद्योगों की सेवा करने के लिए है और रेलवे इस लाइन के निर्माण को इस तरह चरण-बद्ध कर रही है ताकि यह काम हल्दिया बन्दरगाह प्रायोजना के पूरा होने के साथ ही पूरा हो।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

बिजली के सामान के दाम

4138. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में बिजली के सामान के दाम 20 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो जून 1966 के अन्त तक की अवधि में दामों में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). बिजली के सामान के मूल्यों जैसे बिजली के बल्ब (लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि), बिजली के छोटे बल्ब (25 प्रतिशत वृद्धि), बल्बों के पीतल के होल्डर (40 प्रतिशत वृद्धि), स्टोरेज बैटरियां (25 प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत वृद्धि), सूखी बैटरियां (35 प्रतिशत बढोतरी) घरों में लगने वाले बिजली के तार (17 प्रतिशत से लेकर 22 प्रतिशत वृद्धि) हुई है। रेडियो रिसीवरों, बिजली के पंखे, तथा बिजली के घरेलू साज-सामान के मूल्य में 7 प्रतिशत से लेकर 17 प्रतिशत तक का अन्तर है। स्टोरेज तथा सूखी बैटरियों के मामले में 1964 की तुलना में 30 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक की वृद्धि

हुई है तथा सितम्बर, 1965 के बाद मूल्य लगभग स्थिर रहे हैं। कुछ मामलों जैसे बैटरियों पर आयात कर में वृद्धि कर देने तथा बराबर करने के लिए सीसे पर जो एक आधारभूत कच्चा माल है, शुल्क लगा देने के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है। इन सभी उद्योगों पर कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, आयात शुल्क वृद्धि, वेतनों तथा पैकिंग इत्यादि में वृद्धि हो जाने के कारण उनकी उत्पादन लागत भी बढ़ गई है।

अम्बोडला स्टेशन के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतरना

4139. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जून, 1966 को दक्षिण रेलवे के रायपुर-विजयानगरम सेक्शन में अम्बोडला और दोइकाही स्टेशनों के बीच एक पुल पर एक मालगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 10.6.66 को अम्बोडला और डोयकल्लु स्टेशनों के बीच पुल नं० 448 से जरा पहले किलोमीटर 267/11-12 पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गयी।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) अनुमानत: 1,80,000 रुपये।

काश्मीर में पोदार नीलम की खानें

4140. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतत्वविदों के एक दल ने काश्मीर में पोदार नीलम की खानों का पता लगाया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु०कु० डे) : (क) से (ग). भारतीय भौमिकी विभाग के पास प्राप्त सूचना के आधार पर पोदार नीलम खानों का अन्वेषण 1961 में जे० एण्ड के० सरकार के भौमिकी तथा खनन विभाग के भौमिकी विज्ञों ने किया था। 1964 और 1965 में जे० एण्ड के० मिनरल्स लि० के भौमिकी विज्ञों के एक समूह ने इनकी आगे जांच की। जे० एण्ड के० सरकार ने खानों को खोदकर कुछ नीलम कोरडम प्राप्त किया है तथा इसका विस्तृत पैमाने पर अन्वेषण कार्य करने के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

1966-67 के क्षेत्रीय काल में भारतीय भौमिकी विभाग का विचार इन खानों के अन्वेषण करने का है।

खनिज सलाहकार बोर्ड

4141. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर में खनिज सलाहकार बोर्ड की एक बैठक 21 जून, 1966 को हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) बोर्ड द्वारा मुख्य सिफारिशों का विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-7008/66]

Drinking Water at Raiwala Junction

4142. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no facilities for drinking water and no arrangement of water in the quarters of railway employees at Raiwala Junction Station on the Northern Railway between Hardwar and Dehra Dun ;

(b) whether it is also a fact that close to the station, a stream flows from where water can be provided at the station at a small expenditure ; and

(c) when a final decision is likely to be taken for making proper arrangements of water at such an important junction station ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. Drinking water is being supplied to staff by means of mobile water tanks.

(b) There is a stream about 1½ miles away from the Station. The expenditure that would have to be incurred for arranging supply of water from this stream to the Station would be very heavy, and not commensurate with the very small requirement of drinking water at this station.

(c) The existing arrangements are considered satisfactory for the present.

भदोही (उत्तर रेलवे) में इंजन का पटरी से उतरना

4143. **श्री किन्दर लाल :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री बड़े : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जून, 1966 को इलाहाबाद से लगभग 60 मील दूर झंगई-वाराणसी सेक्शन में भदोही नामक स्थान पर एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) रेलवे सम्पति की कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण गाड़ी पटरी से उतर गयी थी ।

(ग) रेल सम्पति को लगभग 350 रुपये का नुकसान हुआ ।

(घ) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराये गये कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन सम्बन्धी उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है ।

प्रस्फोटकों के संदूकों का लूटा जाना

4144. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जून को पंचेट बांध के पास एक बारूदघर से कोयला खान में काम आने वाले प्रस्फोटकों के 26 संदूक लूट लिये गये थे ;

(ख) क्या इनका पता लगा लिया गया है ; और

(ग) क्या गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) 18-6-1966 (रात्रि) को कोयला खनन कार्य में प्रयोज्य डिटोनेटरों की 26 पेटियों के पंचेट मैगनीन से लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई ।

(ख) 19 पेटियां बरामद की जा चुकी हैं । मामले की जांच चल रही है ।

(ग) पुलिस ने अभी तक पांच गिरफ्तारियां की हैं ।

भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार

4145. **श्री बृजबासी लाल :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और यूगोस्लाविया के बीच व्यापार के बारे में बातचीत करने के लिए यूगोस्लाविया का एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल हाल में नई दिल्ली आया था ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला है और यदि कोई व्यापार करार किया गया है, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). जी, हां। बातचीत मुख्यतया अवमूल्यन के बाद उठाये जाने वाले कदमों के बारे में थी। बातचीत के अन्त में जिस संलेख पर हस्ताक्षर किये गये उसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

चोर बाजार में कार का पुनः विक्रय

4146. **श्री गुलशन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थान के एक पुलिस सुपरिन्टेंडेंट ने सरकारी कोटे से कार खरीदने के एक वर्ष के अन्दर चोर बाजार में अपनी कार बेच दी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार

4147. **श्री जसवंत मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली जुलाई में हुई प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार की बैठक में कैनेडी राउण्ड प्रशुल्क बातचीत की प्रगति के बारे में भारत के प्रतिनिधियों ने असंतोष व्यक्त किया;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). जी, हां। कैनेडी राउण्ड टैरिफ वार्ता की प्रगति की समीक्षा हेतु जेनेवा में 8 जुलाई, 1966 को हुई व्यापार वार्ता समिति की

बैठक में गाट में भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने, अल्प विकसित देशों की व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के क्षेत्र में प्रगति न होने पर अपनी निराशा व्यक्त की । उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि विकसित देशों के प्रतिनिधि मण्डल अल्प विकसित देशों के लिए निर्यात के अवसर बढ़ाने के ठोस प्रस्ताव करेंगे ।

भारवारी स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर लूट की घटना

4148. **श्री बृजबासी लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जुलाई, 1966 को आधी रात के करीब 72 डाउन पार्सल एक्सप्रेस जब भारवारी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तो कुछ सशस्त्र व्यक्तियों ने, जो उसी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, एक यात्री के बटुवे को छीना और उसको तथा उसके एक मित्र को छुरा मारा और रेलवे के डिब्बे से उसके मित्र को उठा ले गये; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

सारवडी और जालना स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतरना

4149. **श्री बृजबासी लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जुलाई, 1966 को मध्य रेलवे के पूना-मनमाड सेक्शन के सारवडी और जालना स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के चार डिब्बे पटरी से उतर गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) इससे रेलवे की सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) दो माल डिब्बे पटरी से उतर गये, चार नहीं ।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

(ग) लगभग 9,440 रुपये की ।

चक्रधरपुर डिवीजन में छंटनी

4150. **श्री ह० च० सोय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मितव्ययता करने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेलवे

डिवीजन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भारी संख्या में छँटनी की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से बिना किसी आराम अथवा अवकाश के बारह घण्टे तक काम लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य गिर रहा है और कार्य-कुशलता का ह्रास हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अन्य अनावश्यक खर्चों को कम करके मितव्ययता करने तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की छंटनी न करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का प्रयास

4151. **श्री पन्नालाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजबासी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कमालगंज तथा फतेहगढ़ स्टेशनों के बीच 23 जुलाई, 1966 की रात को 13 अप लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का प्रयास ड्राइवर की सतर्कता के कारण विफल हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं । वस्तु स्थिति यह है कि 24-7-1966 को 13 अप एक्सप्रेस गाड़ी के ड्राइवर ने कमालगंज और फतेहगढ़ के बीच समपार नं० 135-सी के पास रेलवे लाइन पर 6 फुट 9 इंच लम्बा पटरी का एक टुकड़ा पड़ा देखा । पुलिस की जांच से पता चला है कि वह टुकड़ा समपार नं० 134 के पास पटरी के टुकड़ों के पुराने स्टाक से, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चुराया गया था, जिसे वे रेलवे लाइन पर छोड़ गये थे । वरिष्ठ रेल अधिकारियों की संयुक्त जांच समिति भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह तोड़-फोड़ की कोशिश नहीं बल्कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी का मामला है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अधीन पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और उसकी जांच कर रही है । समपार नं० 134 के गेटमैन के विरुद्ध कर्त्तव्य की उपेक्षा करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है ।

Shortage of Photographic Paper

4152. **Shri Bade .** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh**

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a shortage of photographic paper in the country ;

(b) if so, the annual value of photographic paper which is imported from abroad ; and

(c) the measures being adopted to cope with this problem ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) Yes, Sir.

(b) The value of actual imports of photographic paper during the last three years is as under :—

Year	Value (Rs./lakhs)
1963—64	48.69
1964—65	41.55
1965—66	20.45

(c) To meet the shortage of photographic paper in the country, it has been decided as a short term measure to import photographic paper worth Rs. 10 lakhs from Rupee area through the State Trading Corporation. As a long term measure, in addition to existing manufacturing units, M/s. Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Ltd., Ooty (Madras) (a public sector undertaking) are expected to install a capacity of 1·5 million sq. metres of photographic paper during next year. The value of their production would be about Rs. 60 lakhs.

Paper Mill at Bareilly

4153. **Shri Bade :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government propose to establish a paper mill at Bareilly or Kichha ;

(b) if so, when work thereon would be taken up ; and

(c) the value of machinery Government will have to import from abroad ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Production at Bhilai Steel Plant

4154 **Shri Bade :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that by starting the Third Shift in Bhilai Steel Plant, the target of production for each department has been raised but the production has come down from

60-70 to 20-30 per cent. which is affecting the bonus being received by the labourers and there is dissatisfaction among labourers on that account ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) (a) and (b). As a result of the commissioning of the 2.5 million tonne plant units at Bhilai, the availability of steel has increased. Following this, the Rail and Structural Mill and the Merchant Mill were put on three shift working earlier this year. The other production units were already on three shift working. Again, with the commissioning of the 2.5 million tonne plant units, production targets for incentive purposes have had to be revised; but care has been taken to evolve realistic targets which have been accepted by the representative Union.

Due to unfavourable market conditions, there has recently been a decline in the orders for certain products of Bhilai which has affected production and incentive earnings in certain Departments.

Export of Bhilai Steel Plant Products

4155 **Shri Bade :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of foreign countries have reduced their imports from India because of the inferior type of iron used at Bhilai Steel Plant ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether there is some thing wrong in the rail structural mill also and that Bhilai rails have been regarded inferior in India and abroad ; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) No, Sir. On the other hand, exports from Bhilai have increased from Rs. 3.95 million in 1964-65 to 14.65 million in 1965-66.

(b) Does not arise.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

नेपाल का प्रतिनिधि मण्डल

4156. **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नेपाल के एक सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधि मण्डल के साथ किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) यदि उनके साथ कोई समझौता हुआ तो क्या ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्धी मामलों पर वार्ता करने के लिए नेपाल सरकार के स्थानापन्न वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल अगस्त, 1966 के प्रथम सप्ताह में भारत आया था। इस वार्ता के पश्चात् 6 अगस्त, 1966 को जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-7009/66]**

दियासलाई के दाम

4157. **डा० रानेन सेन :** **श्री बदरुद्दुजा :**
डा० उ० मिश्र : **श्री ह० प० चटर्जी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न किस्मों की दियासलाई, जिनमें से कुछ पर मूल्य अंकित होता है और कुछ पर नहीं, व्यापारियों द्वारा बाजार में मुंह मांगे दामों पर बेरोकटोक बेची जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). दियासलाई की कीमतों तथा वितरण पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। फिर भी, यंत्रीकृत तथा गैर-यंत्रीकृत, दोनों क्षेत्रों में दियासलाई के निर्माताओं के लिए केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली के अधीन दियासलाइयों की डिब्बियों पर खुदरा कीमत छापना आवश्यक है। नियमों की अवहेलना दण्डनीय है। देश के विभिन्न भागों से दियासलाई के अभाव तथा ऊँची कीमतों की सूचनाएं प्रायः मिलती रहती हैं और ऐसे क्षेत्रों में शीघ्र सम्भरण करने के प्रयास किये जाते हैं। पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए दियासलाई उद्योग को 59 प्राथमिकता उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

घड़ियों का निर्माण

4158. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **उद्योग** मंत्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 957 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घड़ियों के निर्माण में स्विटजरलैण्ड तथा रूस के सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को इस बीच अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसमें कब निर्माण आरम्भ होने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

आसाम में ऐसी चट्टानों का मिलना जिनमें सोना मिलता है

4159. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री पन्नालाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजबासी लाल :
श्री लखमू भवानी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खासी तथा जैन्तिया पहाड़ी जिलों के माफ्लोंग क्षेत्र में ऐसी चट्टानों का पता लगा है, जिनमें सोना मिलता है;

(ख) यदि हां, तो ये चट्टानें किस प्रकार की हैं और कितनी हैं; और

(ग) इन चट्टानों से सोना निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (ग). आसाम सरकार से पता चला है कि खासी और जैन्तिया के पहाड़ी जिलों के माफ्लोंग क्षेत्र में सोना प्राप्त होने वाली जिन चट्टानों का पता चला है उनकी लम्बाई 8 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 30 से 350 मीटर तक अलग-अलग है । सोना उत्पादन करने वाले खनिज सम्भवतः टैलूराइड की प्राप्ति काल्क शिस्ट से पर्याप्त होती है । परिमाणुओं (सोना प्राप्त होने वाले) का माप अलग-अलग होता है। चट्टानों में सोने की मात्रा 1.2 डी डबल्यू टी (पैनी वेट) प्रति मीटरी टन से लेकर 0.1286 डी डबल्यू टी है । भूतल से प्राप्त नमूनों में सोने की मात्रा ऐसी है कि उसका खनन मित्तव्ययी नहीं है। तथापि आने वाले क्षेत्रीय काल में आसाम सरकार का प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र में कुछ छिद्र किये जायें ताकि पता लगाया जा सके कि इनके मूल्य में वृद्धि होती है या नहीं ।

Arrest of Dacoit at Bali Station Near Calcutta

4160. **Shri Bade :**
Shri Yudhvir Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang of dacoits was found breaking the location box at Bali station near Calcutta as reported in the "Hindustan" dated the 31st July, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that as a result of a clash with the Railway Protection Force, a dacoit was apprehended ;

(c) if so, the information gathered about the subversive activities of this gang ; and

(d) the action taken against that person ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Yes. Two criminals have been arrested so far in this connection.

(c) The intention of the criminals was apparently to steal the Railway equipment.

(d) The case is under police investigation.

चमन लाल एण्ड ब्रदर्स

4161. **श्री जसवन्त मेहता :** **श्री दलजीत सिंह :**

श्री भागवत झा आजाद : **श्री शिवचरण माथुर :**

श्री पालीवाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमन लाल एण्ड ब्रदर्स कम्पनी ने 1959 में मैगनीज के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम से वस्तु विनिमय समझौता किया था;

(ख) इस वस्तु विनिमय समझौते की क्या शर्तें थीं;

(ग) इस वस्तु विनिमय समझौते के अन्तर्गत कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(घ) इस कम्पनी को इस निर्यात के बदले में इस्पात तथा अन्य वस्तुओं के आयात संबंधी कितनी राशि के प्रोत्साहन लाइसेंस दिये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । राज्य व्यापार निगम ने मेसर्स चमन लाल के माध्यम से, इस्पाती सामान के बदले, 108.23 लाख रुपये के 74,200 मी० टन मैंगनीज अयस्क के कुल परिमाण के निर्यात के लिए संविदाएं की ।

(ख) मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिए मेसर्स चमन लाल ब्रदर्स को पक्की संविदाएं करनी थीं जिनके अन्तर्गत विदेशी खरीदारों को राज्य व्यापार निगम के पक्ष में पक्के ऋण पत्रों का प्रतिपादन करना था । ऋण पत्रों में भी इस आशय का एक चेतावनी खण्ड (रेड क्लाज) रखा जाना था कि यदि विदेशी खरीदार इस कार्य की घोषणा के बाद 60 दिन के अन्दर माल नहीं उठाते तो सम्भरणकर्ता को अधिकार होगा कि वह ऋण-पत्र को भुना सकेगा और खरीदारों से नोटिस खत्म होने की तिथि से लदान की तिथि तक माल को रखने और उसकी देखभाल करने के प्रभार मांग सकेगा । सन्तोषजनक ऋण पत्रों के प्रतिपादन के बाद, सम्पन्न संविदाओं के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के बराबर, अत्यावश्यक इस्पाती सामान के लिए आयात लाइसेंस जारी करने हेतु, राज्य व्यापार निगम द्वारा लौह तथा इस्पात नियंत्रक को आवेदन पत्र दिया जाना था । इस्पात का आयात अयस्क के निर्यात से पूर्व करने की अनुमति दी गई थी ।

(ग) जब 60.51 लाख रुपये के 38,797 मी० टन परिमाण का लदान हो गया तो विदेशी खरीदारों ने ऋण-पत्र की वैधता बढ़ाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की क्योंकि उनके बैंक चेतावनी खण्ड को सम्मिलित करने के लिए सहमत नहीं थे । इस पर चेतावनी खण्ड के बिना ऋण पत्रों को बढ़ाने के लिए और चेतावनी खण्ड के बदले शेष निर्यात के 15% के लिए बैंक गारण्टी देने को कहा गया । चूंकि पूरे मूल्य का निर्यात सम्पन्न न हो सका अतः 6.53 लाख रुपये की बैंक गारण्टियां जब्त कर ली गईं । उपर्युक्त सौदे के अन्तर्गत उपार्जित विदेशी मुद्रा की राशि 83.52 लाख रुपये थी ।

(घ) आयात का कुल मूल्य 94.31 लाख रुपये था । आयात की मदें, एच० वी० तार, नर्म इस्पात की चादरें, जी० पी० तथा वी० प० चादरें, बेदाग इस्पात और सिगनल जी० आई० तार थी ।

जस्ते की चादरों की मांग और पूर्ति

4162. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जस्ते की चादरों की मांग और पूर्ति के बारे में कोई मूल्यांकन कर लिया गया है और कितने कारखानों में जस्ते की चादरों का निर्माण हो रहा है, उनकी क्षमता कितनी है और इस समय कितना निर्माण हो रहा है;

(ख) क्या इन चादरों के वितरण पर सरकार का कोई नियंत्रण है, और यदि हां, तो किस प्रकार का नियंत्रण है;

(ग) क्या यह सच है कि ब्लाक बनाने वाले उद्योग को उचित मूल्य पर जस्ते की चादरें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलतीं और यदि हां, तो क्या इस बारे में, विशेषतः निर्माताओं के कुछ एजेण्टों द्वारा की गई चोर-बाजारी की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(घ) ब्लाक बनाने वालों को जस्ते की चादरों का समुचित सम्भरण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) यद्यपि देश के विभिन्न इंजीनियरी उद्योगों द्वारा अपेक्षित जस्ते की चादरों, पत्तियों और प्लेटों के बारे में कुल मांग का कोई निश्चित निर्धारण नहीं किया गया है, तो भी टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट से यह पता लगा है कि मुद्रण उद्योग में इस्तेमाल होने वाली अत्यधिक पालिश हुई जस्ते की चादरों की मांग का ब्योरा निम्नलिखित है :—

1964-65	420 टन
1965-66	480 टन
1966-67	525 टन

केवल एक ही यूनिट इस उद्योग में लगा है । 1964 और 1965 में बैटरी निर्माण के लिए औसत 4250 टन जस्ते की पत्तियों और मुद्रण उद्योगों के लिए औसत 250 टन फोटो एंग्रेवर प्लेटों का निर्माण किया गया था । संयंत्र के अधिकतम उपयोग के आधार पर द्वितीय मद के 600 टन के निर्माण की क्षमता का हिसाब लगाया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मुद्रण उद्योग में ब्लाक बनाने के लिए जस्ते की प्लेटों (अत्यधिक पालिश हुई जस्ते

की चादरों) के कम मात्रा में मिलने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। परन्तु, चोर-बाजारी का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है।

(घ) ब्लाक बनाने वालों को अत्यधिक पालिश हुई जस्ते की चादरों की जितनी जरूरत है उसकी कमी को पूरा करने के लिए, खनिज और धातु व्यापार निगम से इस उद्योग में लगे हुए एकमात्र यूनिट को आवंटित किये गये जस्ते में से 525 टन की मात्रा अत्यधिक पालिश हुई जस्ते की चादरों के निर्माण के लिए सुरक्षित की जा रही है।

प्याज का निर्यात

4163. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री लंका के साथ भारत का प्याज निर्यात व्यापार समाप्त होने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य देशों को प्याज का निर्यात करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें अन्य देशों को किये गये निर्यात का मूल्य दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-7010/66]

Import of Fish and Rice from Pakistan

4164. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan have stopped exporting rice and fish to India ;

(b) If so, the articles which India has stopped exporting to Pakistan as a mark of protest ; and

(c) the reasons stated by Pakistan for discontinuing the export of these articles ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c). As a result of Indo-Pakistan Conflict, trade with Pakistan was banned with effect from 10th September, 1965. This ban was lifted by us unilaterally on 27th May, 1966, in pursuance of the Tashkent Declaration. Similar action has not, however, so far been taken by the Government of Pakistan who had also banned trade with India.

Construction of Railway Hospital at Lalgarh

4165. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether stone-lime was used in any work on the Northern Railway in Bikaner city before 1933 ;

(b) whether stone-lime is being brought from Gotan and used in the Railway Hospital under construction at Lalgarh since 1964 although Kankar lime, also called as hydraulic lime, is available in plenty ;

(c) whether Kankar lime is less durable than stone-lime ; and

(d) the difference between the rates of stone-lime and hydraulic lime ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) It is regretted that no information is available regarding the use of stone lime before 1933.

(b) No lime has been used for the construction of Hospital at Lalgarh. However, stone lime from Gotan was used in the construction of staff quarters at Lalgarh under the same contract as the Kankar lime locally available was felt to be not of acceptable quality.

(c) The relative durability of Kankar lime and stone lime depends entirely on the quality of the raw materials.

(d) According to the Northern Railway Schedule of rates 1955 for Bikaner Division, the difference between the rates of stone lime and kankar lime is Rs. 82.50 per 100 cft.

Industries in Jaipur

4166. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the nature of industries which have been set up in Jaipur and for which licences were given by Government during the last 3 years ; and

(b) the names of partners in those industries ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-7011/66].**

Railway Line Between Hindumalkote and Sri Ganga Nagar

4167. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 500 on the 12th. November, 1965 and state the progress since made in laying the broad gauge line between Hindumalkote and Sri Ganga Nagar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : The State Government have since undertaken earthwork in formation and the progress achieved for this item of work is 25%. According to the conditions on which this project was sanctioned,

the State Government are also to provide through 'Shramdan' skilled and unskilled labour for construction of quarters, station buildings and platforms. The State Government have as yet drawn no plans for making 'Shramdan' available for this purpose.

Manufacture of X-Ray Appliances

4168. **Shri Dhuleshwar Meena :**
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the price of each of the big and small X-Ray Appliances manufactured by the Escorts Company of Delhi ;

(b) whether it is a fact that the appliances manufactured by this Company are entirely useless and are lying idle in every hospital to which they were supplied ; and

(c) the reasons for giving incentives to this company even in these circumstances ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-7012/66].**

(b) Government have not received any complaints as such from any of the hospitals regarding these appliances supplied by M/S. Escorts. However, a reference from a local hospital indicated that one of the X-Ray tubes supplied by this firm was not functioning. This tube had actually been used for more than a year. This tube was replaced free of cost by the firm even though there was no guarantee for these highly vacuumatic X-Ray tubes.

(c) Does not arise.

व्यापार बोर्ड (बोर्ड आफ ट्रेड)

4169. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बोर्ड ऑफ ट्रेड--फंक्शंज एण्ड ऐक्टिविटीज 1962-66" नामक प्रकाशन आयातीत आर्ट पेपर पर छापा गया है;

(ख) क्या इस प्रकाशन की कुछ प्रतियां भारत से बाहर बांटी गई हैं और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) कितने आर्ट पेपर का प्रयोग किया गया है तथा उसकी लागत कितनी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । वस्तु-विनिमय व्यापार के अन्तर्गत आयातित पूर्वी जर्मनी के कागज पर ।

(ख) जी, हां । विदेश स्थित व्यापार मिशनों और भारत सूचना केन्द्रों के द्वारा 600 से अधिक प्रतियां वितरित की जा चुकी हैं । विदेशों से मांग आने पर अतिरिक्त प्रतियां भेजी जा रही हैं ।

(ग) 31 रीमें, जिनका बिक्री कर सहित मूल्य 3,800 रुपये था ।

पश्चिमी बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना

4170. **डा० रानेन सेन :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पश्चिमी बंगाल की छः कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-7013/66**]

Export of Steel Goods to Iran

4171. **Shri Y. D. Singh :** **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Kashi Ram Gupta :**
Dr. L. M. Singhvi :

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a greater demand for Indian Steel goods in Iran;

(b) if so, the action taken by Government in this connection ; and

(c) the quantity of goods exported so far ?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) All possible assistance is given to exporters for export of steel. A Government sponsored delegation of officers from the Hindustan Steel Ltd. has visited Iran recently to explore markets for Rails and other steel items.

(c) Following quantities of steel have been exported to Iran :—

Year	Quantity in M/T
1964-65	6504
1965-66	7318
1966-67 (upto 22.8.66)	21365 (licences issued)

Railway Fireman in Varanasi

4172. **Shri Y. D. Singh :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade : **Shri L. M. Singhvi :**
Shri Kashi Ram Gupta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a seniority list of Firemen in Varanasi District has been

published in which there are several irregularities;

(b) whether certain persons were promoted arbitrarily against which letters of complaints have also been sent to the Railway Administration;

(c) whether it is also a fact that with a view to giving promotions to certain persons they have been sent for shunter's training; and

(d) if so, the action taken against the Officers who have taken such wrong steps?

She Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A provisional seniority list of Firemen Grade II showing position as on 1-4-1966 was circulated on 4-6-1966 and staff were asked to submit representations, if any, against their position in the provisional seniority list. Representations so received are under examination.

(b) No.

(c) No.

(d) Does not arise.

ओवलटीन का उत्पादन

4173. **श्री किशन पटनायक :**
श्री शिंकरे :
श्री मधु लिमये :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
डा० सारादीश राय :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री राम सेवक यादव :
श्री तु० राम :
श्री म० ना० स्वामी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री बड़े :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के एक सार्थ तथा ब्रिटेन के मेसर्स ए० वंडर लिमिटेड के बीच किसी करार के अन्तर्गत भारत में ओवलटीन का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत सहयोग की शर्तों के अनुसार विदेशी कम्पनी ओवलटीन के उत्पादन के लिए भारतीय कम्पनी को सभी तकनीकी जानकारी और भावी अनुसन्धान और विकास के लाभ प्रदान करेगी तथा इंगलैण्ड में स्थित अपने कारखाने में तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करेगी। इसके अलावा वह भारतीय कम्पनी को उपकरणों को लगाने, उत्पादन के निर्माण तथा वितरण, के मामले में परामर्श भी देगी। विदेशी कम्पनी भारतीय कम्पनी को कई देशों के लिए निर्यात का अधिकार भी देगी। उपर्युक्त सेवाओं की एवज में विदेशी कम्पनी को

कारखाने से चलते समय के विक्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत (कर देय) पारिश्रमिक दिया जायगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने यह नोट कर लिया है कि भारतीय कम्पनी कम से कम पारिश्रमिक दी जाने वाली राशि अपने उत्पादों 'ओवलटीन' 'माल्ट', माल्ट-एक्ट्रैक्ट तथा अपनी उत्पादन सीमा के अन्तर्गत अन्य वस्तुओं का निर्यात करके आवश्यक विदेशी मुद्रा कमा लेगी।

भूतत्वीय कार्यक्रमों सम्बन्धी बोर्ड

4174. **श्री पन्नालाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजवासी लाल :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतत्वीय कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार का विचार एक भूतत्वीय कार्यक्रमों सम्बन्धी बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). भौमिकी कार्यक्रम बोर्ड की स्थापना 27 जुलाई, 1966 को की गई थी।

(ग) बोर्ड का कार्य लगातार चलने वाला होगा। व्यय मुख्य रूप से इसके सदस्यों के यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के रूप में होगा जो कि अधिकतर राज्य सरकारों और संस्थाओं द्वारा किया जायगा जिनका कि वे प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए कुल व्यय का अनुमान नहीं दिया जा सकता।

साइकिल टायरों की कमी

4175. **श्री लखमू भवानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साइकिल टायरों की अत्यधिक कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). देश में इस समय साइकिल टायरों की कोई कमी नहीं है। साइकिल टायरों का मौजूदा उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। 196 लाख अदद प्रतिवर्ष की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता के अलावा 29 लाख अदद तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये हैं और 15 कारखानों को 196 लाख अदद की और अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए संबंधित

आशय पत्र भी जारी कर दिये गये हैं । इस प्रकार कुल स्थापित क्षमता 421 लाख अदद प्रतिवर्ष हो जायगी जिससे चौथी योजना अवधि के अन्त तक की मांग पूरी हो जाने का अनुमान है ।

फिर भी साइकिल टायरों के एक विशेष ब्रांड के लिए उपभोक्ता की विशिष्ट पसन्द है । इसलिए इस विशिष्ट ब्रांड की कमी की शिकायतें पैदा हो गई हैं । स्पष्ट है कि साइकिल टायरों का एक उत्पादक देश की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता ।

सुपारी का आयात

4176. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत दूसरे देशों से सुपारी का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1965-66 में कितना आयात किया गया; और

(ग) सुपारी के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1965-66 के दौरान 16·1 लाख रु० मूल्य की 2,629 मी० टन कटी हुई तथा 4·36 लाख रु० मूल्य की 694 मी० टन साबित सुपारी की कुल मात्रा आयात की गई ।

(ग) सुपारी का उत्पादन बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक विभिन्न उपाय किये गये हैं जिनमें पौधशालाओं की स्थापना, प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था करना, सिंचाई की बेहतर सुविधा, उर्वरकों तथा खादों का प्रयोग करना, पौधों के संरक्षण के उपकरणों एवं रसायनिक पदार्थों का वितरण तथा प्रकाशन और प्रचार शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, केरल, मैसूर तथा आसाम के कुछ अनुकूलतम जिलों में सुपारी पैक करने का कार्यक्रम संगठित करने का भी प्रस्ताव है ।

दिल्ली में सुपर बाजार

4177. **श्री फ० गो० सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के विभिन्न भागों में सुपर बाजार खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). सुपर बाजार खोलने के निर्णय सहकारी थोक भण्डारों द्वारा किये जाते हैं जो कि सरकारी प्रायोजित संगठन हैं । जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है कनाटप्लेस के क्रमशः भीतरी तथा बाहरी चक्करों में पहले से ही खोले गये सुपर बाजार तथा सहकारी भण्डार के अतिरिक्त चान्दनी चौक, आई० एन० ये० मार्केट, रामकृष्णपुरम और प्रस्तावित जिला बाजार केन्द्र, पूसा रोड में भी ऐसे ही भण्डारों की स्थापना करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

खेतरी परियोजना में उत्पादन

4178. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतरी तांवा परियोजना विद्युत विश्लेषिक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रयोग के लिए तांबे का उत्पादन कब आरम्भ करेगी;

(ख) प्रत्याशित वार्षिक उत्पादन क्या है और यह किस हद तक मांगों को पूरा करेगा; और

(ग) क्या रूसियों ने राखा तांबा परियोजना के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दे दिया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) आशा है 1969-70 में खेतरी से विद्युदांशिक तांबे का उत्पादन होने लगेगा ।

(ख) परियोजना के पूर्ण क्षमता ग्रहण कर लेने पर आशा है कि उत्पादन 31,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष होने लगेगा ।

चौथी योजना के अन्त तक (1970-71) में तांबे के 2,50,000 मी० टन की आवश्यकता का अनुमान है । इसमें से लगभग 12.4 प्रतिशत खेतरी तांबा परियोजना से पूरी की जायगी ।

(ग) 1965 में दो रूसी दलों ने राखा का निरीक्षण किया । पीछे जून में दी गई रिपोर्ट में उन्होंने भौमिकी अन्वेषण का सुझाव दिया है । अन्वेषण का एक कार्य-क्रम सरकार के विचाराधीन है ।

सिमरा में कपड़ा मिलें

4179. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा समाचार मिला है कि मैसर्ज बिड़ला ब्रादर्स ने, जिन्होंने सिमरा (करीमगंज-नेपाल) में आधुनिक ढंग का कपड़ा मिल लगाना था, निर्माण-कार्य स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय मुद्रा और नेपाली मुद्रा की विनिमय दर में हाल में हुए पुनरीक्षण के कारण प्रायोजना की लागत काफी बढ़ गई है । नेपाल सरकार के सम्बद्ध अधिकारियों के साथ इन प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

उड़ीसा में भूतत्वीय सर्वेक्षण

4180. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 के दौरान उड़ीसा में भूतत्वीय सर्वेक्षण के किसी कार्य-क्रम को

अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय ।

(ख) विवरण निम्न प्रकार हैं :—

गंजम, कालाहांडी, बौद्ध-फूलवाणी एवं संबलपुर जिलों में भौमिकी मानचित्रण तथा खनिज सम्बन्धी प्रारम्भिक अनुमान ।

कोरापुत में उमरकोट तथा कियोझर-सुन्दरगढ़ के मालंगटोली खण्ड में कच्चे लोहे के; कटक में सुकिन्दा तथा कियोझर में नौसाही में निकल के; वालंगीर और मयूरभंज में सीसे और जस्ते के; कोरापुत और सुन्दरगढ़ में चूना पत्थर के; सुन्दरगढ़ में सल्फाइड के तथा राज्य में एस-बैस्टस के विस्तृत अनुसन्धान ।

इन्द्रावती, वालीमेला, और उच्च कोलाब हाइडल परियोजनाओं; जोरा हरभंगी, उटेई, सालन्दी, दधरा घाटी, तकरा, बाराबंकी, सालिया, रमियाला, जारपाड़ा, कानूपुर, ओरदायी, कंझारी, ओंग, वरकोटी, तिकेरपाड़ा, बदनाला, पथरेल, सालदीही,झोराबंद, लोदानी परियोजनाओं के अन्वेषण ।

कटक तथा बालसूर में हाईड्रोलोजिकल जांच तथा कुछ नगरों में जल प्रदाय के अन्वेषण ।

धेनकानाल में ग्रेफाइट, वोलनगिरि; पटना में मैंगनीज अयस्क के; तथा वोलनगिरि में सीसा अयस्क के भूभौतिकी अन्वेषण ।

रेजर ब्लेडों का निर्माण

4181. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेजर ब्लेडों के निर्माण की आज तक की स्थिति क्या है और क्या यह निर्माण देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) संगठित क्षेत्र में 1965 तथा 1966 (जनवरी-जून) की अवधि में रेजर ब्लेडों का उत्पादन क्रमश: 9600 लाख तथा 4150 लाख हुआ । इसके अलावा लघु उद्योग क्षेत्र में भी कुछ उत्पादकों द्वारा 580 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से उत्पादन किया जा रहा है । देश की मांग को पूरा करने के लिए देश का उत्पादन पर्याप्त है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंजीनियरी उद्योग के लिए उपयुक्त इस्पात

4182. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी उद्योग के लिए उपयुक्त इस्पात की अभी भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). वैसे तो इस्पात की अत्यधिक कमी नहीं है लेकिन देशीय उत्पादन में कमी के कारण कभी-कभी मोटी प्लेटों, चादरों और विशिष्ट इस्पात की किस्मों में कमी हो जाती है । एक इस्पात संरचक उद्योग समिति जिसकी तीन क्षेत्रीय उप-समितियां हैं, मैचिंग स्टील की पूर्ति पर नजर रखती हैं और स्थिति का पुनरावलोकन करती हैं । जब कभी आवश्यक होता है मैचिंग स्टील की पूर्ति की स्थिति के बारे में संयुक्त संयंत्र समिति को सूचित कर दिया जाता है और दुष्प्राप्य वस्तुओं के विशेष बेलन की व्यवस्था कर ली जाती है ।

मोटी प्लेटों, चादरों और विशिष्ट इस्पात के देशीय उत्पादन की कमी को यथासम्भव आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है । प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आयात नीति को और उदार बना दिया गया है । इन किस्मों के इस्पात के देशीय उत्पादन में सुधार होने के साथ-साथ स्थिति में और भी सुधार होने के आशा हैं ।

तीन पहियों वाली गाड़ी उद्योग

4183. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन पहिये वाली गाड़ी उद्योग में हाल में कम गाड़ियां बनी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) तीन पहियों वाली गाड़ियों के उत्पादन में कुछ कमी हो गई है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :

वर्ष	उत्पादन
1964	4181 संख्या
1965	3665 संख्या
1966 (31-7-66 तक)	1336 संख्या

(ख) उत्पादन में यह कमी मुख्यत: इस उद्योग को मिलने वाली विदेशी मुद्रा में कमी के कारण हुई है । इस उद्योग को अब स्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए पुर्जों / कच्चे माल का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा पाने के हकदार प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है । इसको ध्यान में रखते हुए अनुमान है कि 1961 की प्रथम छमाही में तीन पहियों वाली गाड़ियों का उत्पादन बढ़ जाएगा ।

काली मिर्च का निर्यात मूल्य

4184. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों में काली मिर्च के निर्यात मूल्य गिर गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अच्छे मूल्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।
(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Employees of Signal Deptt. of the North Eastern Railway

4185. **Shri S. M. Banerjee :** **Shri Daji :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that employees of the Signal Department of the North Eastern Railway, who were promoted in 1956 have not been paid the arrears of Dearness Allowance so far ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) when the said arrears would be paid ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Duty Roster in the North Eastern Railway

4186. **Shri S. M. Banerjee :** **Shri Daji :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that model duty roster has not been introduced in various categories and branches of the North Eastern Railway ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) when the Railway Administration propose to introduce the said duty roster ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Railway Sanitary Staff of Varanasi

4187. **Shri Daji :** **Shri S. M. Banerjee :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway sanitary staff of Varanasi has not been paid the arrears of increase in dearness allowance so far ;

(b) whether it is also a fact that the said staff has not been paid the arrears of annual increments for several years ; and

(c) when the arrears are likely to be paid ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) No, the arrear increments relate to a period of two years only.

(c) By 30th September, 1966.

Drinking water at Stations on Northern Railway

4188. **Shri S. M. Banerjee :** **Shri Daji :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no adequate arrangements of drinking water for the passengers at the intermediary railway stations between Tundla and Shikohabad on the Northern Railway ;

(b) whether it is also a fact that Firozabad Railway Station on this very section, having passenger traffic in thousands, has neither sufficient arrangements for drinking water nor hand pumps nor there exists any arrangements of rope and bucket at the well for drawing water, thus causing much inconvenience to the thirsty passengers in summer ; and

(c) if so, the steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No. Adequate arrangements for drinking water do exist at all the three intermediary stations on Tundla-Shikohabad section ?

(b) No. Firozabad station is provided with 7 water taps, connected to the Municipal Water Supply System. Water is also stored in two water-huts and served to the passengers by four watermen who remain on duty all the time, for which there are five water trollies. There is therefore no need to provide hand-pumps etc. The Railway Administration is however proposing to install its own tube well at this station, instead of depending on water supply from Municipal Board.

(c) Does not arise.

काजू उत्पादक

4189. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काजू-निर्यात के द्वारा अर्जित की जाने वाली विदेशी पूंजी की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, काजू उत्पादकों को प्रोत्साहन देना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). चौथी योजना में काजू के उर्वराकरण के साथ-साथ सुधरी हुई पद्धतियों के और सघन प्रवर्तन का प्रस्ताव है। काजू की खेती करने वालों को नये क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 200/-रुपये के हिसाब से दीर्घावधि ऋण देने का विचार है बशर्ते कि काजू बागानों के चारों ओर बाड़ लगायी जाय। इसके अतिरिक्त, सहकारी विपणन संगठनों के माध्यम से, जोकि फैक्टरियों को संभरण हेतु कच्चे काजू के संचय के लिए उत्तरदायी हैं, उत्पादकों को अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए, सुधरी हुई विपणन सुविधाएं देने का भी विचार है।

Office of the General Manager, Western Railways

4190. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the office of the General Manager of the Western Railway is situated in Bombay ;

(b) whether it is also a fact that he is the Chief Administrative Head of all the employees of the Western Railway ; and

(c) the functions assigned to the General Manager by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The General Manager is responsible for the efficient management and functioning of the Zonal Railway.

कोयला खानों का बन्द किया जाना

4191. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई कोयला खानों, विशेषकर छोटी कोयला-खानों को हाल ही में बन्द करने के लिये बाध्य कर दिया गया था और यदि हां, तो ऐसी खानों की संख्या कितनी है और इनके नाम क्या हैं और उन खानों के क्या नाम हैं जो अपनी क्षमता से कम कार्य करती रही हैं ;

(ख) उन्हें किन परिस्थितियों में बन्द करना पड़ा और कितनी खनन-क्षमता बेकार पड़ी हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यद्यपि पिछले दस वर्षों में उनकी उत्पादन लागत बहुत ही बढ़ गयी है तथापि कोयले के दाम कम कर दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन-लागत में कितनी वृद्धि हुई है और कोयले के दामों में कितनी कमी हुई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे०) : (क) और (ख). 1966 में जो कोयला खानें बन्द हुई हैं (जुलाई 1966 तक) तथा उनके बन्द होने के कारणों का एक विवरण सदन के समक्ष रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-7014/66**]

(ख) खानों की क्षमता का युक्तियुक्त सही निर्धारण करना कठिन है क्योंकि खानों की उत्पादन क्षमता बहुत से बदलने वाले कारकों पर निर्भर होती है।

(ग) और (घ). समय समय पर मूल्य की बढ़ती स्वीकार की गई है जिसमें कि कोयले के उत्पादन की लागत के विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। यह सही नहीं है कि कोयले की कीमतें कम कर दी गई हैं। कोयला उत्पादन की लागत की विस्तृत जांच करने के लिये हाल ही में यह काम टैरिफ कमीशन को सौंप दिया गया है।

Public Sector Industries

4192. **Shri P. C. Borooah** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have received any advice from any outside agency to strengthen and expand the public sector industries at the expense of industries in the private sector ;

(h) if so, the name of the outside agency ; and

(c) how far it will be in consonance with the policy of Government to have a mixed economy in the country?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a). No, Sir.

(b). Does not arise.

(c) Government's approach to industrial development of the country has been clearly spelt out in the Industrial Policy Resolution, 1966.

हावड़ा-मद्रास एक्सप्रेस के एक डिब्बे में शव का मिलना

4193. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री बृजवासी लाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 अगस्त, 1966 को हावड़ा-मद्रास एक्सप्रेस के एक तृतीय श्रेणी के डिब्बे के शौचालय में, जब गाड़ी विशाखापतनम जिले में सामर्ल कोट पर रुकी, एक अज्ञात महिला का शव मिला ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन राजमुंद्री स्टेशन पर ।

(ख) वाल्टेर की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 379 के अन्तर्गत अपराध सं० 206/66 का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। आन्ध्र खुफिया पुलिस की अपराध शाखा स्थानीय पुलिस की सहायता कर रही है ।

Motor Launches

4194. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of motor launches with the Indian Railways at present ; and

(b) the number of additional launches proposed to be purchased ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Eight.

(b) One.

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में कर्मचारी

4195. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या के बारे में खाडिलकर समिति का प्रतिवेदन अधिकार देने वाली समिति (एम्पावरिंग कमेटी) को भेज दिया गया है ;

(ख) क्या इस अधिकार देने वाली समिति ने कलकत्ता स्थित लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में 300 पद स्थायी बनाने के प्रस्ताव पर खाडिलकर समिति से सहमति प्रकट की है ;

(ग) अब वित्त मंत्रालय अपेक्षित कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत कर्मचारियों को ही स्थायी बनाये जाने का नियम क्यों लागू कर रहा है जब कि पिछले 25 वर्षों से उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा ;

(घ) क्या यह इसलिए है कि पहले 300 से अधिक कर्मचारियों को स्थायी बनाना पड़ता है ; और

(ङ) 74 कर्मचारियों को फालतू क्यों रखा जा रहा है और इस पर भी उनको सरकार के अन्य विभागों में नौकर हो जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). खाडिलकर समिति ने 30 अगस्त, 1965 को कलकत्ता स्थित लोहा और इस्पात नियंत्रक

के कार्यालय की सेवीवर्ग व्यवस्था के कुछ पहलुओं पर सरकार को अपना अन्तिम प्रतिवेदन दिया था। प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी थी कि अन्तिम प्रतिवेदन में संगठन और सेवीवर्ग सम्बन्धी समस्याओं के बारे में मूल सिफारिशें मिलने तक, कार्यालय के दिन प्रतिदिन के काम के लिए जितने कर्मचारी आवश्यक हों और काम के अनुरूप हों उनकी संख्या निश्चित कर ली जाए और यदि कुछ कर्मचारी आवश्यकता से अधिक होवें तो उन्हें अधिसंख्य पदों पर रखा जाये। इस काम के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई अधिकार देने वाली समिति ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया। समिति ने फैसला किया कि दिन प्रतिदिन के काम के लिए 300 अराजपत्रित अनुसचिवीय कर्मचारी होने चाहिये तथा बचे हुए काम को पूरा करने के लिये 73 और कर्मचारी होने चाहिएं। लेकिन चूंकि लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में इन वर्गों के कर्मचारियों की वास्तविक संख्या 380 थी अतः यह फैसला किया गया कि मार्च 1966 के अन्त तक उन सबको रहने दिया जाये। ऐसी सम्भावना भी थी कि उस समय तक अध्ययन दल की सिफारिशें भी प्राप्त हो जायेंगी। संवादी पदों में स्थायी तथा अस्थायी दोनों शामिल थे।

अध्ययन दल ने अभी तक अपने प्रतिवेदन का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है। द्वितीय और अन्तिम भाग की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। इसमें संगठन तथा कर्मचारी सम्बन्धी प्रश्नों का भी विवेचन किया गया है। संगठन में कर्मचारियों की स्थायी संख्या के बारे में निर्णय प्रतिवेदन के अन्तिम भाग के मिल जाने पर ही किया जा सकता है।

ऐसा हो सकता है कि पिछले बाकी काम को पूरा करने के लिए रखे गये 73 पदों को खत्म करना पड़े। इन पदों के खत्म हो जाने से ही कुछ कर्मचारी फालतू होंगे। उनको अन्य नौकरियां देने के प्रश्न पर समय आने पर विचार किया जाएगा।

दक्षिण रेलवे में गैंगमैन और गेट-कीपर

4196. **श्री म० ना० स्वामी :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन : **श्री इम्बीचिबावा :**
श्री य० ना० सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के क्विलोंन-एर्णाकुलम लाइन पर कुछ मैट्रिकुलेट लोग गैंगमैन और गेट-कीपर के पदों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उनमें कुछ कर्मचारी इन पदों पर पिछले आठ वर्ष से कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) ऊंचे पदों पर उनकी पदोन्नति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पांच ।

(ग) जी हां ।

(घ) वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति के लिए उनकी बारी नहीं आयी है ।

इंजीनियरी कर्मचारियों की पदोन्नति

4197. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :
श्री कोल्लावैंकैया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक अर्हता वाले इंजीनियरी कर्मचारियों की पदोन्नति किस प्रकार हो, इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए कुछ समय पहले क्या एक आयोग नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या मदुरै डिवीजन के अधिकारियों ने इस आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

भारतीय कपड़े का निर्यात

4198. **श्री उमानाथ :**
श्री प० कुन्हन :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में कितना भारतीय कपड़ा बर्मा को निर्यात किया गया ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में बर्मा के साथ भारत का कितना व्यापार हुआ ; और

(ग) अगले पांच वर्षों में कितना व्यापार होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1964-65 और 1965-66 में बर्मा को भारत से क्रमशः 396.20 लाख रु०. तथा 183.55 लाख रु० मूल्य के कपड़े (सूती, जूट, कायर, नकली रेशम का माल आदि भी शामिल है) के निर्यात किये जाने का अनुमान है ।

(ख) 1961-62 से 1965-66 तक के वर्षों में बर्मा के साथ हुए व्यापार का परिमाण नीचे दिया जा रहा है :—

(लाख रु०)

वर्ष	व्यापार का परिमाण
1961-62	16,50
1962-63	14,17
1963-64	14,81
1964-65	16,71
1965-66	12,98

(ग) अगले पांच वर्षों में बर्मा के साथ होने वाले व्यापार के परिमाण का पूर्वानुमान करना कठिन है। फिर भी अनुमान है कि हमारा निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मक होगा तथा बढ़ेगा।

भारतीय कपड़ा संवर्धन एकक

4199. **श्री उमानाथ :**
श्री प० कुन्हन :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपड़ा संवर्धन एकक को रंगून में भारतीय दूतावास के भवन में स्थान दिया गया है ;

(ख) क्या इस भवन में प्रवेश एकदम वर्जित है ; और

(ग) यदि हां, तो एकक के द्वारा भारतीय कपड़े की प्रदर्शनी से क्या उद्देश्य पूरा हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). रंगून में भारतीय दूतावास के भवन में किसी भी भारतीय कपड़ा संवर्धन अथवा प्रदर्शन एकक को स्थान नहीं दिया गया है। सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि का कार्यालय दूतावास के भवन में स्थित है। प्रतिनिधि को रंगून में इसलिये रखा गया है जिससे कि भारत से बर्मा को, जहां बड़ी खपत की आशा है, होने वाले सूती कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

अत्यावश्यक वस्तुओं की सूची

4200. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं की सूची को बढ़ाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ोतरी में आने वाली वस्तुओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). आत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अभी तक घोषित 'अत्यावश्यक' वस्तुओं की सूची पर निरन्तर पुनर्विचार किया जा रहा है। जब कभी आवश्यकता पड़ी तो इस अधिनियम के अन्तर्गत और वस्तुएं भी ले आई जायेंगी। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अभी जो वस्तुएं सन्निहित हैं, उनको संलग्न सूची में दिखाया गया है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-7015/66**]

श्रीनगर को भेजे गये गेहूं का खराब हो जाना

4201. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **रेलवे** मंत्री काश्मीर जाने वाले खुले वैगनों में गेहूं लादने के बारे में 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 809 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने, जिसे राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था, हानि को पूरा करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस लापरवाही और हानि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) इस सम्बन्ध में अब तक राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति से क्षतिपूर्ति का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) हानि के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी ठहराने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

कानपुर से आगे रेलवे का विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन)

4202. **डा० प० श्रीनिवासन** : क्या **रेलवे** मंत्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर से टूंडला तक और रूरकेला से भिलाई तक के सेक्शनों के विद्युतीकरण के लिये सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उपरोक्त विद्युतीकरण कार्य ठेके पर कराने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्तमान रेलवे कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) कानपुर-टूण्डला और राउरकेला-दुर्ग (भिलाई) खण्डों के बिजलीकरण के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुके हैं और विस्तृत आंकड़े इकट्ठा करने तथा अभिकल्प-नक्शे बनाने का काम प्रगति पर है।

(ख) ऊपरी उपस्कर लगाने और स्विचिंग स्टेशन बनाने से सम्बन्धित काम, बिजली-सम्बन्धी कुछ सामान्य काम तथा कुछ सिविल इंजीनियरिंग के काम ठेके पर कराये जायेंगे, जबकि सिगनल और दूर-संचार सम्बन्धी काम, अन्य खण्डों पर इस प्रकार के कामों के लिए प्रचलित परिपाटी के अनुसार, स्वयं रेलवे द्वारा किये जायेंगे ।

(ग) और (घ). जो कर्मचारी स्थानान्तरण के पात्र हैं, उन्हें नयी योजनाओं में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । अन्य स्थानों पर कुछ फालतू कर्मचारी निर्दिष्ट कामों पर लगाये गये हैं । उन कामों के पूरा हो जाने पर इन फालतू कर्मचारियों की सम्भवतः छंटनी करनी पड़े ।

दुर्गापुर में धातुमिश्रित इस्पात कारखाना

4203. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में धातुमिश्रित इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए जापान की सरकार से कोई बातचीत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत में क्या प्रगति हुई है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु उद्योग

4204. **श्री रामपुरे** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के लिये नई प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना धन नियत किया गया है ;

(ख) ऐसी कितनी संस्थाएं स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) ये संस्थाएं किन-किन राज्यों में स्थापित की जायेंगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के विकास के लिये 120 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है । लघु उद्योगों के लिये नई प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये अलग से कोई धनराशि नियत नहीं की गई है । फिर भी शीघ्र ही राज्य सरकारों द्वारा आरम्भिक कार्य पूरा करने के पश्चात विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये विस्तृत कार्यक्रम बनाया जायेगा ।

(ग) यह सूचना कि कितनी नई संस्थायें स्थापित की जायेंगी तथा किन-किन राज्य में स्थापित की जायेंगी, विस्तृत कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के पश्चात् उपलब्ध होगी ।

चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्यात

4205. **श्री रामपुरे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एक प्रतिनिधिमण्डल ने भारतीय चीनी मिट्टी के बरतनों इत्यादि के लिये नई मंडियों का पता लगाने के उद्देश्य से अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों की यात्रा की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिनिधिमण्डल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिनिधिमण्डल ने प्रतिवेदन का प्रारूप दे दिया है ।

(ग) आवेदन में बताया गया है कि जिन देशों का दौरा किया गया है, उनमें स्वच्छता के सामान, चीनी मिट्टी के बर्तनों, चीनी के बर्तनों, काचित् टाइलों और अवरोधकों के लिये बाजार विद्यमान हैं बशर्ते कि उनका सम्भरण प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर किया जाय । स्वच्छता के सामान के मामले में उन्हें पुनः आकार-प्रकार देने, उनकी पुनः डिजाइनें बनाने और पुनः आकृति देने का सुझाव दिया गया है जिससे वे कम वजन के स्वच्छता के सामान के साथ मेल खा सकें ।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक का कार्यालय

4206. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में कार्य हस्तांतरण के परिणाम-स्वरूप कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के बारे में जांच करने और उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या निष्कर्ष तथा सुझाव दिये गये हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Trade Agreement with Bulgaria

4207. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri R. S. Tiwary :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have recently entered into a new trade agreement with Bulgaria as with other East European Countries; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). In connection with the problems that had arisen as a consequence of devaluation, discussions were held with the Government of Bulgaria in regard to revaluation of the contracts. Agreement was reached with them, similar to the ones reached with other East European countries, regarding the revaluation of the existing and unimplemented portions of the contracts by 57.5% both ways. A gist of the agreement reached with the Government of Bulgaria is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-7016/66].**

Dunlop Tyres and Tubes

4208. **Shri Vishram Prasad** : **Shri Ram Sewak Yadav** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Yashpal Singh** :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quality of tyres and tubes manufactured by the "Dunlop" Company has deteriorated although their prices have increased ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) No complaint regarding deterioration in the quality of tyres and tubes manufactured by M/s. Dunlop Rubber Co. (India) Ltd. has been received.

(b) Does not arise.

Railway Line Between Delhi and Bulandshahr

4209. **Shri Vishram Prasad** : **Shri Ram Sewak Yadav** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Yashpal Singh** :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a direct railway line between Delhi and Bulandshahr in view of the importance of the latter in the field of recruitment to the Army ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sri Sham Nath) : (a) No.

(b) Bulandshahr is already connected by rail with Delhi and there is no justification for another link from operational point of view.

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्

4210. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न परिषदों के अध्यक्षों के रूप में गैर-सरकारी व्यक्तियों के चयन और नियुक्ति के बारे में किसी नियमित तथा निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के अध्यक्ष का चयन और नियुक्ति किसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ;

(ग) क्या इस परिषद् के अध्यक्ष-पद के लिए कोई निश्चित अवधि रखी गई है ; और

(घ) क्या इस प्रकार के अध्यक्ष-पद के कार्य की जांच के बारे में कोई प्रणाली बनाई जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) तथा (ख). जहां कहीं भी गैर सरकारी व्यक्तियों की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई है वहां इसके लिए बनाए गए नियमों के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों की सीमा में केन्द्रीय सरकार द्वारा ये नियुक्तियां की जाती हैं। अध्यक्ष का वास्तविक चुनाव करने में केन्द्रीय सरकार इन स्थानों पर सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करती है।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार हर साल नियुक्ति पर पुनर्विचार करती है।

(घ) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद एक स्वायत्तशाली संस्था है जिसमें 12 सदस्य भारत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इनके द्वारा अध्यक्ष समेत परिषद के कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाती है।

भिलाई के लिये स्लीपर प्रेसिंग प्लांट का आयात

4211. **श्री रा० बरुआ :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 में भिलाई इस्पात कारखाने में लगाये जाने के लिये किसी स्लीपर प्रेसिंग प्लांट का आयात किया गया था ;

(ख) क्या इस प्लांट को स्थापित करने के पश्चात् चालू कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा क्रयादेश

4212. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1959 से लेकर अब तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कुल कितने निर्यात क्रयादेशों का निष्पादन किया है ;

(ख) ये निर्यात किन के द्वारा किये गये थे ; और

(ग) वस्तुओं की किस्म के बारे में कितने दावे दर्ज किये गये हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 1959 से अबतक 115 निर्यात के आर्डरों का निष्पादन किया है ।

(ख) अधिकांश इकरारनामों का निष्पादन इन्डियन एक्सपोर्ट हाउजिस के माध्यम से हुआ है ।

(ग) तीन हालतों में तथाकथित निम्न स्तर के माल होने से पार्टियों ने दावे किये हैं । ये सभी दावे मध्यस्थ-निर्णय/कानूनी जांच के अधीन हैं ।

इस्पात का निर्यात

4213. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कुछ निर्यातकों को विशाखापत्तनम से विदेशों को इस्पात का निर्यात करने के लिए कहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने वह माल स्वयं निर्यात करने की बजाय उसे स्थानीय बाजार में ही बेच दिया ; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कुछ निर्यातकों के साथ विशाखापत्तनम से वस्तु विनिमय के आधार पर निर्यात के बारे में इकरारनामें किये ।

(ख) हां, निर्यातकों ने उस माल की डिलीवरी नहीं ली और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को उसे स्थानीय बाजार में बेचना पड़ा ।

(ग) इसमें किसी प्रकार की विदेशी मुद्रा की हानि नहीं हुई लेकिन जिस 11 मिलियन रुपये की विदेशी मुद्रा की आमद की आशा थी वह पूरी नहीं हुई ।

इस्पात पिंडों का निर्यात

4214. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता की एक फर्म ने इस्पात पिण्डों का निर्यात किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि आयातकर्ता फर्म ने उन पिण्डों में से, जिनकी जांच की जा चुकी थी, 6,000 टन पिण्डों को रद्द कर दिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने यह दावा मान लिया है और वह दावे की राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है ; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अब तक उस राशि का भुगतान कर दिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां। कलकत्ता की दो फर्मों ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गये इस्पात पिण्डों का निर्यात वेल्स की इस्पात कम्पनी को किया।

(ख) लगभग 5600 टन परीक्षित इस्पात पिण्ड, जिसे तथा कथित निम्न स्तर का होने के कारण वेल्स की इस्पात कंपनी ने लेने से इन्कार कर दिया बताते हैं, के निम्न श्रेणी के होने के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ). उक्त फर्म द्वारा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पर किये गये दावे और उन फर्मों के विरुद्ध हिन्दुस्तान स्टील के दावे मध्यस्थ निर्णय/कानूनी कारवाई के अधीन हैं।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा अमरीका को कुंडलियों (कुआएल) का विक्रय

4215. **श्री कु० शिवप्रघासन** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अमरीका को 10,000 टन कुंडलियां (कुआएल) बेची हैं ;

(ख) ये कुंडलियों किस मूल्य पर तथा किस को बेची गई हैं ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टील ने उस फर्म की प्रदत्त पूंजी के बारे में पता लगाया था ;

(घ) उन कुंडलियों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या हैं और क्या विक्रय मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बराबर हैं ; और

(ङ) जिस फर्म ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से यह माल खरीदा है, उसकी साख क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स आर्टको इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन, न्युयार्क, यू० एस० ए० को क्वायल्स बेचे गये। मूल्य आदि के बारे में जानकारी देना लोक हित में नहीं होगा।

(ग) से (ङ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने स्वयम् भी क्रेता फर्म के पूर्ववृत और हैसियत के बारे में अधिकोष और वाणिज्य-निर्देश आदि द्वारा तसल्ली कर ली थी। यह तय हुआ था कि सप्लाई पुष्टिकृत और अप्रतिसंहार्य प्रत्यय-पत्र पर की जाएगी।

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल के लंदन स्थित विदेशी कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिस समय यह सौदा तय हुआ उस समय क्वायल्स का लागत-भाड़ा सहित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 81·50 डालर प्रति मीटरी टन था। (गम्य स्थान अमरीका के पूर्वी तट के पत्तन)

साइकिलों का निर्यात

4216. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1382 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकिलों के टायरों और ट्यूबों की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में कितने व्यापारी-निर्यातकों तथा निर्माता-निर्यातकों को सुविधा दी गई थी और किन निर्यातकों ने इस सुविधा का फायदा उठाया ;

(ख) इस शंका के क्या कारण हैं कि व्यापारी-निर्यातक टायर और ट्यूबों को निर्यात करने की बजाये घरेलू मण्डी में सप्लाई कर सकते हैं ; और

(ग) क्या किसी निर्यातक को प्रत्याशित निर्यात के लिये समय से पहले ही टायर और ट्यूब दिये गये थे और यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) डनलप टायर और ट्यूबों की कमी को पूरा करने की सुविधा केवल निर्माता-निर्यातकों को ही दी गयी हैं। अभी तक 12 निर्माता-निर्यातकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है ।

(ख) केवल निर्माता-निर्यातकों तक ही टायर और ट्यूबों के सम्भरण को सीमित करने में निम्न वार्ता को ध्यान में रखा गया है :—

(1) यद्यपि इस संबंध में वास्तविक निर्माता-निर्यातकों का कुछ पर्यवेक्षण किया जा सकता है किन्तु व्यापारी-निर्यातकों के मामले में इस उद्देश्य को सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है ।

(2) चूंकि डनलप कम्पनी बाइसिकिल के सभी निर्माताओं, जिसमें बाइसिकिलों के निर्माता-निर्यातक भी शामिल हैं, को भी सामान्य सम्भरण कर रहा है, अतः उनके द्वारा किये जाने वाले किसी भी प्रकार के अनाचार को कम्पनी द्वारा सामान्य सम्भरण को बन्द करके रोका जा सकता है ।

(ग) जी, नहीं ।

फर्मों का पंजीयन

4217. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, पटसन आयोग तथा वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी निदेशक ने, अलग अलग प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कितनी फर्मों को पंजीकृत किया है ; और

(ख) क्या कोई फर्म या फर्में 1965-66 में अपंजीकृत की गई थीं तथा उनको किन कारणों से अपंजीकृत किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1965-66 के दौरान चाय बोर्ड, काफी बोर्ड

जूट आयुक्त तथा वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय के महानिदेशक ने निम्नलिखित प्रकार से 1533 फर्मों को पंजीकृत किया :—

(1) चाय बोर्ड : 381 (171 व्यापारी निर्यातकों और 210 निर्माता-निर्यातकों को निर्यात करने के लिए निर्यात-लायसेंस दिये गये। यह कैलेण्डर वर्ष 1965 के लिए है)। चाय बोर्ड द्वारा पंजीकरण की तरह का कोई काम नहीं किया जाता।

(2) काफी बोर्ड : 6 (5 व्यापारी निर्यातकों और 1 निर्माता-निर्यातक के रूप में)।

(3) जूट आयुक्त : 39 (10 निर्माता-निर्यातकों और 29 अन्य रूप में)।

(4) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय का महानिदेशक : 1107 (524 व्यापारी निर्यातक तथा 583 निर्माता-निर्यातक के रूप में)।

(ख) काफी बोर्ड द्वारा केवल एक फर्म अपंजीकृत की गई क्योंकि वह फर्म अपना व्यापार चालू रखना नहीं चाहती थी। चाय बोर्ड जूट आयुक्त, तथा वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय के महानिदेशक ने कोई फर्म अपंजीकृत नहीं की।

साइकिलों के निर्यातक

4218. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकिल के तथा साइकिल के पुर्जों के कितने निर्यातक, व्यापारी-निर्यातक तथा उत्पादन-निर्यातक के रूप में अप्रैल 1966 तक इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् में पंजीकृत किये गये हैं और उनके नाम तथा पते क्या क्या हैं; और

(ख) उपरोक्त निर्यातकर्त्ताओं में से 1965-66 में कितने निर्यातकर्त्ताओं का अपंजीकृत किया गया, किन कारणों से किया गया तथा उनके नाम और पते क्या क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). पंजीकृत निर्यातकों के नाम तथा पते विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों के पास उपलब्ध हैं जिनमें इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् भी शामिल है। किसी भी विशिष्ट परिषद् के पास पंजीकृत होने वाले सभी निर्यातक उस परिषद् की सीमा में आने वाले किसी भी उत्पाद का निर्यात कर सकते हैं।

सरकार द्वारा अनुमोदित पंजीकरण नियमों के अनुसार निर्यातकों का पंजीकरण सम्बन्धित परिषदों तथा जिन्स बोर्डों द्वारा किया जाता है। परिषदों द्वारा उन निर्यातकों का अपंजीकरण किया जाता है, जो 18 मास की अवधि में निर्यात नहीं कर पाते हैं। काम के निष्पादन में त्रुटि होने के कारण भी अपंजीकरण किया जाता है। जो भी पंजीकृत निर्यातक अपंजीकरण के कारणों से सन्तुष्ट नहीं होता, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है जोकि या तो अपंजीकरण की

पुष्टि कर देती है या पंजीकृत निर्यातिक द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर सरकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए परिषद को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहती है ।

नारियल की आवश्यकता

4219. **श्री मणियंगाडन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नारियल की वार्षिक आवश्यकताओं का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो कितनी मात्रा की आवश्यकता है ;

(ख) देश में नारियल का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा में नारियल का आयात किया गया ; और

(घ) इस वर्ष के दौरान नारियल की कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा और आयातित नारियल का मूल्य क्या होगा ?

वाणिज्य उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) भारत में नारियल की वार्षिक आवश्यकता का औपचारिक मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है । किन्तु अनुमान है कि 1965-66 में भारत में 50,140 लाख नारियलों की मांग हुई ।

(ख) 1964-65 में देश में 48,390 लाख (अस्थायी) नारियलों का उत्पादन हुआ ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में खोपरे का आयात निम्न प्रकार से किया गया :—

	आयात	
वर्ष	**परिमाण, मी० टनों में**	**मूल्य, करोड़ रु० में**
1963-64	88067	8.80
1964-65	63099	6.43
1965-66	48722	6.26

(घ) 1 करोड़ रु० मूल्य का खोपरा आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम को एक लायसेंस दिया गया है । आयात की जाने वाली मात्रा विदेशी बाजार में चालू कीमतों पर निर्भर करेगी । यदि स्थिति अनुकूल हुई तो और अधिक आयात करने का अधिकार दिया जा सकता है ।

रबड़ का आयात

4220. **श्री मणियंगाडन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी रबड़ का आयात किया गया था ;

(ख) भारत में प्राकृतिक और संश्लिष्ट (सिंथेटिक) रबड़ दोनों कितनी पैदा होती हैं ; और

(ग) देश में कितनी रबड़ की आवश्यकता है और आयात की जाने वाली रबड़ का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) :

(क)

वर्ष	प्राकृतिक रबड़	संश्लिष्ट रबड़	कितनी मात्रा में आयात की गई उद्धत रबड़	आंकड़े मी० टनों में कुल योग
1963-64	26275	8812	8251	43338
1964-65	15003	3752	130	18885
1965-66	16357	2735	114	19206

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारत में उत्पादित रबड़ की मात्रा इस प्रकार थी :—

(आंकड़े मी० टनों में)

वर्ष	प्राकृतिक रबड़	संश्लिष्ट रबड़
1963-64	37487	9149
1964-65	45616	11633
1965-66	50530	14741

(ग) 1965-66 में 95092 मी० टन रबड़ की आवश्यकता थी और चालू वर्ष में रबड़ की अनुमानित आवश्यकता 1,04000 मी० टन है ।

तट पर आकर पड़ने वाली लागत बीमा भाड़ा मूल्य (अवमूल्यन-पूर्व) लगभग 4800 रु० प्रति मी० टन है ।

जम्मू तथा काश्मीर में रबड़ के कारखाने

4221. **श्री मणियंगाडन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में रबड़ के कारखाने हैं ;

(ख) क्या रबड़ उद्योग के उत्पादकों से उस राज्य में कोई उपकर लिया जाता है ;

(ग) क्या वे उपकर देने के लिये बाध्य नहीं हैं, क्योंकि रबड़ अधिनियम उस राज्य पर लागू नहीं होता है ;

(घ) यदि हां, तो उपकर वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ; और

(ङ) जम्मू तथा काश्मीर में उद्योगों को रबड़ किस प्रकार दिया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां । इस तरह की चार छोटी फैक्टरियां राज्य में हैं ।

(ख) तथा (ग). राज्य में, निर्माताओं से इस प्रकार का कोई उपकर नहीं लिया जा सकता क्योंकि रबड़ अधिनियम, 1947 जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता ।

(घ) तथा (ङ). राज्य में निर्माता कारखानों की आवश्यकता इस समय आयात द्वारा पूरी किये जाने के कारण उनसे कोई उपकर लिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

रबड़ अनुसंधान संस्था

4222. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबड़ बोर्ड के अधिकारियों ने पिछले तीन वर्ष से रबड़ अनुसन्धान संस्था की इन उपपत्तियों को दबाया है कि रबड़ बागान के मालिकों को दिये जाने वाले पोटाशियम में हानिकारक मात्रा में पोटाश मिला होता है और यही कारण है कि लागत बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अनुसंधान के परिणामों के दबाये जाने के कारण इस बोर्ड ने भारी घाटा उठाया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रूस को जूतों का निर्यात

4223. **श्री काजरोलकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम जूतों की सप्लाई के लिये रूस के आर्डर का पालन करने में अनुसूची से पीछे है ;

(ख) दिल्ली और आगरा में निगम के चमड़ा निर्माण विभागों द्वारा सप्लाई के लिये कितना कोटा रखा गया है ; और

(ग) क्या दिल्ली और आगरा के अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन अथवा समयोपरि भत्ता दिये बिना, बकाया काम समाप्त करने के लिये उनसे समय से ऊपर और छुट्टियों के दिन काम कराया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं । रूस को 8.8 लाख जोड़े जूतों के संभरण के लिये मास्को में 14 जनवरी, 1966 को राज्य व्यापार निगम एवं राजनोएक्सपोर्ट के मध्य एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गये थे । आज तक 5.25 लाख जोड़ों का लदान हो चुका है या वे वास्तविक लदान की प्रक्रिया में हैं । सम्भरण की गति उत्तरोत्तर इस प्रकार से रखी गई है कि कुल परिमाण का सम्भरण 1 दिसम्बर, 1966 से पहले ही पूर्ण हो जाय । मई तथा जुलाई,

1966 के बीच 1.2 लाख जोड़े जूतों तथा 5.85 लाख जोड़े चप्पलों के सम्भरण के लिये एक पूरक क्रयादेश के लिये बातचीत की जा चुकी है। हाल ही के इस क्रयादेश में से 41,000 जोड़े जूतों और 1.2 लाख जोड़े चप्पलों का सम्भरण किया जा चुका है। यह पूर्णतः लदान की परस्पर सहमत कार्यक्रम के अनुसार है।

(ख) अपनी प्रत्यक्ष प्राप्ति के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा क्रयादेश का विभिन्न प्राप्ति केन्द्रों के आवंटन, सामान्यतः विभिन्न केन्द्रों को अच्छी किस्म के माल देने की निर्माता एककों की क्षमता के निर्धारण के आधार पर किया जाता है। चालू क्रयादेश के लिये 3.19 लाख जोड़ों का सम्भरण राज्य व्यापार निगम के आगरा केन्द्र से तथा 0.96 लाख जोड़ों का सम्भरण दिल्ली केन्द्र से किया जाना है।

(ग) जी, नहीं। राज्य व्यापार निगम द्वारा उसके नियमों के अनुसार समयोपरि भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें निगम के विभिन्न केन्द्रों में, कार्य दिवसों पर काम के सामान्य घण्टों से अधिक या छुट्टियों में काम करने को कहा जाता हो। वर्ष 1965-66 में आगरा तथा दिल्ली केन्द्रों में समयोपरि भत्ते के रूप में 7,607.66 रुपये की राशि दी गयी। इसके अतिरिक्त दिल्ली तथा आगरा केन्द्रों के कार्यभारी अधिकारियों को वास्तविक मामलों में समयोपरि भत्ते की स्वीकृति के लिये अधिकार दे दिया गया है और यह क्रियाविधि सन्तोषजनक रूप से चल रही है।

भारतीय लोहा तथा इस्पात कम्पनी में नियुक्त विदेशी लोग

4224. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :
श्री बूटा सिंह :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय लोहा तथा इस्पात कम्पनी में कार्य कर रहे विदेशी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति वेतन की सुविधायें दी गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय कर्मचारियों को यह सुविधायें नहीं दी गई हैं ;

(ग) क्या विदेशियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते में काफी वृद्धि की गई है, परन्तु भारतीय अफसरों को उसी दर पर मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिस दर पर 1947 में दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने 1 जनवरी, 1963 से एक योजना लागू की थी जिसके अधीन ऐसे कर्मचारियों को जो

भारत से बाहर पैदा हुये हों और विदेश में ही भर्ती किये गये हों सेवानिवृत्ति वेतन की सुविधाएं प्राप्त हैं। जिस समय यह योजना लागू की गई थी उस समय उनके पास 19 विदेशी कर्मचारी काम कर रहे थे जिनमें से दो कर्मचारी चले गये हैं और उनको ये सुविधायें दी गई हैं। तीन कर्मचारी बिना सुविधा लिये नौकरी छोड़ गये हैं। जब से यह योजना चालू की गई तब से केवल एक ही वृद्धि हुई है। लागत के कारण ये सुविधाएं सभी कर्मचारियों को नहीं दी गई हैं। ऐसी संभावना है कि जिन कर्मचारियों को ये सुविधायें प्राप्त हैं उनकी सेवानिवृत्ति के साथ ही इस योजना के अन्तर्गत जो निधि स्थापित की गई है वह समाप्त हो जायेगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कार्य करने वाले भारतीय तकनीशन

4225. **श्री बूटा सिंह :**

श्री राम सेवक यादव :

श्री मधु लिमये :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में भारतीय तकनीशनों को 55 वर्ष की आयु में सेवा से निवृत्त होने के लिये बाध्य किया जाता है जबकि वैसी ही नौकरियों पर 55 और 65 वर्ष के बीच के विदेशियों को लगे रहने दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब भी प्रशासनिक पदों सहित महत्वपूर्ण पदों पर विदेशी कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या विश्व बैंक मूल्यांकन दल ने इस पर कोई टिप्पण किया है ; और

(घ) इस कम्पनी तथा इसके भारतीय अफसरों से सम्बन्धित मुकदमों की संख्या कितनी है और इस कम्पनी में भारतीय कर्मचारियों के साथ विदेशी कर्मचारियों के समान व्यवहार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी नहीं। इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का कहना है कि सेवा निवृत्ति की सामान्य आयु 55 वर्ष है। सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा-काल में वृद्धि करना हरेक केस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

(घ) एक मामले में एक सहायक काम संतोषजनक नहीं पाया गया और उसे त्याग पत्र देने के लिये कहा गया। सहायक यह मामला न्यायालय में ले गया है। उसने कम्पनी के विरुद्ध यह दावा किया है कि सेवा के इकरारनामें के अधीन उसे जो लाभ प्राप्त थे वे उसे नहीं दिये गये हैं। कम्पनी ने भी ऐसे सहायकों के विरुद्ध एक या दो मामले दायर किये हैं जो नौकरी के इकरारनामें में दी गई शर्तों का पालन किये बिना ही नौकरी छोड़ गये हैं।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदनपत्र

4226. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन पत्र महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) उनमें से कितने आवेदनपत्र उक्त अवधि में मंजूर किये गये तथा कितने नामंजूर किये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 93 (तीन महीनों मई-जूलाई, 1966 की अवधि में)।

(ख) स्वीकृत : एक भी नहीं।

अस्वीकृत : 1

जिनके लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं : 4

अपूर्ण आवेदन-पत्र : 1

अनिर्णीत : 87

महाराष्ट्र के लिए सीमेंट का आवंटन

4227. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की जनता के लिए सीमेंट का विशेष आवंटन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने टन सीमेंट का आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) से (ग). विनियंत्रण योजना के अन्तर्गत सरकार सीमेंट का नियतन केवल सरकारी विभागों/संगठनों को समझौते की दर पर देने के लिए किया जाता है जिसके लिए कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत सीमेंट सुरक्षित रहता है। सीमेंट नियतन तथा समन्वय संगठन ने जुलाई-सितम्बर, 1966 की अवधि के लिए सार्वजनिक दर पर खरीदे जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के नाम इस कार्य के लिए 59,000 मी० टन सीमेंट का विशेष नियतन करने का प्रस्ताव किया है।

महाराष्ट्र के लिए नालीदार जस्ता चढ़ी चादरों का नियतन

4228. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 के लिए महाराष्ट्र की जनता को नालीदार जस्ता चढ़ी लोहे की चादरों का विशेष नियतन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में अथवा कितने टन लोहे की चादरों का नियतन किया जा रहा है; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जस्ती नालीदार चादरों का कोई विशेष आवंटन संभव नहीं क्योंकि उत्पादकों के पास पहले के ही बहुत से आर्डर बकाया पड़े हुए हैं और जस्ते की कमी के कारण जस्ती नालीदार चादरों के उत्पादन में एकदम कटौती करनी पड़ी है ।

पांडिचेरी में जनता को नालीदार जस्ता चढ़ी लोहे की चादरों का दिया जाना

4229. **श्री कु० शिवप्रघासन** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966-67 में पांडिचेरी की जनता के लिए नालीदार जस्ता चढ़ी लोहे की चादरों का विशेष आवंटन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में अथवा कितने टन लोहे की चादरों का आवंटन किया जा रहा है; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जस्ती नालीदार चादरों का कोई विशेष आवंटन संभव नहीं क्योंकि उत्पादकों के पास पहले के ही बहुत से आर्डर बकाया पड़े हुए हैं और जस्ते की कमी के कारण जस्ती नालीदार चादरों के उत्पादन में एकदम कटौती करनी पड़ी है ।

पांडिचेरी के लिए सीमेंट आवंटन

4230. **श्री कु० शिवप्रघासन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी की जनता के लिए सीमेंट का विशेष आवंटन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने टन सीमेंट का आवंटन किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं हो तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) से (ग). विनियंत्रण योजना के अधीन सरकार सीमेंट का नियतन केवल सरकारी विभागों/संगठनों को समझौते की दर पर देने के लिए किया जाता

है जिसके लिए कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत सीमेंट सुरक्षित रहता है, सीमेंट आवंटन तथा समन्वयी संगठन ने पांडिचेरी को जुलाई-सितम्बर, 1966 की अवधि के लिए समझौते की दर पर इस कार्य के लिए 240 मी० टन सीमेंट का एक विशेष नियतन करने का प्रस्ताव किया है ।

Class III Empolyees selected by Railway Service Commission, Allahabad

4231. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees (class III) who were selected by the Railway Service Commission, Allahabad for the Civil Engineering Department (Field Staff), particularly the locomotive works and were posted at Mandva Locomotive works, have been declared surplus;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether they are now being sent to other Railways ; and

(d) the number of employees ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

(d) Nil.

Exploitation of Mines in Maharashtra and Madhya Pradesh

4232. **Shri Solanki** : Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that nearly three hundred mines are not being exploited at present in Maharashtra and Madhya Pradesh :

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken in this regard thereto ?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) It appears that the Hon'ble Member is referring to manganese ore mines in the States of Maharashtra and Madhya Pradesh. During the period 1961 to June, 1966, 15 mines were closed down and production in 169 mines was discontinued temporarily, of which, however, 117 mines were later reopened.

(b) The closure of 15 mines was due mainly either to the exhaustion or depletion of ore reserves below the economic level of the quality and grade. The reasons for the temporary stoppage of production in other mines were lack of suitable grade of ore, limited resources of the mine-owners to equip the mines with suitable machinery, lack of facilities for road and rail transport of ore from the mine to the port or internal market, fall in demand and also seasonal factors such as rains, harvesting season, etc.

(c) There has been a distinct revival in demand for manganese both in the internal market and the export market. Government have taken a decision to canalise all export

trade in manganese through Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., and secure the optimum benefit in terms of price and sale of all grades of Indian manganese ore. The devaluation of rupee is also expected to improve the competitive position of our manganese ores in the international market. It is hoped that these incentives will encourage the mine-owners to restart production from some of the mines where closure was not due to exhaustion of reserves.

भारत में बनाये जाने वाले संश्लिष्ट (सिंथेटिक) सूत का दाम

4233. **श्री बूटा सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने कारखाने हैं जो मोजे, बनियान इत्यादि के उद्योग में प्रयोग किये जाने के लिए संश्लिष्ट सूत को शंकु-वेलन (कोन्स) में तैयार हैं;

(ख) देश में उसका वार्षिक उत्पादन कितना होता है तथा वार्षिक मांग कितनी है;

(ग) 1955, 1960, 1962, 1964 में ये कारखाने अथवा उनके अभिकर्ता (एजेन्ट) इस सूत को किस दाम पर सप्लाई करते थे, तथा अब वह किस दाम पर सप्लाई किया जाता है; और

(घ) क्या इसके मूल्य पर कोई नियन्त्रण लगाया गया है और यदि नहीं, तो मूल्य पर नियन्त्रण लगाने तथा उसे निर्माताओं को उनकी मांग के अनुसार उचित मूल्य पर देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) भारत में होजरी उद्योग में उपयोग के लिए संश्लिष्ट सूत को शंकु-वेलन में तैयार करने वाला केवल एक ही कारखाना है ।

(ख) कारखाने ने मई, 1962 में उत्पादन करना आरम्भ किया था । उस समय से इस प्रकार उत्पादन हुआ है :—

वर्ष	**उत्पादन (किग्रा)**
1962	31,588
1963	77,092
1964	1,09,101
1965	98,486
1966 (जनवरी-जुलाई)	78,496

होजरी उद्योग की ऐसे सूत की वार्षिक मांग का अनुमान 10 लाख किग्रा लगाया गया है ।

(ग) फर्म द्वारा ली गयी कीमत नीचे दी गई है :—

वर्ष	**कारखाने से चलते समय की प्रति किग्रा कीमत जिसमें उत्पादन शुल्क भी शामिल है ।**
1962	रु० 90.00
1964	रु० 90.50
1966	रु० 101.00

(घ) ऐसे सूत पर कोई कीमत नियंत्रण अथवा वितरण नियंत्रण नहीं है ।

डिलक्स और सदर्न एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के बैरे

4234. **श्री नम्बियार :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प० कुन्हन :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री उमानाथ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि डिलक्स और सदर्न एक्सप्रेस रेलगाड़ी के बैरों और भोजन परोसने वालों को उनके कार्य की सूची में परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप सप्ताह में एक बार मिलने वाले विश्राम के दिन से वंचित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि डिलक्स रेलगाड़ी के भोजन परोसने वालों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली से, जहां यह पिछले दस वर्ष से था, अचानक बीच में ही मद्रास बदला जा रहा है जबकि उनके बच्चे दिल्ली में स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं;

(ग) क्या यह सच है कि लगभग सभी भोजन परोसने वालों ने इस स्थानान्तरण का और विश्राम का दिन समाप्त करने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं । एक संयुक्त रोस्टर शुरू करने का विचार है, जिसके अनुसार दोनों गाड़ियों के भोजन यान के कर्मचारियों को समान रूप से विश्राम मिलेगा ।

(ख) जी हां, लेकिन यह स्वयं कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर किया गया है ।

(ग) जी नहीं, लेकिन कुछ बैरों ने मुख्यालय बदलने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये हैं ।

(घ) अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

माल्ट मिश्रित दुग्ध खाद्यपदार्थ (माल्टिड मिल्क फूड) का निर्माण

4235. **श्री स० मो बनर्जी :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी व्यापार-चिह्न से माल्ट मिश्रित दुग्ध खाद्य-पदार्थ का निर्माण करने के लिए किसी विदेशी फर्म को कोई औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी वर्तमान कठिनाई की स्थिति के संदर्भ में लाभ तथा लाभांश के फलस्वरूप किस प्रकार से अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भेजने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख). मेसर्स हिन्दुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स लि०, नाभा को विदेशी ब्रांड 'हार्लिक्स' के नाम से माल्ट मिश्रित दुग्ध खाद्य बनाने के लिए 1992 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक औद्योगिक लाइसेंस दे दिया गया था। उनके वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 4,800 मी० टन वार्षिक तक कर देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा उनके लिए एक आशय-पत्र भी जारी कर दिया गया है।

(ग) मेसर्स हिन्दुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चरर्स लि० को विदेशी मुद्रा कमाने के लिए घी तथा माल्ट मिश्रित दुग्ध-खाद्य का निर्यात करने के लिए परामर्श दिया गया है।

नारियल जटा से बनी वस्तुओं का निर्यात

4236. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमूल्यन के पश्चात् नारियल की जटा से बनी वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है; और

(ख) 1965-66 की जून-जुलाई, अवधि के निर्यात आंकड़ों की तुलना में 1966-67 की जून-जुलाई अवधि में निर्यात आंकड़े क्या थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) तथा (ख). कोयर के माल के निर्यात पर अवमूल्यन के प्रभाव का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता।

अंग प्रक्षालन कागज (टायलेट पेपर) का आयात

4237. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंग प्रक्षालन कागज (टायलेट पेपर) के आयात की शर्तें शिथिल करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, नहीं। इसके आयातों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रबड़ का आयात

4238. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रबड़ के आयात को उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में कितना आयात होगा; और

(ग) क्या अधिक मात्रा में किये जाने वाले इस आयात का देश में रबड़ के वर्तमान मूल्यों पर बहुत बुरा असर पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी):(क) जी, हां।

(ख) लगभग 15,000 मी० टन।

(ग) इस आयात तथा नई देशी फसल के आ जाने के परिणामस्वरूप, देशी प्राकृतिक रबड़ की कीमतों, जो उच्च स्तर पर पहुंच गयी थीं, के कम हो जाने की आशा है।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में भेजा गया पुराना माल

4239. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री बालकृष्ण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ए० एल० सी० ओ० ने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी को पुराना माल नया कह कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). वाराणसी स्थित डीजल रेल-इंजन कारखाने ने अमरीका के ओवरसीज डीजल कारपोरेशन से अब तक कुल 3 करोड़ 60 लाख डालर का सामान खरीदा है। इसमें से कुल 60.75 डालर की लागत के तीन सामान जो अक्टूबर, 1965 में प्राप्त हुए थे, इस कारण से अस्वीकार कर दिये गये, क्योंकि ऐसा लगता था कि भेजे जाने से पहले उनका अमरीका में इस्तेमाल किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में पूछताछ करने से मालूम हुआ कि यह एक अकेला मामला है। इसके लिए ओवरसीज डीजल कारपोरेशन को बहुत दुःख हुआ और कारपोरेशन ने उन्हें मुफ्त बदल देने को कहा।

चूंकि इन चीजों का मूल्य अपेक्षाकृत नगण्य था और ओवरसीज डीजल कारपोरेशन इन्हें मुफ्त बदल देने के लिए रजामंद है, इसलिये मामले में आगे छानबीन करना जरूरी नहीं समझा गया।

अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संस्था

4240. **श्री नम्बियार :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे "अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संस्था" के मुख्यालयों को लखनऊ में

केन्द्रीकृत करने के निर्णय को क्रियान्वित कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सभी कार्यालयों तथा उपकरणों को जो अन्य केन्द्रों में थे अथवा हैं, लखनऊ ले जाया जा रहा है ;

(ग) क्या चितरंजन की अनुसंधान, डिजाइन तथा मानक संस्था के धातुकार्मिक और रसायन एकक को लखनऊ ले जाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा यह कब लाया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). धातुकर्म एवं रासायनिक स्कंध को छोड़कर, अनुसंधान निदेशालय के अन्य सभी स्कंध अब लखनऊ में स्थित हैं।

(ग) और (घ). धातुकर्म एवं रासायनिक स्कंध को लखनऊ ले जाने की बात सिद्धान्त रूप में स्वीकार की जा चुकी है, लेकिन जैसे-जैसे रकम उपलब्ध होगी, उपयुक्त चरणों में यह काम किया जायेगा।

पारे का आयात

4241. **श्री फिरोडिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय व्यापार निगम निम्नांकित वस्तुओं को अप्रैल, 1963 में किस मूल्य पर दे रहा था और आज किस मूल्य पर दे रहा है ;

(1) पारा (2) कपूर (3) अमोनियम बाइकार्बोनेट (4) मैन्थौल क्रिस्टल्स (5) सल्फेसेटामाइड सोडियम ;

(ख) वास्तविक उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं को सीधे मंगाने तथा राजकीय व्यापार निगम द्वारा आयातित करके दिये जाने वाले मूल्य में कितना अन्तर है ; और

(ग) क्या राजकीय व्यापार निगम द्वारा आयातित सामान को सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं में वितरित किया जाता है या विचोलियों द्वारा बांटा जाता है, और यदि विचोलियों के द्वारा बांटा जाता है तो कितनी छूट दी जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) संगत जानकारी नीचे दी गयी है :—

(रु० में)

	पारा	कपूर	अमोनियम बाइकार्बोनेट	मेन्थल	सेडामाइड सोडियम
1663 में कीमत	1800 (प्रति फलास्क)	15.17 वी० पी० वर्ग, 12.56 संश्लिष्ट	829.4	180.0	26.24 प्रति किग्रा, गोदाम से चलते समय

वर्तमान कीमत	5200 (प्रति फलास्क)	रा० व्या० नि० द्वारा कोई आयात नहीं किया गया	892.57	100.0	31.26 प्रति किग्रा, गोदाम से चलते समय

(ख) आवश्यक जानकारी नीचे दी गयी है :—

पारा : प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि पारे का आयात अब केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है और वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा पृथक से कोई आयात नहीं किया जाता है। पारे की विश्व कीमतें उसकी विश्व में कमी होने के कारण इन वर्षों में बढ़ गयी हैं।

कपूर : इसका मामला भी पारे जैसा ही है। इसके अतिरिक्त उसका कोई आयात नहीं किया जा रहा है।

अमोनियम बाइकार्बोनेट : उन कीमतों के बारे में जिन पर वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा आयात किया गया था, ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य व्यापार निगम द्वारा अब उसका आयात नहीं किया जाता है।

मैन्थौल : कई वर्षों से इस वस्तु का आयात केवल राज्य व्यापार निगम के द्वारा ही किया जाता है, राज्य व्यापार निगम और वास्तविक उपयोक्ताओं की कीमतों में अन्तर होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सल्फासेटामाइड सोडियम : वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा जिन कीमतों पर आयात किया गया था, उनके बारे में ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः कीमतों के अन्तर को बता पाना सम्भव नहीं है।

(ग) संगत जानकारी नीचे दी गयी है :—

पारा : इसका वितरण अंशतः राज्य व्यापार निगम और अंशतः वितरकों के द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रति फ्लास्क के पीछे 100 रु० पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है।

कपूर : इसका वितरण सीधे ही राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता था।

अमोनियम बाइकार्बोनेट : इसका वितरण वितरकों के जरिये किया जाता है जिन्हें तटागत लागत के 10 प्र० श० का लाभ दिया जाता है।

मैन्थौल : इसका वितरण वितरकों के जरिये किया जाता है जिन्हें 5 रु० प्रति किग्रा का लाभ दिया जाता है।

सल्फासेटामाइड सोडियम : इसका वितरण वितरकों के जरिये किया जाता है जिन्हें तटागत लागत के $4\frac{1}{2}$ प्र० श० का लाभ दिया गया है ।

अफगानिस्तान को चाय का निर्यात

4242. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर बाजार के वह लोग ही, जिनके पास निर्यात संवर्द्धन प्रोत्साहन लाइसेंस हैं, अफगानिस्तान को चाय का निर्यात करने के हकदार हैं तथा वास्तविक उत्पादक ऐसा करने के हकदार नहीं हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह मेवों के निर्यातकों के नाते काम करते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वास्तविक उत्पादकों अथवा उनकी संस्थाओं को, जैसे "कांगड़ा टी प्लांटर्ज सप्लाई एण्ड मार्केटिंग सोसाइटी" को मेवों के बदले में चाय का निर्यात करने देने के लिए निर्यात संवर्द्धन प्रोत्साहन लाइसेंस देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). विनिमय नियन्त्रण विनियमन के अधीन केवल उन्हीं निर्यातकों को लाइसेंस दिये जाते हैं जो कि अफगानिस्तान से वस्तुओं के स्वयं आयातकर्ता भी हैं और पिछले वर्षों में अपने अफगान एजेन्टों के नाम में हिसाब रखते आये हैं, किन्तु किसी भी पार्टी द्वारा अफगानिस्तान को चाय का निर्यात किया जा सकता है, बशर्ते कि वह आयात व्यापार नियन्त्रण विनियमन के अधीन निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार अफगानिस्तान से अनुमति प्राप्त वस्तुओं जिनमें मेवे भी शामिल हैं, के आयात से प्रतिसंतुलित किया जा सके ।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा नगरपालिका के चुनाव लड़ना

4243. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्रीमती गंगा देवी :**
श्री मौर्य : **श्री ना० नि० पटेल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1960 के पहले रेलवे कर्मचारी नगरपालिका के चुनाव लड़ सकते थे ;

(ख) यदि हां, तो किस विशिष्ट आधार पर ऐसी अनुमति दी जाती थी ; और

(ग) क्या सरकार ने उस नियम को अब वापस ले लिया है जिसके अन्तर्गत प्रत्याशित उम्मीदवारों को अनुमति दी जाती थी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1960 से पहले, रेल कर्मचारी (आचरण) नियम, 1956 के निबन्धनों के अधीन सरकार रेल कर्मचारियों को स्थानीय

प्राधिकरण के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दे सकती थी, लेकिन वास्तव में 1960 से पहले किसी रेल कर्मचारी को म्युनिसिपल चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गयी थी ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी हां, 16-6-1960 से ।

चप्पलों और बीड़ियों का निर्यात

4244. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के लोग कोल्हापुरी चप्पलों और भारतीय बीड़ियों का प्रयोग करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी बिक्री हुई है ;

(ग) भविष्य में इनकी बिक्री की क्या संभावना है ; और

(घ) क्या हाल ही में कोई बाजार सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). विगत 2-3 वर्षों में अमेरिका को कोल्हापुरी चप्पलें निर्यात की गई हैं । निर्यात के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते परन्तु अनुमान है कि चालू वर्ष में 35,000-40,000 रुपए मूल्य के लगभग 50,000 जोड़े निर्यात किए जायेंगे । ऐसी वस्तुओं की मांग स्थायी नहीं मानी जा सकती ।

अमेरिका को बीड़ियों का कोई निर्यात नहीं किया गया । अमेरिका में बीड़ियां चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(घ) जी, नहीं ।

कोयले का उत्पादन

4245. **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की परियोजनाओं में कोकिंग तथा नान कोकिंग कोयले के उत्पादन के लिए पृथक-पृथक, कुल कितना धन लगाया गया है ;

(ख) तीसरी योजना अवधि में कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयले का कितना उत्पादन हुआ है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) कोकिंग तथा नान-कोकिंग कोयला निकालने पर औसतन कितना खर्च आता है ; और

(घ) क्या कोयले की आयोजना की प्राथमिकताओं तथा आवश्यकता के अनुसार इसके उत्पादन कार्यक्रम को कम करने की इस निगम की कोई योजना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की परियोजनाओं पर पूंजी की लागत 31-3-66 को 138.11 करोड़ रुपये थी जिसमें 33.07 रुपये कोकिंग कोयला परियोजनाओं, 68.82 करोड़ रुपये नान कोकिंग कोयला परियोजनाओं तथा 36.22 करोड़ रुपये कोयला खनन परियोजनाओं के अतिरिक्त दूसरे एककों पर शामिल है।

(ख) तीसरी योजना काल में कोकिंग तथा नान कोकिंग कोयले का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

(आंकड़े लाख मीटरी टनों में)

वर्ष	कोकिंग	नान कोकिंग	कुल
1961-62	31.433	29.07	60.50
1962-63	31.82	52.43	84.25
1963-64	32.31	57.29	89.60
1964-65	29.41	52.99	82.40
1965-66	28.44	68.41	96.85

चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक आशा है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की परियोजनाओं से लगभग 12 मिलियन टन कोकिंग कोयला 2.5 मिलियन टन व्लेडेवल कोयला तथा 18 मिलियन टन नान कोकिंग कोयला उत्पादन होगा। कोयले का वास्तविक उत्पादन मांग के साथ सम्बन्धित होगा।

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की राजस्व कोयला खानों से कोकिंग तथा नान कोकिंग कोयला खनन की औसतन लागत क्रमशः 27.14 रु० तथा 23.60 रु० प्रतिमीटरी टन है।

(घ) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अपने उत्पादन कार्यक्रम को कोयले की योजनाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार नियोजित करेगी।

मैसूर खादी बोर्ड

4246. **श्री हु०चा० लिंग रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय किये जाने हेतु मैसूर राज्य खादी बोर्ड के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) कितना धन व्यय किया जा चुका है तथा किन योजनाओं पर;

(ग) खादी बोर्ड द्वारा राज्य में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है; और

(घ) कार्यक्रम का ब्योरा क्या है तथा चौथी योजना की अवधि में कितना धन नियत किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

मैसूर में औद्योगिक बस्तियां

4247. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में अब तक कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं तथा वे कहां-कहां पर हैं और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आई है;

(ख) वे अब तक नये उद्योग आरम्भ कराने तथा बेरोजगारी की समस्या को हल करने में किस सीमा तक सफल हुई हैं; और

(ग) राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये इन औद्योगिक बस्तियों का क्या कार्यक्रम सुझाया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क). मैसूर राज्य में 31-3-1966 तक निम्नलिखित 12 औद्योगिक बस्तियां बसाई जा चुकी हैं :—

बस्तियों का स्थान	**जिला**	**अनुमानित लागत (रु० लाखों में)**
मैसूर	मैसूर	6.5
बेलगांव	बेलगांव	6.55
रामनगरम्	बंगलौर	2.48
बंगलौर-1	बंगलौर	38.18
बंगलौर-2 (एच. एम. टी.)	बंगलौर	17.9
हुबली	दरवाड	8.00
हरिहर	चित्रदुर्ग	6.63
गुलबर्ग	गुलबर्ग	5.4
मंगलौर	दक्षिणी कनारा	4.16
बीजापुर (1)	बीजापुर	3.00
जामखंडी	बीजापुर	5.00
मरकरा	कुर्ग	1.5
	योग	105.30

(ख) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक ज्ञापन में राज्य सरकार ने 15 नई औद्योगिक बस्तियां तथा चार कार्यरत औद्योगिक बस्तियां बसाने का सुझाव दिया था ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम के अधीन योजनाओं के लिए 655 लाख रुपये खर्च करने का सुझाव दिया गया है ।

मैसूर में रेशम उद्योग का विकास

4248. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर राज्य में रेशम उद्योग के विकास हेतु कितने सिंचाई कूप खोदे गये हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के लिये तीसरी योजना की अवधि में कितना धन नियत किया गया था तथा नियत राशि से कम व्यय होने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में रेशम उत्पादन करने वाले क्षेत्र में और विशेषतया मैसूर राज्य में चौथी योजना की अवधि में रेशम उद्योग का विकास करने के लिए सिंचाई के कुएं खोदने का क्या कार्यक्रम है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 136 ।

(ख) 10.99 लाख रुपये के आवंटन में से तीसरी योजना अवधि में वास्तविक व्यय 8·72 लाख रुपये हुआ था । व्यय में कमी के प्रमुख कारण ये थे :—

(1) राष्ट्रीय संकट के बाद मैसूर सरकार द्वारा की गई कटौती; और

(2) रेशम विभाग से तालुक बोर्ड की योजना का हस्तान्तरण, जिसके कारण योजना के क्रियान्वयन में क्रियाविधि सम्बन्धी देर हुई ।

(ग) चौथी योजना की अवधि में मैसूर, मद्रास, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में 3,415 कुएं खोदने के विचार से राज्यों के चौथी योजना के प्रस्तावों में 299.98 लाख रुपये की अनुमानित लागत सम्मिलित की गयी है । कार्यक्रम के अन्दर मैसूर राज्य में 287.1 लाख रुपये की लागत से 3,000 कुएं खोदने का विचार है ।

मालूर में रेलवे पुल

4249. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के बंगलौर तथा मद्रास के बीच मालूर में रेलवे पुल बनाने के सम्बन्ध में, आज तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार इस पुल पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

(ग) इस अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) यह पुल कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) मालूर में ऊपरी सड़क-पुल के नये स्थान के बारे में राज्य सरकार के परामर्श से अन्तिम निर्णय अभी किया गया है ।

(ख) इस काम की लागत में रेलवे का हिस्सा लगभग 3.24 लाख रुपये है ।

(ग) रेलवे की वजह से कोई विलम्ब नहीं हुआ । रेलवे ने इस काम के खर्च का अनुमान अगस्त, 1964 में तैयार कर लिया था, लेकिन राज्य सरकार के अनुरोध पर पुल का स्थान बदल दिये जाने के कारण रेलवे इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाई न कर सकी । पुल के नये स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय अभी हाल में हुआ है ।

(घ) आशा है कि रेलवे के हिस्से का निर्माण-कार्य 1967-68 तक पूरा हो जायेगा ।

Bogus Supply of Sleepers to Railways by M/s. Shriram Ram Niranjan, Bombay

4250. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri S. L. Verma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Shriram Ram Niranjan, Bombay had signed a contract for the supply of sleepers worth about Rs. 10 lakhs to the Railway Department during 1954-55 ;

(b) whether it is also a fact that the said Company made bogus supplies of sleepers to Government and a criminal case was also instituted against some of the proprietors of this firm at that time ;

(c) if so, the names thereof, and when this case was decided :

(d) if this case has not been decided so far, the reasons therefor ; and

(e) the total amount of loss incurred by Government thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

इटारसी रेलवे स्टेशन

4251. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि मध्य रेलवे के इटारसी रेलवे स्टेशन पर नये प्लेट फार्म पर सदर्न एक्सप्रेस तथा अन्य मुख्य गाड़ियां आकर रुकती हैं फिर भी इस प्लेट फार्म पर कोई छत (शेड) नहीं है;

(ख) सरकार द्वारा इस प्लेट फार्म पर गाड़ियों में चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों को,

विशेष रूप से गर्मी और बरसात के दिनों में, होने वाली कठिनाई और असुविधा की ओर ध्यान न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ). इटारसी स्टेशन के नये प्लेटफार्म पर 300' × 51'-5" की छत डालने का प्रस्ताव 1966-67 के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इस काम की मंजूरी अभी हाल में दी गई है और आशा है, इसे जल्द शुरू कर दिया जायेगा।

आयातित टेलीविजन सेट

4252. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैकड़ों आयातित टेलीविजन सेट राज्य व्यापार निगम के पास पड़ें हैं, जो बेचे नहीं जा सके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको उचित और नियमित तरीके से बेचने या देने तथा लापरवाही एवं उदासीनता के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). पूर्वी अफ्रीका के एक प्रवासी भारतीय द्वारा 1000 टेलीविजन सेटों का आयात इस शर्त पर किया गया था कि वह इसके लिये अपनी निजी विदेशी मुद्रा प्रयुक्त करेगा। चूंकि वह बहुत समय तक माल को कस्टम्स से नहीं छुड़ा सका, राज्य व्यापार निगम को सीमा शुल्क चुकाने और जनता को बेचने के उद्देश्य से सेटों को दिल्ली लाने के लिये अधिकृत किया गया। तब पार्टी ने सेटों की बिक्री शुरू की और वस्तुत: 350 सेट खरीदारों को दे दिये गये। फिर, 18-5-66 को उसके एक सहयोगी के नाम पर प्राप्त एक न्यायालय व्यादेश के माध्यम से खरीदारों से और रुपया लेने, या राज्य व्यापार निगम से और सेट प्राप्त करने से उसे बंचित किया गया। इसी कारण बकाया सेटों की बिक्री आगे के लिये रोक दी गयी है। इसी बीच, ऐसे ग्राहकों का रिकार्ड रखा जा रहा है जिन्होंने अग्रिम भुगतान कर दिया है या अपनी आवश्यकताएं दर्ज करा दी हैं।

सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार

4253. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 तक कुछ उद्योगों तथा उपक्रमों में सरकारी क्षेत्र का जो एकाधिकार था वह संसद के बजट सत्र से अब तक लगभग समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो एकाधिकार किन-किन उद्योगों तथा उपक्रमों में समाप्त कर दिया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिये अन्य प्रकार से भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ङ) . सरकार की औद्योगिक नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अभी भी औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के ढांचे के अनुसार ही हो रहा है। इस ढांचे के अन्दर गैर-सरकारी क्षेत्र के स्थिति के अनुसार आवश्यकताओं को देखते हुए प्राथमिकता वाले उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है।

खण्ड निरीक्षक (ब्लाक इंस्पेक्टर)

4254. **श्री गुलशन** : **श्री साधु राम** :
श्री बूटा सिंह : **श्री मौर्य** :
श्री दलजीत सिंह : **श्री मधु लिमये** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के सिगनल तथा दूर-संचार विभाग में कितने खण्ड निरीक्षक हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं;

(ख) उन विभागों में कितने सहायक निरीक्षक हैं और इनमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं; और

(ग) क्या सरकार ने रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एस० सी० टी०) 57-सी, एम/1/20 दिनांक 27 अप्रैल, 1959 के अनुसार उक्त वर्गों में आरक्षित रिक्त स्थानों को अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की भरती द्वारा भरने की व्यवस्था की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

(क)	कुल	64
	अनुसूचित जातियों के	1
(ख)	कुल	48
	अनुसूचित जातियों के	—

(ग) आरक्षित जगहों को भरने की कोशिश जारी है। योग्य उम्मीदवारों की कमी के कारण अभी इस कोशिश में सफलता नहीं मिली है।

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना

4255. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से हिन्दुस्तान केबल्स द्वारा उत्तर प्रदेश में जो ट्रैक्टर बनाने का कारखाना लगाया जाने वाला था उसके स्थान के बारे में पुनः विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में परिवर्तन किस प्रकार हो गया है जबकि तकनीकी विशेषज्ञों ने रामनगर और बरेली को उचित स्थान के रूप में चुना था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में उतनी केन्द्रीय परियोजनाएं आरम्भ नहीं की गईं जितनी की जानी चाहिए थीं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में कृषि ट्रैक्टर तथा पुर्जे बनाने के लिये एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। चैकोस्लोवाकिया की मेसर्स मोटोकोव द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस परियोजना को लागू करने के बारे में अन्तिम निर्णय चैकोस्लोवाकिया के अधिकारियों के पास से तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही किया जायगा। यदि इस योजना पर अमल करने का निर्णय किया गया तो इसकी स्थापना वाराणसी जिले के रामनगर नामक स्थान पर करने का विचार है। इस परियोजना की स्थापना हिन्दुस्तान केबिल्स के द्वारा नहीं की जाएगी।

(ग) पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक प्रायोजनाएं स्थापित करने के कार्य पर लगभग 62.90 करोड़ रु० की पूंजी लगाई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में अभी निम्नलिखित औद्योगिक एककों को कार्यान्वित किया जा रहा है :—

(1) डीजल लोको-फैक्ट्री, वाराणसी।

(2) ऐन्टीबायोटिक्स फैक्ट्री, ऋषीकेश।

(3) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार।

(4) फर्टिलाइजर फैक्ट्री, गोरखपुर।

(5) अल्कैलाइट फैक्ट्री।

इनके अतिरिक्त चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में स्थापित निम्नलिखित परियोजनाओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव है :—

(1) हैवी स्ट्रक्चरल्स प्रोजेक्ट, इलाहाबाद।

(2) हैवी कम्प्रेसर तथा पम्प प्रोजेक्ट, इलाहाबाद।

(3) हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार के लिये फांउड्री फोर्ज।

फिएट कारों का आवंटन

4256. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को पिछले दस वर्षों में (वर्षवार) कितनी फिएट कारों का आवंटन किया गया;

(ख) क्या इस अवधि में आवंटित कारों की संख्या घटती रही है; और

(ग) यदि हां, तो साम्यता के आधार पर कारों का आवंटन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

बंगाल जूट मिल्स, हावड़ा

4257. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों ने 1 अक्तूबर, 1965 से हावड़ा स्थित बंगाल जूट मिल्स को बन्द कर रखा है तथा गार्डन रीच स्थित विक्टरी जूट मिल्स 1 सितम्बर, 1966 से बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि बताये गये कारण सही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से इन मिलों को अपने अधिकार में लेकर उन्हें चलाने का है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी कि बंगाल जूट मिल्स के प्रभावित कर्मचारियों को कानून के अन्तर्गत देय न्यूनतम बोनस और जबरी छुट्टी के लिए मुआवजा आदि दिये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) बंगाल जूट मिल्स, हावड़ा 1 अक्तूबर, 1965 से और विक्टरी जूट मिल्स 20 जून, 1966 से बन्द पड़ी हैं।

(ख) बंगाल जूट मिल्स के मामले में मुख्य शाफ्ट का खराब हो जाना इसके बन्द हो जाने का कारण बताया गया है । किन्तु मिल के वर्तमान मालिकों के मध्य प्रस्तावित विभाजन को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वचनवद्धताओं को पूरा करने की कठिनाइयां वास्तविक कारण प्रतीत होती हैं ।

विक्टरी जूट मिल्स के बन्द होने का मुख्य कारण वित्तीय कठिनाइयां हैं ।

(ग) इस समय इन मिलों के प्रबन्ध को अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है । दोनों ही मिलें पुरानी हैं ।

(घ) यह सुनिश्चित करना पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार का काम है। ज्ञात हुआ है कि बंगाल जूट मिल्स ने फरवरी 1966 के प्रथम सप्ताह तक कामगरों को जबरी छुट्टी के लिए मुआवजा दे दिया है। कामगरों को मुआवजा देने का कुल मामला पश्चिमी बंगाल के स्थायी औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज दिया गया है। विक्टरी जूट मिल्स अपने कामगरों को इसके बन्द होने के समय से ही जबरी छुट्टी के लिए मुआवजा दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जबरी छुट्टी का मामला पश्चिमी बंगाल के स्थायी औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज दिया है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के वर्कशाप तथा अनुसचिवीय कर्मचारियों के पदों का ऊंचा किया जाना (अपग्रेडिंग)

4258. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्कशाप तथा अनुसचिवीय कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को ऊंचा (अपग्रेड) किये जाने के बारे में शंकर शरण पंचाट को दक्षिण-पूर्व रेलवे में अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित कर्मचारियों की वह हानि कैसे पूरी करने का विचार है जो उन्हें अपग्रेडिंग के लाभ से जिसे वे 1 अक्तूबर, 1962 से प्राप्त करने के हकदार थे, वंचित किये जाने के कारण हुई है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के इंजन चलाने वाले कर्मचारियों को भी संयुक्त सलाहकार समिति द्वारा 1950 में की गई सिफारिश के आधार पर अपग्रेड नहीं किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). जी नहीं, लेकिन क्रमोन्नति का लाभ अ-यांत्रिक कारखानों को जून, 1964 में दिया गया। खड़गपुर बिजली कारखाने को छोड़कर दक्षिण-पूर्व रेलवे के सभी अ-यांत्रिक कारखानों में भी इन अदेशों पर अमल किया गया है। खड़गपुर बिजली कारखाने में इन पर अमल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस बिजली कारखाने के पात्र-कारीगरों को 1-10-1962 से, पूर्व व्याप्ति सहित, बकाये का भुगतान किया जायेगा।

(ग) रेलवे बोर्ड ने 1961 में यह विनिश्चय किया था कि जिन फायरमैनों और शंटरों के मामलों में संयुक्त परामर्श समिति के वेतनमान लागू नहीं किये गये हैं, उन्हें सीधे 1957 के वेतनमान दिये जायें और सामान्य नियमों के अनुसार उनका वेतन निर्धारित किया जाये। फायरमैनों और शंटरों के सम्बन्ध में संयुक्त परामर्श समिति के वेतनमान, दक्षिण-पूर्व रेलवे में उस समय तक केवल 5 कर्मचारियों पर लागू हुए थे। बाकी कर्मचारियों को सीधे 1957 के वेतनमान दिये गये।

केरल में काफी बागान

4259. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काफी बागान का क्षेत्र बढ़ाने के सम्बन्ध में काफी बोर्ड की कोई योजनाएं हैं;

(ख) नये बागान लगाने वाले लोगों को क्या सहायता देने का विचार है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में कितने क्षेत्र में नये बागान लगाये गये; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में अनुदान और ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं। वास्तव में केरल राज्य में काफी के बागान के विस्तार के लिए बहुत ही थोड़ी भूमि उपलब्ध है।

(ख) काफी के नये बागान लगाने के लिए काफी बोर्ड द्वारा सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

(ग) पिछले पांच वर्षों में केरल में काफी उपजाने के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) पिछले पांच वर्षों में काफी के पैदा करने वाले क्षेत्र में गहन रूप से बागान लगाने के लिए केरल के काफी उत्पादकों को कुल 3,10,226 रु० के ऋण दिये गये।

शिमला के एक भाग का धंसना

4260–ए. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला में कुछ स्थान धंस रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) और (ख). सितम्बर, 1959 में हुए तटीसर्पण और अधोगमन का अनुसंधान भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा किया गया। वे स्थानीय थे, कटाव के नियंत्रण तथा सतह और अधोतल जलोत्सारण के तरीकों के बारे में सिफारिशें की गईं। हाल में शिमला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किए गये निवेदन के फलस्वरूप भारतीय भौमिकी विभाग शिमला की म्युनिसिपल सीमा के अन्दर के उन भागों का अनुसंधान कर रहा है जिनके बारे में धंसने की सूचना मिली है और यह भी पता लगायेगा कि धंसान किस हद तक है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 787 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to U. S. Q. No. 787

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह): अतारांकित प्रश्न 787 के भाग (क) के उत्तर में यह कहा गया था कि 'यह पेटेंट भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के पास है।'

2. सही स्थिति यह है कि भारत के राष्ट्रपति के नाम समनुदेशन विलेख सहित लेटर्स पेटेंट का केवल मूल विलेख भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सुरक्षित कब्जे में है। चूंकि अभी पेटेंट भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को दिया जाना है, इसलिए प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में से यह वाक्य काट दिया जाये कि 'पेटेंट भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के पास है,' क्योंकि सांविधिक दृष्टि से भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने अभी तक पेटेंट में लाभग्राही हित प्राप्त नहीं किया है।

3. इसलिए भाग (क) के उत्तर को इस प्रकार पढ़ा जाये :—

"जी हां, लेकिन सूरी ट्रांसमिशन सहित वर्तमान डिजाइन के टार्क कन्वर्टरों से इसके बेहतर होने का कोई खास दावा नहीं किया गया है।"

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान को अमरीकी सेबर जैटों का दिया जाना
Supply of U. S. Sabre Jets to Pakistan

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I would invite the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and request him to make a statement thereon :

"Reported supply of Sabre Jets to Pakistan through Ottawa-Bonn-Teheran axis".

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : पाकिस्तान ने बहुत से एफ-86 हवाई जहाज जिनकी संख्या 60 से 90 तक बताई जाती है, हाल ही में ईरान से प्राप्त किये। वह हवाई जहाज कनाडा में बनाये गये थे तथा कुछ वर्ष पूर्व कनाडा ने पश्चिमी जर्मनी को बेच दिए थे। पश्चिमी जर्मनी ने हाल ही में उन जहाजों को ईरान को बेच दिया। यद्यपि वह जहाज अमरीकी नमूने के हैं फिर भी हमें अमरीकी सरकार ने सूचित किया है कि उनके उत्पादन, बिक्री तथा निबटान पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है।

पिछले वर्ष के अन्त में जब यह समाचार मिला कि पाकिस्तान तीसरे देशों के जरिये पश्चिमी जर्मनी से शस्त्र प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो हमने जर्मन गणतन्त्र संघ से इसके बारे में पूछताछ की तथा उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि पाकिस्तान को कोई शस्त्र नहीं दिये जा रहे हैं। बाद में समाचारों से पता चला कि ईरान पश्चिमी जर्मनी से एफ-86 जहाज खरीद रहा है। पिछली जनवरी में भी ईरान स्थिति हमारे राजदूत ने ईरान सरकार के अधिकारियों को बहुत ऊंचे स्तर पर भारत सरकार की पाकिस्तान को एफ-86 हवाई जहाज देने के फलस्वरूप होने वाली आशंका व्यक्त की। उसके तुरन्त बाद पश्चिमी जर्मनी की सरकार को एक औपचारिक नोट भेजा गया जिसमें उन जहाजों के पाकिस्तान भेजे जाने के बारे में स्पष्ट रूप से भारत सरकार की आशंकाओं को व्यक्त किया गया। सरकार ने कनाडा की सरकार से भी दूतावास द्वारा सम्पर्क

रखा । दोनों सरकारों ने हमें आश्वासन दिया कि बेचने सम्बन्धी समझौते के अनुसार पश्चिम जर्मनी सरकार द्वारा भेजे गये जहाज किसी तीसरे देश को नहीं दिए जा सकते ।

एफ-86 विमानों का पाकिस्तान पहुंचने का पता जब हमें कुछ मास पूर्व लगा तो हमने पश्चिमी जर्मनी तथा ईरान की सरकारों से कड़ा विरोध किया । हमें ईरान ने आश्वासन दिया कि जो भी हवाई जहाज ईरान से पाकिस्तान भेजे गये हैं, वह केवल मरम्मत, सफाई तथा कुछ रूपभेद के लिये भेजे गये हैं क्योंकि यह सुविधा ईरान में उपलब्ध नहीं है ।

कनाडा सरकार ने कनाडा के बने हुए हवाई जहाज ईरान को आगे बेचने के विरुद्ध मत व्यक्त किया । जर्मन गणतन्त्र संघ ने हमें सूचित किया कि उन्होंने ईरान सरकार से इस बारे में बातचीत करली है कि वह ये जहाज पाकिस्तान से वापस लें । ईरान सरकार ने यह बात फिर दोहराई कि जो विमान पाकिस्तान भेजे गये थे वह केवल मरम्मत सफाई तथा परिवर्तन के लिये भेजे गये तथा वहां से वापिस लिये जायेंगे । हमें ईरान सरकार ने सूचित किया है कि उनमें से कुछ हवाई जहाज तो पहले ही पाकिस्तान से ईरान वापिस पहुंच गये हैं ।

हमने सम्बन्धित सरकारों को अपनी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है कि 90 एफ-86 विमानों का पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अथवा तीसरे देशों द्वारा हस्तान्तरित किये जाने से अनिवार्य रूप से पाकिस्तान की सैनिक शक्ति भारत के विरुद्ध बढ़ेगी तथा इसके परिणामस्वरूप भारत के उन देशों के सम्पर्क पर जो इन सौदों में भाग लेंगे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । हम इस सम्बन्ध में अपने प्रयत्न जारी रखेंगे कि विमान लौटाये जायें ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether Government have information regarding the extent of U. S. military aid to Pakistan.

Mr. Speaker : This question has no hearing on the notice given by the Hon. Member.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : There is a reference to this effect in the Call Attention Notice.....

अध्यक्ष महोदय : जब श्री ओंकार लाल बेरवा प्रश्न पूछ रहे हैं तो श्री कछवाय क्यों खड़े हो रहे हैं ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : ***

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में शामिल नहीं होगा ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether after these planes have been returned to the said country, the Government would ascertain whether these are the same planes and not the bare frames ?

श्री स्वर्ण सिंह : सम्बद्ध देशों ने हमें पक्के आश्वासन दिये हैं और हमें यह देखना है कि वे आश्वासन पूरे होते हैं अथवा नहीं ?

***कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

***Not recorded

Shri Yashpal Singh : This Government do not make the country strong and go on begging****

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether there was no friendly country which could have checked these planes from coming from Iran to Pakistan.

श्री स्वर्ण सिंह : विमान को यदि ईरान से पाकिस्तान लाना हो तो किसी अन्य देश के ऊपर से उड़कर नहीं आना पड़ता ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): May I know the terms on which Canada gave these planes to West Germany and then West Germany gave them to Iran?

श्री स्वर्ण सिंह : यह स्पष्ट किया गया था कि जो देश पश्चिमी जर्मनी से विमान खरीदेगा वह उन्हें किसी अन्य देश को नहीं देगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर)) : क्या पश्चिमी जर्मनी ने दूसरी किश्त में तेहरान को और विमान देने के सम्बन्ध में ओटावा से पूछा है और मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या हमने इस सम्बन्ध में अमरीका से भी पूछताछ की है?

श्री स्वर्ण सिंह : ईरान को और विमान देने की स्वीकृति नहीं दी गई है। कनाडा द्वारा विमान बेचने पर अमरीका का कोई नियंत्रण नहीं है। सम्बद्ध सरकारों से हमने इस मामले में बातचीत की थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि यह विमान वापिस मंगवाये जायेंगे। मुझे तसल्ली है कि इस बारे में हम अधिक से अधिक जो कार्यवाही कर सकते थे, वह हमने की है ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : इस विवाद के दौरान पश्चिमी जर्मनी के चुप रहने का कारण क्या यह है कि हमारे प्रधान मंत्री के रूस के दौरे के बाद जो संयुक्त भारत-रूस प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें दो जर्मन-राष्ट्रों का होना स्वीकार किया गया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह स्वीकार नहीं करता कि वह इस कारण से चुप है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : ईरान इन विमानों को कब तक वापिस लेगा और क्या पाकिस्तान में इनकी मरम्मत हो सकती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे भी इसमें सन्देह है कि पाकिस्तान में इनकी मरम्मत हो सकती है। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने बहाना बनाया है और यही कारण है कि हम सम्बद्ध देशों को विश्वास दिला सकें कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये और विमान वापिस मंगवाने चाहिये। समय बतायेगा कि यह आश्वासन कहां तक पूरे होंगे।

****कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

****Not recorded

Shri Bade (Khargone) : May I know whether Government has obtained a guarantee to the effect that these planes would not be sent in small batches again to Pakistan Secretly.

श्री स्वर्ण सिंह : अन्य देश भी सम्पूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न देश हैं। हम उनसे हर प्रकार की गारंटी नहीं मांग सकते।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of planes out of those destroyed in the last Indo-Pak conflict which Pakistan could repair properly.

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि फिर ऐसा हुआ तो क्या सरकार ईरान तथा पश्चिमी जर्मनी से राजनयिक सम्बन्ध तोड़ेगी ?

अध्यक्ष महोदय :यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री दाजी (इन्दौर) : यह डर बना रहता है कि यदि यह विमान भी वापिस कर दिए जायें तो भी इनसे महत्वपूर्ण पुर्जे निकाले जा सकते हैं। क्या सरकार ने यह तसल्ली कर ली है कि दिए गए स्पष्टीकरण उचित हैं ? क्या सरकार यह मामला गम्भीर रूप से उठायेगी ताकि यह घटना दोबारा न हो।

श्री स्वर्ण सिंह : हमने यह मामला गम्भीर रूप से ही उठाया है। मैंने पहले भी कहा है कि हमें आशा है कि यह आश्वासन पूरा किया जाएगा।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आदेश तथा अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2314 की एक प्रति जो दिनांक 30 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गयीं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6995/66]**

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ग्यारह) के अन्तर्गत जारी किये गये निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :-

(एक) एस० ओ० 2381 जो दिनांक 8 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सोड़ा ऐश टार्चों और हरीकेन लालटेनों के लिये ड्राई सेलों को अत्यावश्यक वस्तुएं घोषित किया गया।

(दो) एस० ओ० 2511 जो दिनांक 17 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा साईकिल रिक्शा टायरों और टयूबों को अत्यावश्यक वस्तुएं घोषित करने के लिये दिनांक 14 जून, 1966 के आदेश में संशोधन किया गया।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6996/66]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं उपर्युक्त मद (एक) तथा (दो) में उल्लिखित वस्तुओं के बारे में सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन वस्तुओं को अत्यावश्यक घोषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया था कि यह वस्तुयें पर्याप्त मात्रा में बाजार में उपलब्ध हों ?

श्री शफी कुरेशी : जी हां, श्रीमान्।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रमाणित लेखे

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं श्री अलगेसन की ओर से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1964-65 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6997/66]

रबड़ (तीसरा संशोधन) नियम, 1966

श्री शफी कुरेशी : मैं रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रबड़ (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 20 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1281 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6998/66]

सदस्य की गिरफ्तारी
(श्री बीरेन दत्त)
ARREST OF MEMBER
(Shri Biren Dutta)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, अगरतला से दिनांक 1 सितम्बर, 1966 को निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है :

"लोक सभा के सदस्य श्री बीरेन दत्त को भारतीय प्रतिरक्षा नियम, 1962 के नियम 41 के उपनियम (5) के अन्तर्गत 1 सितम्बर, 1966 को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हे नौ दिन के लिये केन्द्रीय जेल अगरतला में रखा गया है।"

सदस्य की पैरोल पर रिहाई

(श्री याज्ञिक)

RELEASE ON PAROLE OF A MEMBER

(Shri Indulal Yajnik)

अध्यक्ष महोदय :मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे गृह-सचिव, गुजरात सरकार, अहमदाबाद से दिनांक 1 सितम्बर, 1966 को निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है :

"निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत बड़ौदा केन्द्रीय कारागार में निरुद्ध लोक-सभा के सदस्य श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक को 2 सितम्बर, 1966 से छः दिन के लिये पैरोल पर रिहा किया जा रहा है।"

श्री दाजी (इन्दौर): कल ही गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि वह गुजरात सरकार को सलाह देगें कि उन्हें रिहा कर दिया जाय परन्तु इसके बावजूद भी उसने उन्हें पैरोल पर रिहा किया है। क्या यह ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय :मुझे जो तार प्राप्त हुआ था वह मैंने पढ़ दिया है।

त्रिपुरा में उपद्रवों के बारे में

RE: DISTURBANCES IN TRIPURA

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री ने त्रिपुरा में उपद्रव के बारे में 1.9.66 को जो वक्तव्य दिया था उस पर प्रश्न पूछे जाने हैं। मेरा विचार है कि यह विषय 4.45 म० प० पर लिया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): यदि अभी प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये तो सदस्यों को सुविधा रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्यों की सुविधा का प्रश्न है तो प्रश्न अभी पूछे जा सकते हैं

Shri Madhu Limaye (Monghyr): You had observed that Shri Madhu Limaye or Shri Pattnayak might explain how they allege failure on the part of the Government.

Mr. Speaker : I cannot permit it now.

Shri Madhu Limaye : I was asked not to raise that question yesterday.

अध्यक्ष महोदय : कोई औचित्य प्रश्न इत्यादि नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। केवल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वक्तव्य का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं। मंत्री महोदय सब कुछ जानते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : उनकी रिपोर्ट के अनुसार तीन व्यक्ति मरे हैं, लाठी चार्ज हुआ और अश्रु गैस का प्रयोग हुआ। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें कुछ विधान

मंडल के सदस्य भी थे । गिरफ्तार होने वालों में वाम और दक्षिण दोनों पक्ष के साम्यवादी लोग थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले की कोई न्यायिक जांच की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : किसी भी राजनैतिक दल को दबाने का प्रयास नहीं किया गया । स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है और यदि आवश्यकता हुई तो अवश्य जांच की जायेगी ।

श्री दाजी : इस सारी दुर्घटना को मूल्यों की वृद्धि की पृष्ठभूमि को सामने रख कर सोचा जाना चाहिए । चावल की कमी के कारण विद्यार्थी भी भड़क उठे थे । यह बहुत ही खेद-जनक है कि विद्यार्थियों के साथ सशस्त्र पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया । छोटी सी बात के लिए तीन जीवन नष्ट हो गये । अब और क्या औचित्य सिद्ध किया जा सकता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह बात कल अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दी थी कि सारी बात एक छोटी सी घटना को लेकर हुई थी । एक सिपाही और एक काला बाजार में सिनेमा की टिकटें बेचने वाले एक व्यक्ति के बीच झगड़ा हो गया था । इससे मामला बढ़ गया । मूल्यों की बृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं था ।

Shri Bade (Khargone) : I want to know whether the persons arrested were indulging in exciting the people or they were arrested only on the ground that they were Communists. Whether some judicial inquiry is being instituted ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have said that the matter is being assessed.

श्री स्वैल : मैं इस सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि इस मामले को साधारण पुलिस के काम को 'आसाम राइफल्ज' ने अपने हाथ में क्यों लिया ? सरकार इस क्षेत्र के असैनिक नागरिकों और सुरक्षा सैनिकों के सम्बन्धों को अच्छा बनाने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार ने इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार किया है । बात यह है कि आसाम राइफल्ज का कोई सिपाही सिनेमा देखने गया और वहां टिकटों के काला बाजार के कारण उसका किसी से झगड़ा हो गया ।

Shri Madhu Limaye : The Minister says that firing was resorted to in order to dispel the unlawful assembly, I want to know whether Government have value in their eyes of the human lives thus lost ?

Shri Vidya Charan Shukla : The crowd was already there and it became violent. The crowd not only burnt the belongings of Textile Depot but also entered the assembly and tried to grapple with the Chief Minister. Those who molested the Chief Minister also included some M. Ps. and M. L. As. Following this a series of incidents took place.

श्री अ० क० गोपालन : मैं यह जानना चाहता हूं, दो संसद सदस्यों के विरुद्ध आरोप क्या हैं । उनके त्रिपुरा पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने बता दिया है कि दो संसद सदस्य भीड़ के साथ विधान सभा भवन में घुस गये और मुख्य मंत्री से हाथापाई करने लगे। एक व्यक्ति को पहले और दूसरे को कुछ देर बाद गिरफतार किया गया।

श्री नम्बियार : मेरा औचित्य प्रश्न है। मंत्री महोदय कहते हैं कि दोनों संसद सदस्यों ने भीड़ के साथ विधान सभा भवन में प्रवेश किया और मुख्य मंत्री से हाथापाई की। यह विशेष प्रकार के आरोप हैं। उन्होंने यह नहीं कहा है ; ज्ञात हुआ है कि उन्होंने ऐसा किया अपितु उन्होंने निश्चयात्मक रूप से आरोप लगाया है अतः यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने वही जानकारी दी है जो कि उन्हें दी गई है। उनके पास जानकारी प्राप्त करने का कोई अन्य साधन तो है नहीं केवल त्रिपुरा के अधिकारी ही हैं।

श्री रंगा : मैं इस बात का समर्थन करता हूं जो कि श्री नम्बियार ने कही है। सदस्यों के विरुद्ध आरोप लगाना अनियमित भी है और अनुचित भी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे विचार में माननीय सदस्य इसे समझने का प्रयास करेंगे कि यह जानकारी मुझे त्रिपुरा सरकार से प्राप्त हुई है। और उसके आधार पर ही मैं यह कह रहा हूं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह मामला गम्भीर है। दो माननीय संसद सदस्यों पर आरोप है कि उन्होंने मुख्य मंत्री से हाथापाई की। माननीय सदस्य तो यहां हैं नहीं कि इन आरोपों का उत्तर दे सकें। वहां अधिकारियों ने भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार किया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे ये आरोप सिद्ध नहीं कर सकते। उनके विरुद्ध ये आरोप सिद्ध करने होंगे।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या मंत्री महोदय के लिये हर बार यह कहना जरूरी है कि वह राज्य सरकार की जानकारी के आधार पर वक्तव्य दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो केवल गिरफ्तारी की ही जानकारी प्राप्त होती है। विस्तार से सारी स्थिति नहीं बताई जाती।

श्री ही० ना० मुकर्जी : ये गिरफ्तारियां भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत क्यों की गईं।

श्री कपूर सिंह : मुख्य प्रश्न जो हमें परेशान कर रहा है, वह यह है कि मुख्य मंत्री से हाथापाई भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कैसे आ गई ?

Shri Bagri ; This whole incident is a clear breach of privilege.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा औचित्य का प्रश्न है। बस्तर के मामले में जब श्री नन्दा ने यह कहा था वह सब इन्सपैक्टर की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो हमने इसका विरोध किया था। आपने कहा था कि यह रिपोर्ट मध्यप्रदेश सरकार और पुलिस से प्राप्त हुई है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री गोपालन का प्रश्न बहुत सीधा था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है ? माननीय उपमंत्री ने जो कुछ कहा है, अर्थात् यह कि उन्होंने मुख्य मंत्री से दुर्व्यवहार किया है, इस सभा के एक माननीय सदस्य के आचरण पर आक्षेप है। उन्होंने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और मेरा निवेदन है कि नियम 227 के अन्तर्गत इसे समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है जिसके बारे में मुझे निर्णय करना है।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मंत्री महोदय ने कल स्पष्ट रूप से कहा था कि वह सूचना सभा-पटल पर रखने के लिये तैयार हैं। यदि उन्होंने उस सूचना के अनुसार जानकारी दी है तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने क्या गलती की है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने त्रिपुरा सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा है। जहां तक भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत सूचना का सम्बन्ध है, उसकी सूचना आपको दी जा चुकी है। संसद सदस्य को भारत रक्षा नियमों के नियम 41 (5) के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

श्री नम्बियार : क्या सरकार इस समूचे मामले की जांच करेगी।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

Shri Vishwa Nath Pandey : (Salempur) : The persons who have indulged in this affair, caused a loss to the telephone exchange, Central bureau and cottage industries emporium. May I know whether the communists had a hand in this conspiracy?

Shri Vidya Charan Shukla : According to the information available from Tripura Government, left wing of the Communist party had a hand in this matter.

Shri Kishan Pattnayak : Will the Government seriously consider not to use border security force in the killing of people living on the border? Whenever such a thing happens, Judicial enquiry should be conducted by the Central Government.

Shri Vidya Charan Shukla : We will consider this matter.

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय ने इसे हल्का सा लाठी चार्ज बताया है। यह लाठी चार्ज हल्का नहीं बल्कि बड़ा लाठी चार्ज था।

क्या मंत्री महोदय केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से बनाये गये आचरण संहिता के बारे में जानते हैं जिसमें पुलिस द्वारा लाठी चार्ज अथवा गोली चलाने से पहले की शर्तें निश्चित की गई हैं। क्या इस संहिता को गृह-कार्य मंत्रालय लागू करेगा। मामूली आरोपों के कारण दो संसद सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चोर बाजार करने वालों को भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : चोर बाजार करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। वास्तव में उसे थाने ले जाते समय ही यह स्थिति उत्पन्न हुई। हम आचार संहिता का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। घायल हुये व्यक्तियों में से अधिकांश पुलिस वाले थे।

खाद्य मंत्री द्वारा अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये खाद्यान्नों में लोहे के टुकड़े तथा कंकड़ आदि के पाये जाने के बारे में दी गई जानकारी के संबंध में वक्तव्य तथा इस बारे में मंत्री महोदय का उत्तर

STATEMENT RE: INFORMATION GIVEN BY FOOD MINISTER ON PRESENCE OF FOREIGN MATTER IN FOODGRAINS FROM U. S. A. UNDER P. L. 480 AND MINISTER'S REPLY THERETO

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष के निदेश 115 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान खाद्य तथा कृषि मंत्री, श्री चि० सुब्रह्मण्यम द्वारा दिये गये विभिन्न गलत तथा भ्रामक कथनों की ओर दिलाता हूं।

1. **लिबर्टी पोत :** जब यह पूछा गया कि क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात लिबर्टी पोतों में रखे खाद्यान्न से कम से कम आंशिक रूप में किया जाता है तो मंत्री महोदय ने नकारात्मक उत्तर दिया। यह पोत खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के भण्डार जमा करने के लिये रखे गये हैं।

2. **पुराना माल :** खाद्य मंत्री का यह कथन गलत है कि यह माल पिछले वर्ष अथवा इस वर्ष की उपज का है। वह कम से कम चार अथवा पांच वर्ष पुराना है।

3. **उपहार अथवा क्रय :** श्री सुब्रह्मण्यम का यह वक्तव्य ठीक नहीं है कि पिछले कुछ माल के दौरान आयातित आटा अथवा मैदा विभिन्न देशों से उपहार में मिला है, गलत है। जो वस्तु स्पष्ट रूप से मानवीय उपभोग के लिये योग्य नहीं है, उसे बेचने का प्रयत्न क्यों किया जाये।

4. **नानबाइयों को बाध्य करना :** महाराष्ट्र तथा दिल्ली के नानबाइयों ने शिकायत की है कि उन्हें वीवल कीड़ों वाला आटा तथा मैदा खरीदने पर बाध्य किया जाता है।

5. **मैदे का धूमीकरण :** मंत्री महोदय ने मेरे इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या दिल्ली में मैदे का धूमीकरण किया गया अथवा नहीं; उनका यह वक्तव्य गलत है कि इसमें से अधिकांश का उपभोग पहले ही किया जा चुका है।

6. **वीवल का अभिजनन कैसे होता है :** खाद्य मंत्री ने इस बारे में डा० लोहिया के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। धूमीकरण से वीवल तो मर जाते हैं परन्तु अण्डे नहीं।

7. **निरीक्षण :** इस बारे में श्री सुब्रह्मण्यम का वक्तव्य बिलकुल गलत है। पिछले 5 अथवा 6 वर्षों से भारतीय सम्भरण मिशन में निरीक्षण के कोई कर्मचारी नहीं हैं।

8. **पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न में अन्य वस्तुयें पाया जाना :** खाद्य मंत्री का यह वक्तव्य पूर्णतया ठीक नहीं है कि खाद्यान्न में लोहे के टुकड़े आदि वस्तुएं पोत की दीवारों को जंग

लगने के कारण मिले हैं । उसमें मोटर कारों के पुर्जे आदि पाये गये हैं। यह स्पष्ट है कि यह वस्तुएं जान बूझ कर डाली गई हैं ।

खाद्य मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : श्री मधु लिमये तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा उठाये गये मामलों के उत्तर में मैं निम्नलिखित तथ्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं :—

1. **लिबर्टी पोत** : उन पोतों में रखा गया माल नहीं भेजा गया है ।

2. **पुराना माल** : जैसा कि मैंने पहले बताया था, परीक्षणों से पता चला है कि अधिकांश खाद्यान्न पिछले एक अथवा दो वर्ष के उत्पादन में से हैं ।

3. **उपहार अथवा क्रय** : पिछले कुछ महीनों के दौरान मिलने वाला आटा तथा मैदा उपहार में मिला था । सरकार को जो भी आटा और मैदा प्राप्त होता है उसका विश्लेषण किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के बाद, कि वह मानवीय उपभोग के लिये उचित है, बेचा जाता है ।

4. **नानबाइयों को बाध्य करना** : यह ठीक नहीं है कि यह आटा तथा मैदा गला सड़ा था अथवा उसमें कीड़े थे । नानबाई इटली का मैदा लेने से इस कारण हिचकिचाते थे क्योंकि उसमें जल मिलाने की क्षमता कम थी । देश में पिसे आटे को मिलाने से डबल रोटी ठीक बनती है ।

5. **मैदे का धूमीकरण** : विशेषज्ञों ने मुझे बताया है कि मैदे अथवा आटे का धूमीकरण किया जा सकता है ।

6. **वीवल का अभिजनन कैसे होता है** : यह ठीक नहीं है कि धूमीकरण से अण्डे नष्ट नहीं होते हैं ।

7. **निरीक्षण** : यह ठीक है कि अमरीका में हमारे सप्लाई मिशन में खाद्यान्न की किस्म का निरीक्षण करने के लिये कर्मचारी नहीं हैं । जब इस बात की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया तो मैंने 19-8-66 को लोक सभा सचिवालय को एक वक्तव्य भेजा जो मैं सभा में देना चाहता था । यह कहना ठीक नहीं है कि अमरीकी निर्यातक निम्न कोटि का माल भेजते हैं । वर्तमान प्रबन्ध सन्तोषजनक समझे गये हैं और यह अनुभव किया गया है कि निरीक्षण के लिये अपनी व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है ।

8. **पी० एल० 480 खाद्यान्न में अन्य वस्तुयें पाया जाना** : इन वस्तुओं के नमूनों से यह विचार ठीक मालूम होता है कि यह वस्तुएं पोत में से आई हैं, बाहर से नहीं । इस विचार में कोई सार दिखाई नहीं देता कि यह वस्तुएं कुछ शरारती लोगों ने जान बूझ कर डाली हैं ।

———

औरडिगनम एण्ड कम्पनी पर छापों के बारे में
RE: RAIDS ON THE PREMISES OF ORRDIGNUM AND CO.

श्री दाजी इंदौर : कल एक बहुत गम्भीर प्रश्न उठाया गया था और आपने उसके सम्बन्ध में अपना विनिर्णय देने के लिए कहा था।

अध्यक्ष महोदय : संबंधित पत्र पढ़ने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि जांच की कार्यवाही में बाधा डाली गई है। वह इस सम्बन्ध में सोमवार को एक वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री को सूचित कर दिया जाये कि वह सोमवार को वक्तव्य दें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Shri R. C. Dutt, Secretary had asked the Enforcement Directorate to report on the following matters;

"The specific provisions of the law under which the searches were conducted to the extent; if any, to which the approval of the Headquarters was obtained...."

Which means whether the permission of the Ministry has been taken or not. They could have arrested Dr. Teja, but they referred it to the Ministry out of fear.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—जारी
REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे।

श्री सेझियान (पैरम्बलूर) : प्रस्ताव में एक छपाई की गलती है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां संख्या 10 के बजाय संख्या 12 होनी चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरे विचार में विचार करने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं किया गया है।

संसद कार्य तथा संचार विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : समय को 3 बजे तक बढ़ा दिया जाये। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य 3 बजे लिया जा सकता है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी): कल मैं बता रहा था कि किस प्रकार त्रुटिपूर्ण निर्वाचन कानून के कारण एक अल्पमत प्राप्त सरकार चल रही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

विधिमंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन की 25 प्रतियां लोक-सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। मैं अधिक प्रतियां प्राप्त नहीं कर सका, अन्यथा मैं अधिक प्रतियां भेज देता।

श्री प्र० के० देव : यह दुर्भाग्य है कि देश में इतनी राजनैतिक पार्टियां हैं। मुझे आशा है कि राजनैतिक विचारधारा के आधार पर केवल दो अथवा तीन पार्टी पद्धति ही रह जायेगी। निर्वाचन आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ 124 पर इसी बात पर बल दिया है।

(1) यह आवश्यक है कि चुनाव कुछ योग्य उम्मीदवारों में होना चाहिए और ऐसे उम्मीदवारों को जिनको कि कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पैरा (iii) में आयोग ने कहा है कि :

"कई स्वतन्त्र उम्मीदवार केवल इसलिए खड़े होते हैं कि किसी अन्य उम्मीदवार से रुपया लेकर बैठ जायें या जाति भेद का फायदा उठाकर वोट बाट दिये जायें।"

सरकार ने सिफारिश के इस भाग को स्वीकार नहीं किया क्योंकि जितने अधिक उम्मीदवार होंगे उतना ही कांग्रेस को लाभ होगा। सरकार को सारी पद्धति में आमूल परिवर्तन करना चाहिए।

जहां तक निर्वाचक अधिकारियों का सम्बन्ध है, निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि मुख्य निर्वाचक अधिकारी और उप-मुख्य निर्वाचक अधिकारी पूर्ण समय के लिए उसी कार्य के लिए होने चाहिए। कुछ राज्यों में अवर सचिव अथवा सचिव इस कार्य को आंशिक रूप से करते हैं। यह अधिकारी सरकारी दबाव के परे होने चाहिए और निर्वाचन आयोग को उत्तरदायी होने चाहिए। यह और भी अधिक अच्छा होगा यदि इन अधिकारियों को न्यायालयों से भर्ती किया जाये।

निर्वाचन आयोग ने और आगे सिफारिश की है कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी होने चाहिए। सरकार ने इस सिफारश को स्वीकार कर लिया है। जिला दण्डाधिकारियों को जो निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) के रूप में सामान्यत: कार्य करते हैं, अधिक अधिकार देना बहुत ही खतरनाक है। इस सम्बन्ध में मैं दाण्डेकर बनाय आर० आर० गुप्ता के केस में न्यायाधिकरण के निर्णय का उल्लेख करना चाहता हूं। निर्णय में कहा गया था कि श्री सी० एम० निगम, जिला दण्डाधिकारी, गोण्डा ने श्री राम रतन गुप्ता को चुनाव जीतने में सहायता की थी और इसके परिणामस्वरूप उनको फैजाबाद डिवीजन का कमिशनर बना दिया गया था।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : चूंकि इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई है, अत: इस निर्णय का हवाला देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

श्री अ० सि० सहगल (जंजगीर) : इसकी अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री प्र० के० देव : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि निर्णय न्यायाधिकरण का है। मेरा निवेदन यह है कि केवल उन अधिकारियों को यह कार्य सौंपा जाये जो पदोन्नति के लिये सरकार पर निर्भर नहीं हैं।

यह बहुत अच्छा है कि अब से जम्मू और काश्मीर से भी सदस्य निर्वाचित किये जाएंगे। परन्तु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जम्मू और काश्मीर के लिये पृथक नामावली क्यों बनाई जा रही है। जम्मू और काश्मीर की निर्वाचन नामावली स्थायी निवास आधार पर बनाई जा रही है मुझे समझ में नहीं आता है कि जम्मू और काश्मीर के लिये बाकी भारत से पृथक नामावली क्यों बनाई जा रही है।

निर्वाचक नामावली का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण किया जाना चाहिये।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : क्या जम्मू और काश्मीर के लिये पृथक आधार होना चाहिये क्योंकि वहां स्थिति अस्थिर और अनिश्चित है।

श्री प्र० के० देव : मतदाताओं को किसी वाहन द्वारा ले जाने के लिये बहुत कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार सबसे अधिक दोषी है। चुनावों के दौरान ब्लाक जीपों का प्रयोग किया जाता है। इस सभा में यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि निर्वाचन से तीन महीने पहले सभी ब्लाक जीपें वापस ले ली जायेंगी।

मूल अधिनियम की धारा 7 डी में यह दिया हुआ है कि यदि निर्वाचन के समय किसी ठेकेदार ने ठेका समाप्त नहीं किया तो चुनाव नहीं लड़ सकता।

अब सरकार द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा यदि निर्वाचन के समय किसी ठेकेदार ने कार्य पूरा कर लिया है परन्तु उसको अन्तिम भुगतान नहीं किया गया तो वह चुनाव लड़ सकता है। सरकार ठेकेदारों पर अपना दबाव रखना चाहती है जिससे यदि कोई ठेकेदार चुनाव लड़े तो वह उस पर दबाव डालकर उसको बैठने के लिये बाध्य करे, और यदि वह जीत जाये तो भी उनके दबाव में रहेगा। कुछ समय पश्चात इस सभा में ठेकेदार ही रह जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य दलों के लोगों को भी बोलना हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : विरोधी दलों में मेरा दल सबसे बड़ा है और इस कारण हमें कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिये। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिये हमें कम से कम 15 मिनट का समय दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें 3 बजे चर्चा बन्द कर देनी है। मैं सभी दलों का सहयोग चाहता हूं।

श्री प्र० के० देव : मेरा निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार का सूत्र पंचायती राज से होता है। पंचायती राज में सरपंच ठेकेदार का काम करता है और पंचायत समिति के सभापति से लाभ बांट लेता है।

तत्पश्चात्, न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय दिये जाने के पश्चात्, उच्च न्यायालय भी न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है। कोई भी सम्मानित उच्च न्यायालय इस रूप में कार्य करना पसन्द नहीं करेगा कि निर्वाचन आयोग उसके फैसले की जांच करे।

एक उप-मंत्री के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसने निर्वाचन बहुत ही अनैतिक ढंग से लड़ा। परन्तु निर्वाचन आयोग ने उसे दोबारा निर्वाचन लड़ने की इजाजत दे दी। बैलट पेपर नासिक सिक्योरिटी प्रेस में छापे जाने चाहिये। अन्यथा चुनावों में जाली बैलट पेपर प्रयोग में लाये जा सकते हैं। सरकार ने निर्वाचन आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव एक ही दिन में समाप्त हो जाने चाहिये। सरकार को अपने खर्च पर मतदाताओं को परिचय पत्र देने चाहिये जिससे वेश बदल मतदान न किया जा सके।

खण्ड 59 में दिया हुआ है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी निर्वाचन एजेन्ट के रूप में कार्य करेगा तो उसे 500 रुपया जुर्माना होगा। परन्तु प्रचार करने के विरुद्ध कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिये भी उनको भारी जुर्माना किया जाना चाहिये।

निर्वाचन से तीन महीने पहले सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये और राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाना चाहिये।

यदि सरकार इस प्रस्थापना को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है तो यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि मंत्रियों द्वारा पदोन्नति, भूमि का आवंटन, विद्यालयों को मान्यता देना, गैर-सरकारी सम्पत्ति का विक्रय, विचाराधीन मुकदमों को वापस लिया जाना तथा अपने विवेकाधीन अनुदान का उपयोग करना इत्यादि के बारे में आदेश न निकाले जायें।

सरकारी अधिकारियों को मंत्रियों के चुनाव अभियानों में उनके साथ नहीं जाना चाहिये। सरकारी कर्मचारी मंत्रियों के साथ जाते हैं। यह सब बन्द होना चाहिये।

अन्त में मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहता हूं कि राजनैतिक सौदेबाजी बन्द कर दी जानी चाहिये। उड़ीसा में हमारा अनुभव यह रहा है कि जब विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं तो उनसे पक्षपात करके उन्हें 'खरीद' लिया जाता है। यह बन्द होना चाहिये।

ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिये कि यदि किसी टिकट विशेष पर निर्वाचित विधान सभा का कोई सदस्य अपना दल बदले अथवा अपने सम्बन्ध को बदले तो उसे निर्वाचित स्थान छोड़ना पड़े। जब तक ऐसा नहीं होगा तो मतदाताओं की इच्छा के विरुद्ध परिणाम निकलेगा और फिर निर्वाचित सदस्य को बदला भी नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उमानाथ।

श्री हरि विष्णु कामत : नियम 292 के अन्तर्गत मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक के लिये जो समय नियत किया गया है वह बढ़ाकर कम से कम तीन घन्टे कर दिया जाये।

श्री त्यागी : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने 1.30 बजे आरम्भ किया था। अतः 1.30 बजे से तीन घंटे गिने जायेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : इस प्रकार यह कल समाप्त होगा, आज नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल सभा ने यह निश्चय किया था कि सरकारी कार्य 3 बजे तक होगा। अतः आज 3 बजे तक यह चलेगा। शेष कल होगा।

श्री काशी राम गुप्त : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। तीन घण्टे से आपका मतलब 3 घण्टों में वह समय भी शामिल है जो ले लिया गया है। इस विधेयक के लिये 5 घण्टे चाहिये। इस प्रकार 5 घण्टे और 3 घण्टे कुल 8 घण्टे हुये।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। 1.30 बजे से 3 घण्टे गिने जायेंगे और इस विधेयक के लिये इतना ही समय रहेगा।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : वर्तमान विधेयक को पुरःस्थापित करके सरकार ऐसा दिखावा कर रही है मानो कि वह चुनाव के लिये प्रक्रिया को और लोकतंत्रीय बनाने का प्रयत्न कर रही है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि इस बात का पता लगाने के लिये कि सरकार वास्तव में चुनावों की प्रक्रिया को लोकतंत्रीय बनाना चाहती है या नहीं, जो कसौटी है वह यह कि इन दो निर्णायक प्रश्नों पर सरकार का रवैया है। एक प्रश्न यह है मत प्राप्त करने के लिये सरकारी प्रभाव का प्रयोग करना तथा दूसरा प्रश्न है मत खरीदने के लिये धन देना। प्रश्न यह है कि इन दो बातों के बारे में अधिनियम में और संशोधन करने के लिये विधेयक में क्या उपबन्ध हैं ? कदाचार नहीं होना चाहिये। मतों को धन द्वारा अथवा दबाव से नहीं खरीदा जाना चाहिये। पंचायत बोर्डों को प्रभावित करके कांग्रेस दल के लिए मत प्राप्त करने के लिये सरकारी शक्ति का प्रयोग करना ठीक नहीं है। कांग्रेस दल इस कदाचार का विरोध नहीं करता क्योंकि उसे इसी में लाभ है।

दूसरी बात यह है कि मतदाताओं को धन देकर मत लेना कदाचार घोषित हो चुका है, फिर भी भारी धनराशि इस प्रकार रिश्वत के रूप में दी जाती है। सरकार इस प्रकार की रिश्वत को नहीं रोक सकी है। अतः यदि कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दी जाने वाली रकम पर रोक लगा दी जाये तो रिश्वत बन्द हो सकती है। सरकार ने इस बारे में निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार नहीं किया है। आयोग ने तीन सिफारिशें की थीं। प्रथम यह कि राजनैतिक दल द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव पर जो व्यय किया जाता है उसे उनके खाते में शामिल नहीं किया जाता है इसलिये निर्धारित अधिकतम सीमा का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसे ठीक किया जाये। दूसरे, वर्तमान कानून में दो मुख्य कमियां यह हैं कि चुनाव पर व्यय के लेखे की गणना का काम चुनाव से लेकर परिणाम की घोषणा की तारीख तक सीमित है और राजनैतिक दलों के व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। इसे कानून में संशोधन करके ठीक किया जाये।

तीसरे, ऐसा उपबन्ध हो कि उम्मीदवार अथवा उसके एजेन्ट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यय करने पर रोक हो और जब ऐसा अधिकृत व्यक्ति व्यय करे तो उसका हिसाब दे ।

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है ।

इसके पश्चात मैं जाति और पंथ के नाम पर मत मांगने के प्रश्न को लेता हूँ । यह भी कदाचार घोषित किया जा चुका है । निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसमें कमी नहीं हुई है । सरकार इस बारे में कानून के उपबन्धों को लागू नहीं कर रही है । वह खुद जाति और पंथ के नाम पर मत लेना चाहती है । मद्रास राज्य में एक जाति के मंत्री को उसी जाति के मतदाताओं के पास भेजा जाता है । इसीलिए सरकार सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं ।

यद्यपि सरकार ने सवारी के प्रयोग के लिए दंड को 250 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करके तथा मुफ्त सवारी को परिज्ञेय अपराध बनाकर सिफारिश के पहले भाग को स्वीकार कर लिया है । फिर भी इससे कुछ नहीं हो सकता । मतदाताओं को मुफ्त सवारी मिलेगी और यदि पुलिस चालक को पकड़ेगी तो मतदाता कहेंगे कि चालक को उन्होंने अपनी जेब से भुगतान किया है । इस प्रकार मामला वहीं समाप्त हो जायगा । अतः निर्वाचन आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए कि मतदान वाले दिन इन रास्तों पर निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलने वाली बसों के अलावा अन्य सभी वाहनों के चलने पर रोक लगा दी जाए या उनका कड़ाई से विनियमन किया जाए । परन्तु सरकार एक ओर तो भ्रष्टाचार करना चाहती है क्योंकि वह इस सिफारिश को स्वीकार न करके इन वाहनों का प्रयोग करना चाहती है और दूसरी ओर कहती है कि वह व्यवस्था को और लोकतंत्रीय बना रही है । वह केवल ऐसा दिखावा कर रही है । वास्तव में वह लोकतंत्रीय व्यवस्था के विरुद्ध कार्य कर रही है ।

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : This bill has some good points as also some disappointing features. So far as the Tribunals are concerned, they take too much time in deciding matters. Hence, the provision for abolishing these tribunals and instead giving powers to High Court Judges is welcome. I wonder if we have sufficient number of judges so that they may dispose of the cases without any delay.

I want the Honourable Minister to consider the matter regarding returns of expenses. Huge amounts of money are spent and I fail to understand how the returns are submitted that no objections are raised.

It is not possible to assess a candidate's expenditure under the present provision in the Act. Hence some other method should be found out.

I agree with the Swatantra Party's suggestion that the contractors should be dealt with more strictly.

I suggest that a ceiling of income of a candidate should be fixed so that a candidate having more than a fixed limit of income shall not be allowed to contest an election. When a rich candidate contests election, a poor candidate cannot be said to have equality of oppor-

tunity for the former spends lakhs of rupees and influences the voters in his favour. If Government wants to give representation to the rich, then it can do so in Rajya Sabha. There should be some provision in the Act for preventing the rich from purchasing the votes of the poor voters.

Government should ensure that minimum expenditure is made by candidates at the time of elections. After all, where does this money come from ?

This expenditure should be lessened. The voters' slips are printed in lakhs as without them nobody can vote. The work regarding issue of slips should be taken over by the Government. As soon as the names of candidates are finalised, Government should get the names published and give publicity to it. I had expected that provision for it would be made in this Bill but the same is not there.

I am glad that Election Commissioner is assuming greater powers. In Gonda and Balrampur constituency the Election Commissioner ordered the recounting of votes which was illegal. Since now that department is taking more powers, I hope they will use them with prudence. The reason for this is that when these things take place, ordinary people lose faith in elections.

I hope the Hon. Minister will take over the work of distribution of slips.

Shri Tyagi (Dehra Dun) : There is no doubt in it that at many places the people used the Government machinery for political purposes. I therefore want the Hon. Minister to keep this thing in mind when the matter comes up in the Select Committee, we should in this respect agree to the suggestion of opposition also. I therefore request that every comment of the opposition should be considered because whatever they are saying at the moment is from the point of view of election law.

One thing due to which I feel that democracy itself is in danger is in the use of Government servants for election purpose. Therefore there should be a law so that Government machinery may not be used for a political party and no political leader may use it for his purpose. I want that if it is done the law should provide that the Government servant should be sent to jail if he has allowed some officer to work for some candidate or the other. If this is not done, the Government is to blame for it. Not only the Government servant but the person who uses the Government servant should both be sent to jail. Mere imposing fine on them is not sufficient. Because I myself belong to the party in power and am ashamed on the happenings of the past. Therefore, we should leave it to the opposition to have a law of their choice.

I also agree that the list of voters should be prepared by the Government and the work of publicity should also be done by them. They should not tell as to whom the vote should be cast.

I request the Minister to agree to the demand of the opposition.

Shri Bade (Khargone) : Mr. Deputy-Speaker the important recommendations of the Election Commission have not been accepted. The Government has not accepted the recommendation relating to election expenditure, increase in security deposit, multiplicity of candidates and deposit in connection with Presidential election.

The provision regarding election expenditure is altogether bogus. In Madhya Pradesh there are 64 seats reserved for Adivasis. They are illiterate people. How can they maintain

the account of election expenses? Hence the provision about this is wholly wrong. Can Congress party say honestly that their candidates spend only that amount which the party sanctions to them? I think the Government should control the election expenses. The late Dr. Rajendra Prasad in his last speech had stated that if the election expenses continued mounting as at present no poor person would be able to get himself elected. Only the candidates of big businessmen and capitalists will be able to win in election. The Rajas and Maharajas get congress ticket and are exploiting the situation. I have learnt that the Maharaja of Gwalior, the Maharaja of Indore and Maharani of Narsinghgarh are seeking election on Congress ticket. They are doing it because they know that they can spend that only as congress candidates. So the Government should make all arrangements for elections.

Then there is a provision about avoiding multiplicity of candidates in elections. My suggestion is that only those candidates should be treated as elected who secure 50 per cent. of the votes. Those who secure less than 50 per cent. votes should be asked to seek election again. Those who obtain less than 30 per cent. votes should not be given ticket to contest election. The Congress Party makes candidates stand for elections by giving them financial aid so that the votes of its opposites may be divided and it may win. The result is that congress is now in power although it obtained only 40 per cent. votes. The Joint Committee should consider this matter.

About broadcasting I would suggest that the opposition parties should be given opportunity to use the forum of broadcasting for election purposes. There should be some provision about it in the Bill.

Some persons change their political party after the election. Those who do so should be made to seek re-election.

This Bill has been made applicable to Jammu and Kashmir. But the question is whether a person who is registered as a voter in Madhya Pradesh can seek election from Jammu and Kashmir.

The penalty for bribery and for case of undue influence in election is disqualification for a period of 6 years to contest elections. The punishment is imprisonment for a period of one year. This is not adequate. There are no rules under which the Election Commissioner can disqualify candidates. No discretionary powers should be given to the Election Commissioner.

About the use of Government machinery there is punishment if a Government servant becomes an agent of a candidate. But what is the punishment to be given to the candidate for whom that person is working in the elections. Both the candidate as well as the person working as agent are guilty.

I want the Joint Committee to consider these points.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक इस बात का नमूना है कि एक मानव कृत-अकृत प्रकार की कितनी त्रुटियां कर सकता है। चुनाव आयोग ने जो जो अच्छे सुझाव दिये वे तो विधि मंत्रालय ने समाप्त कर दिये और जो कम महत्व की बातें थीं वह इस विधेयक में शामिल कर दीं।

उदाहरण के रूप में मैं जानना चाहता हूँ कि विधि मंत्रालय ने चुनाव आयोग की खर्च में कमी करने की सिफारिश को क्यों नहीं माना ? इसका अर्थ तो यह होगा कि केवल धनी लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। क्या हम समाजवादी समाज में रह रहे हैं ? विधि मंत्री को खर्च में कमी करने के बारे में कुछ करना चाहिए था। यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। मुझे खेद है कि कानून मंत्री ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है।

अब मैं जमानत की राशि के बारे में कुछ कहूँगा। मेरे विचार में यह राशि बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि कुछ व्यक्ति तो केवल इसलिये चुनाव में खड़े होते हैं ताकि उन्हें कुछ धन प्राप्त हो सके तथा किसी न किसी दल को तंग किया जा सके।

ऐसे ही उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने का भी प्रश्न है। कानून मंत्री ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। वह चाहते हैं कि केवल वही लोग राज्य करते रहें जिनका समाज तथा देश में ऊँचा स्थान नहीं है।

राष्ट्रपति के पद के लिये चुनाव लड़ने की जमानत की राशि का प्रश्न भी इसी प्रकार है। एक व्यक्ति हर बार राष्ट्रपति के पद के लिये चुनाव लड़ता है और कहता है कि एक मत तो उसका अपना है और दूसरा मत उसके साले का है। इन बातों से राष्ट्रपति पद के चुनाव का जो पवित्र स्थान है वह समाप्त हो जाता है।

चुनाव ठेकेदारों के लिये स्वर्ग बनने वाले हैं। ठेकेदारों को चुनाव लड़ने की स्वतन्त्रता देकर सरकार गलत कार्य कर रही है।

मेरा तीसरा प्रश्न मतदाताओं की सूची का प्रति वर्ष पुनरीक्षण के बारे में है। कई बार तो उम्मीदवारों का नाम ही हटा दिया जाता है। उदाहरण के रूप मेरा नाम ही मेरे चुनाव क्षेत्र की सूची में नहीं था। यह प्रति वर्ष पुनरीक्षण करना ठीक नहीं है।

सरकार ने अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी है। इसे रोकने के बारे में सरकार को कुछ करना चाहिये।

इस विधेयक में परिवर्तन करना चाहिये और इसे ऐसा बनाना चाहिये जिससे लोकतंत्र को लाभ पहुँचे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में जो संशोधन लाया गया है उसकी बहुत समय से आवश्यकता थी। मेरा विचार तो यह है कि इससे अधिक व्यापक संशोधन लाया जाना चाहिये था।

चुनाव में खर्च कम करने के लिये एक महत्वपूर्ण खण्ड लाया गया है। भारत में चुनाव में धन का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। पहले चुनाव में धन की इतनी आवश्यकता नहीं थी।

दूसरे में उससे अधिक हुई और तीसरे में तो बहुत धन का प्रयोग किया गया। चुनाव होने के दो दिन पूर्व धन का बहना प्रारम्भ हो जाता है और फिर किसी को पता नहीं चलता कि क्या हो जाये।

चुनाव में बहुत से उम्मीदवारों के खड़े होने की भी समस्या है। बहुत से व्यक्ति तो केवल इसलिये खड़े किये जाते हैं ताकि जात पात के नाम पर कुछ मत प्राप्त कर सकें और जीतने वाले उम्मीदवार को हटाया जा सके। मैं चाहती हूँ कि संयुक्त समिति इस प्रश्न पर गहराई से विचार करे।

व्यय कम करने के बारे में मैंने स्वयं कुछ सुझाव दिये हैं। उदाहरण के तौर पर एक तो यह कि चुनाव की पर्चियां देने का कार्य सरकार करे। साथ ही किसी भी उम्मीदवार के पक्ष की हिमायत किये बिना सरकार को चाहिये कि उनके चुनाव चिन्ह, उम्मीदवारों के नाम तथा चुनाव के स्थान का बताना सरकार का काम होना चाहिये। गाड़ियों के उपयोग के बारे में अब कहा गया है कि जहां "पैदल जाया जा सकता" है वहां पर गाड़ी का प्रयोग नहीं होगा। सरकार को "पैदल चलने वाले स्थान" की व्याख्या करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त एक और समस्या है कि कोई एक उम्मीदवार नगर के सारे साईकिल रिक्शा किराये पर ले लेता है और दूसरे उम्मीदवारों के लिये वह उपलब्ध नहीं होती। आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे और कैसे खर्च कम करेंगे।

जमानत जमा करने की राशि में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिये क्योंकि जो गरीब दल हैं उनके उम्मीदवारों के पास धन नहीं होता और वह राशि दल को देनी होती है। इसलिये वह गरीब दल घाटे में रहेंगे। धनी दलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दोष सिद्धि वाले खण्ड के बारे में मेरा कहना यह है कि कई व्यक्तियों को इसलिये चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि उन पर फौजदारी मुकदमें थे। एक जमशेदपुर के प्रमुख व्यक्ति श्री केदार दास के साथ यही हुआ। यह मुकदमे अधिकतर वास्तव में राजनीतिक मामलों के होते हैं। परन्तु श्री विद्याचरण शुक्ल जोकि इस समय एक उपमंत्री हैं उन पर लागू नहीं किया गया हालांकि उनके विरुद्ध बहुत कड़े आरोप थे।

मत डालने के बारे में मेरा कहना यह है कि जब तक एक स्थान पर मत न डाले गये हों दूसरे स्थानों पर गिनती बन्द होनी चाहिये क्योंकि इसका प्रभाव दूसरे स्थानों पर भी पड़ता है।

लक्काद्वीप तथा अंडमान आदि के भी अब निर्वाचित सदस्य होने चाहिये। वहां के लिये सदस्य मनोनीत करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिये। ऐसा करने से वहां नौकरशाही का जोर कम होगा।

निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमाओं के बारे में हमें चुनाव आयोग को बहुत अधिक शक्तियां नहीं देनी चाहिये जब तक उसकी उचित जांच न हो।

ठेके के बारे में जो खण्ड है उसकी हम अनुमति नहीं देंगे क्योंकि इससे तो उनके लिये रास्ता साफ हो जायेगा।

मुझे आशा है कि इस विधेयक पर पूरी तरह से विचार होगा क्योंकि जो संशोधन लाये गये हैं उनका वांछनीय प्रभाव नहीं होगा ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Mr. Deputy-Speaker, I am happy that this law will be applicable to Jammu and Kashmir also. Other laws should also apply to that State likewise.

We should have vacant seats for occupied Kashmir also. The population of that area is approximately 12 to 14 lakh people. So we should leave two seats for them. When we get back that area we will be able to fill those seats.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
पंचानवेवां प्रतिवेदन

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 95वें प्रतिवेदन से, जोकि सदन में 31 अगस्त, 1966 को प्रस्तुत हुआ था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 95वें प्रतिवेदन से, जोकि सदन में 31 अगस्त, 1966 को प्रस्तुत हुआ था, सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

The motion was adopted

योजनाओं के पुनर्विन्यास के बारे में संकल्प
RESOLUTION RE : REORIENTATION OF PLANS

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव को पेश करता हूं।

मुझे पता है कि जब योजना की रूपरेखा मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखी गई तो समाचार यह थे कि वे दोनों ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर अधिक महत्व देने के हक में थे। उसके होते हुये भी यदि मैं यह प्रस्ताव लाया हूं तो उसके कुछ अच्छे कारण हैं।

योजना मंत्री श्री अशोक मेहता ने उस दिन कहा था कि दस वर्ष में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुये चौथी पंचवर्षीय योजना का आकार निर्धारित किया गया है। हमारी अभिलाषा है कि कम से कम खाद्य के क्षेत्र में तो आत्मनिर्भरता प्राप्त की ही जाये। यदि खाद्यान्न का आयात करना आवश्यक भी हो तो उसका

मूल्य चुकाने की क्षमता हमारे देश में होनी चाहिये। यदि ये बातें नहीं हुईं तो इसका हमारे देश की आत्मनिर्भरता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मैं इस बात के लिए श्री सुब्रह्मण्यम की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने देश में खाद्य की कमी का पूर्वानुमान करके समय पर खाद्यन्न का आयात करके लोगों को भुखमरी की स्थिति से बचाया, परन्तु वह समय देश को बड़ा ही अपमानजनक भी था कि अनेकों देशों के लोगों और बच्चों ने इस देश के लिए धन बचाकर सहायता की। हमें ऐसी अपमानजनक स्थिति भविष्य में नहीं आने देनी चाहिये। यदि देश में फैले हुये सामाजिक असंतोष, राजनीतिक भ्रान्ति और संकट से लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने पर हमें सर्वप्रथम ध्यान देना होगा। मंत्री महोदय चाहे ऐसा कहें कि वे ऐसा ही करने की सोच रहे हैं परन्तु वस्तुस्थिति दूसरी ही है। योजना की रूपरेखा तैयार करते समय कहा जाता है कि उसमें ग्राम्य समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये, परन्तु इसको कार्यरूप नहीं दिया जाता।

योजना मंत्री ने उस दिन कहा था कि योजना आयोग ने कृषि क्षेत्र के लिये इतने साधनों की व्यवस्था की है जितना कि वह क्षेत्र प्रशासनिक तथा तकनीकी रूप से खपा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु तथ्य यह है कि बड़ी और मध्यम आकार की 500 परियोजनाओं के लिये जो 1750 करोड़ रुपये की जरूरत थी उसमें से हम 1,000 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं और उससे केवल 1 करोड़ 30 लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था हुई है। शेष 750 करोड़ रुपया लगाने पर 4 करोड़ 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। परन्तु हमने इसके लिए केवल 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जिससे 1 करोड़ 40 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी। यदि 250 करोड़ रुपये और दिये जाते तो लगभग 3 करोड़ 40 लाख एकड़ के लिये व्यवस्था हो जाती परन्तु यही 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था नहीं की गई है।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिये योजना के प्रथम वर्ष में 55 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जोकि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और राज्य मांगते रहे हैं परन्तु योजना में इस धनराशि की भी व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये 30 करोड़ रुपये की मांग की गई थी परन्तु यह राशि भी अभी तक उपलब्ध नहीं की गई है। सिंचाई परियोजनाओं अथवा बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं और ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये प्रतिवर्ष दी जाने वाली धनराशि में कमी ही होती जा रही है जो कि इन आंकड़ों से स्पष्ट है :—

सिंचाई परियोजनायें	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67
अथवा		(करोड़ रुपयों में)		
बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनायें		88	76	52
ग्राम्य विद्युतीकरण	183	88	65	65

राजस्थान में लगभग 20,000 कुओं की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपये की आवश्यकता

है जिससे मरम्मत के बाद उनका उपयोग उत्पादन वृद्धि के लिये किया जा सके। यह राशि भी नहीं दी जा रही है। वहां ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये और 2 करोड़ रुपये की मांग की गई है। वहां गांवों तक बिजली पहुंच गई है, ट्रान्सफार्मर लगा है परन्तु उसकी वितरण व्यवस्था करने के लिए धनराशि नहीं मिल रही है। राजस्थान के मुख्य मंत्री और योजना मंत्री इसके लिये लिखते रहे हैं परन्तु रुपया नहीं मिल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार का यह कहना कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। इस तरह हम किस प्रकार लोगों में विश्वास पैदा कर सकते हैं और उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के चेयरमैन श्री पी० सी० भट्टाचार्य के कथनानुसार सरकारी बजटों के द्वारा घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण रिजर्व बैंक सहकारी समितियों को अपने ऋण की मात्रा में अधिक वृद्धि नहीं कर सका है। कृषकों के लिये मध्यम-कालीन और दीर्घकालीन ऋणों की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि सिंचाई और ग्राम्य विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये रूपरेखा तैयार कर ली जानी चाहिये। इसके लिये लगभग 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जो कि योजना के प्रथम दो वर्षों में व्यय किये जायें, पांच वर्षों में नहीं। मध्यम आकार की जो सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जानी हैं उनके लिये लगभग 150 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जिसकी व्यवस्था योजना के प्रथम दो वर्षों में ही की जाये। अन्य योजनाओं को योजना के तीसरे से पांचवे वर्षों में पूरा किया जा सकता है।

इसके विपरीत उद्योगों के लिये हम 9000 लाख डालर का ऋण ले रहे हैं जिसमें से अधिकांश कुछ सुव्यवस्थित उद्योगों के लिये दिया जायेगा और बड़ी मुश्किल से लगभग 50 करोड़ रुपये लघु उद्योगों को दिये जायेंगे। इस प्रकार की स्थिति अक्षम्य है।

तीसरी योजना के दौरान हमारी आर्थिक प्रगति मन्द रही थी। योजना आयोग ने जितने अतिरिक्त संसाधनों की मांग की थी उससे लगभग दुगने जुटाये गये फिर भी प्रगति मन्द क्यों हुई। सब राज्यों ने मिलकर आशानुकूल लगभग 600 करोड़ रुपये जुटाये और केन्द्र ने इससे दुगने। परन्तु लोगों पर भारी कर लगा लगाकर जो इतना रुपया इकट्ठा किया गया उसका हुआ क्या? 1961-62 में सरकार का व्यय 442.3 करोड़ रुपये हुआ था जो अब बढ़कर 805 करोड़ रुपये हो गया। रेलवे और डाक-तार विभाग पर 1961-62 में 253.2 करोड़ रुपये व्यय हुए थे, यह व्यय 1965-66 में बढ़कर 515 करोड़ रुपये हो गया। बिहार बंगाल और आसाम में जो अतिरिक्त संसाधन जुटाये गये थे उनकी राशि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और मंहगाई भत्ते की वृद्धि पर व्यय हो गई।

1962 में चीनी आक्रमण के बाद मितव्ययिता की भावना जागृत हुई। सचिवों की समिति नियुक्त की गई। यह तय किया गया कि वित्त तथा गृह मंत्रालयों की अनुमति के बिना कोई नई भर्ती नहीं होगी। परन्तु पहले वर्ष ही 10,000 और पद निकाले गये और व्यय 253 करोड़ से बढ़कर 504 करोड़ रुपये हो गया।

योजना आयोग ने मद्रास सरकार से 45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिये कहा था। मद्रास सरकार ने 52 करोड़ जुटाये परन्तु उनमें से 25 करोड़ रुपये बढ़े हुये मंहगाई भत्ते पर ही व्यय हो गये। उत्पादन बढ़ाने के लिये राशि बची ही कहां।

प्रशासन व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है कि यह पता नहीं लग रहा कि कितने कर्मचारी फालतू हैं और हमें क्या करना है। यदि इसी प्रकार कार्य किया जाता रहा तो चौथी योजना में भी जो संसाधन जुटाये जायेंगे वे इसी प्रकार कम हो जायेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ। अल्पकालीन उत्पादन कार्यक्रमों को योजना के पहले दो वर्षों में पूरा किया जाये। वर्तमान सरकारी नीति तथा विचारधारा में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र को यह महसूस करना चाहिये कि उसका अस्तित्व सरकारी क्षेत्र पर ही टिका हुआ है जो कि उसे कच्चा माल आदि देता है। सरकारी क्षेत्र की खामी वहां का कुप्रबन्ध ही है। यदि कुप्रबन्ध करने वाले चोटी के लोगों के स्थान पर ठीक व्यक्ति रख दिये जायें तो सरकारी क्षेत्र संसाधन जुटाने के लिये सोने की खान का काम करेगा। रांची परियोजना में कुप्रबन्ध के कारण जो गड़बड़ी हुई है उसके लिये प्रभारी मंत्री और चोटी के अन्य व्यक्ति दोषी हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यक्ति लालची और कदाचारी हैं। उन्हें बता दिया जाये कि उन्हें ठीक प्रकार व्यवहार करना चाहिये ताकि उसका मान रह सके।

योजना का आकार आवश्यकता के अनुरूप ही नहीं अपितु हमारी क्षमता और हमारे संसाधनों के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिये। यह योजना 23750 रुपये या उससे अधिक की हो सकती है परन्तु हमें तीन शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली यह कि हम जो संसाधन जुटायें उनसे और संसाधन उत्पन्न हों और वह मंहगाई भत्ते जैसे अनुत्पादक कार्य पर व्यय न किये जायें। दूसरी यह कि मूल्य देशनांक पर नियंत्रण रखा जाये। 1961-62 में यह 131 या 132 था। इसमें इससे अधिक वृद्धि को समाप्त करके इसे 145 पर ही रखा जाये। चौथी योजना के अन्त तक इसमें प्रतिवर्ष $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक वृद्धि न होने दी जाये। तीसरे यह कि कृषि के सम्बन्ध में केवल खाद्यान्न का ही ध्यान न रखा जाये अपितु औद्योगिक विकास के लिये भी जो कृषि का महत्व है उसे समझा जाये।

सामाजिक कार्यों में मैं ग्राम्य जल सम्भरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता हूँ। चौथी योजना में इसके लिये जो 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है उसमें से राजस्थान को कम से कम 10 करोड़ रुपये दिये जायें। वह क्षेत्र इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित है। योजना में पहले वर्ष ही हमें 2 करोड़ रुपये दिये जायें, परन्तु केवल 30 लाख रुपये दिये गये हैं जबकि 1964-65 और 1965-66 में इस पर एक-एक करोड़ रुपये व्यय हुए थे। कम राशि दिये जाने का परिणाम यह हुआ है कि छोटे नगरों तथा गांवों में जो कार्य चल रहे थे वे बन्द हो गये हैं। क्या इस प्रकार लोग सहयोग देने के लिये प्रेरित हो सकते हैं? वे तो योजना के प्रथम वर्ष में किये जाने वाले कार्य से ही प्रभावित होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की राय है कि योजनाओं की 'परिवहन-संसाधन स्थिति' के विषय में सरकार के दृष्टिकोण को बदलना और सिंचाई, विद्युतीकरण एवं पानी की सप्लाई के लिए ग्राम-क्षेत्र को उच्चतम प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है।"

श्री यशपाल सिंह : मैं अपना स्थानापन्न संकल्प संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये; अर्थात्—

"इस सभा की राय है कि सरकार को सिंचाई, विद्युतीकरण और पानी की सप्लाई के लिए ग्राम-क्षेत्र को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए।"

श्री उमानाथ (पुद्दकोट्टै) : योजनाओं के आकार और प्रगति के प्रश्न पर बात करते समय यह कहा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना 4,000 करोड़ रुपये की थी, दूसरी 7,000 करोड़ रुपये की, तीसरी 10,000 करोड़ रुपये की तो चौथी अब 23,000 करोड़ रुपये की है। यह कहा जाता है कि तीसरी योजना में कुछ असफलतायें तो मिली हैं परन्तु वित्तीय लक्ष्य पूरा किया गया है। वित्तीय लक्ष्य की बात कहने से यह पता नहीं चलता कि योजना की वास्तविक क्रियान्विति किस प्रकार हो रही है। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की यह बात अधिकाधिक बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर वास्तविक कार्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की गति मन्द होती जा रही है। उदाहरणार्थ तीसरी योजना में वित्तीय लक्ष्य तो शत-प्रतिशत पूरे हो गये थे परन्तु विभिन्न अनुमानों के अनुसार वास्तविक कार्य का लक्ष्य केवल 50 से 60 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। यह अन्तर निरन्तर बढ़ता जा रहा है यह ईस्टर्न इकानामिस्ट के एक लेख से स्पष्ट होता है जिसमें बताया गया है कि उत्पादन मूल्य में 300 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि औद्योगिक उत्पादन देशनांक में लगभग 150 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। चौथी योजना का मसौदा भी इस प्रकार का है कि उससे भी इस अन्तर के कम होने की सम्भावना नहीं है अपितु इस प्रवृत्ति की तो वृद्धि ही होगी।

इस योजना का मसौदा तैयार करने से एक वर्ष पहले कहा गया था कि चौथी योजना 21,000 करोड़ रुपये की होगी परन्तु रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् अब यह योजना 23,000 करोड़ रुपये की पेश की गई है जो कि अवमूल्यन-पूर्व की दरों पर 19,000 करोड़ रुपये की बैठती है।

[**श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए**
Shri Sham Lal Saraf in the Chair]

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही वर्ष में वित्तीय परिव्यय में भी कमी कर दी गई। चौथी योजना की प्रस्तावना में भी यह कहा गया है कि सितम्बर 1965 में जो 21,500 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था वह, यदि कार्यक्रमों में कमी नहीं की जाती तो, मूल्य-वृद्धि और अवमूल्यन के कारण 25,000 करोड़ रुपये हो जाता। इस प्रकार कार्य-क्रमों में काट-छांट करके

वित्तीय लक्ष्यों में कमी की बात स्वीकार की गई है और इस प्रकार तो ज्यों-ज्यों मूल्य बढ़ते जायेंगे त्यों-त्यों कार्यक्रमों में कमी की जाती रहेगी ।

देश की प्रगति की गति मन्द रही है । दिनांक 31 अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादकीय लेख में यह आशंका व्यक्त की गई है कि जब 1950-51 से 1964-65 तक की अवधि में राष्ट्रीय आय की दर में केवल 3·8 प्रतिशत वृद्धि हुई है तो 1964-65 से 1970-71 तक की अवधि में किस प्रकार 5.5 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है । मुझे तो लगता है कि इस 3·8 प्रतिशत को भी बनाये रखना कठिन होगा क्योंकि मूल उद्योगों पर पहले जो जोर था चौथी योजना में उनका महत्व कम कर दिया गया है । परिणाम यह होगा कि अन्य उद्योगों के लिए यंत्र कम मिलेंगे और अवमूल्यन के कारण विदेशी यंत्रों का मूल्य बढ़ने से उनका आयात करना कठिन होगा । हम इस स्थिति में इसलिए पहुंचे हैं कि प्रारम्भ से ही योजनाओं, उनके संसाधनों और उनकी क्रियान्विति के लिए साम्राज्यवादी देशों पर निर्भर रहे हैं ।

योजना का उद्देश्य तो यह घोषित किया गया है कि विकास से निर्धनता दूर होगी । परन्तु वास्तविक स्थिति इससे विपरीत है । 'ईस्टर्न इकानामिस्ट' के अनुसार जो औद्योगिक उत्पादन 1956 में 100 प्रतिशत था वह 1963 में 163·8 प्रतिशत हो गया परन्तु असल मजूरी का देशनांक जो 1956 में 100 था वह 1963 में 95·7 हो गया । इससे यह स्पष्ट है कि निर्धनता समाप्त होना तो दूर रहा उलटे उसमें वृद्धि हुई है । उत्पादन में वृद्धि हुई, साथ ही गरीबी में भी वृद्धि हुई, क्या इसी को योजनाओं की सफलतायें कहा जा सकता है ? श्रीमती गांधी को इस स्थिति पर गर्व हो सकता है परन्तु हमें, देश के लोगों को इस पर शर्म आती है । घोषित उद्देश्य तो समाजवाद की स्थापना है परन्तु वास्तव में पूंजीवाद का पोषण किया जा रहा है और जब तक इस मार्ग का त्याग नहीं किया जाता तब तक ऐसी ही स्थिति चलती रहेगी ।

Shri Sidheshwar Prasad: The change in Government's view points with regard to the implementation of Plan as suggested by Shri H. C. Mathur should be given due weight. But this is not correct to say that during the last 15-17 years there has been no economic growth in the country. Some persons might be discontented with the pace of progress made in economic and social spheres and for that we should try to know the reasons therefor. The most important point towards which many Members have been drawing attention is that the administrative machinery, the development oriented machinery required for the implementation of Plans could not be arranged during these years.

After independence when the Government of our country started works in the public sector, it was very essential that necessary changes should have been made in the administrative structure to cope with that kind of work. But it was not done. The Planning Commission has as yet not paid any attention to the fact as to why the plans are not being properly implemented. I suggest the Government to appoint in each state an officer who may be called Plan Administrator or give him some other name and whose duty it may be to see to it that plans are properly implemented. Then only the plans can be properly implemented.

The second point which I want to bring to the notice of the Government is that though they have created a capacity of 33 per cent. for irrigation, yet the water from canals is not reaching the fields.

My third suggestion is that we should raise our own resources. This can be done by savings and taxation. We should not make hue and cry when there is an increase to the taxes.

My next point relates to change in the outlook. When we frame plans we should have the cooperation of the people. There should be peoples' and mass sanction behind it. It is not political question. One more thing worth remembering is that so far the emphasis in our plans was on the urban population. But majority of our population lives in villages. Unless we develop agriculture and raise resources for it, our economic development cannot take place.

Then the next point relates to regional imbalance. We have not been able to remove it even after independence. We should also remove the imbalance in the per capita income. I hope the Government will look into it.

With these words I support the resolution of Shri Mathur.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : I congratulate Shri Mathur for his comprehensive resolution.

Out of a plan of Rs. 16 thousand crores, the loan would be to the extent of Rs. 9 thousand crores. For this a sum of Rs. 3 thousand crores would be raised by means of taxes. The result is that the Government has a capital of Rs. 4 thousand crores only. If our plan fails then the result would be most disastrous.

A sum of Rs. 34 crores would be spent on industry. Not much gain is expected to be derived from that. Therefore the draft plan needs a drastic change.

These days the suggestion for giving top most priority relates to agriculture. The Government is not giving due thought to the organic manure for raising agriculture production.

A pleader farmer of Hazari Bagh has raised five crops in a year by using night soil manure. The Government sent an expert to examine this experiment and he agreed to the method. But that scheme has not been used elsewhere.

About power also the Government earmarked Rs. 500 crores but later on decreased it to Rs. 250 crores. In Rajasthan we wanted Rs. 2 crores only for this work but it was not given. A sum of Rs. 500 is necessary to supply electricity to the villages.

Now I want to say a few things about land reforms. We have done it by carrying out 17th amendment in the constitution. But the implementation is not being done. Who is to be blamed for it ?

Keeping the above in view, we should pay more attention to the villages. We should give them electricity so that they may use the power locms and other things. It will increase employment in the villages.

About drinking water problem I can say that this is an acute problem before Rajasthan. If you do not provide it to them during the next five years, a major portion would desert that area. Money should be found out for it.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : Shri Mathur by bringing his resolution has provided an opportunity to the House to discuss the draft Fourth Five Year Plan and to suggest changes in that.

After the completion of the Third Five year Plan, the picture which emerged before the nation in the economic field is not a pleasant one. There is rise in prices, the increase in agricultural production is also inadequate. There can be many reasons for this. This has forced us to have a second thought on our plans. Our aim should be to become self-reliant.

About the factories which we have in view, most of them have to depend on foreign countries for raw material. We experienced this difficulty at the time when there was conflict between India and Pakistan. Secondly the goods manufactured in our factories are not in a position to face competition in foreign markets as our goods are costly. For the third five year plan also our goal was to become self-reliant and that our economy should be a self-generating one.

We have not created an administration which may be able to cope with the work of implementing the plans. It is hoped we will be able to do so during the Fourth Five Year Plan.

With these words I move my amendment before the House.

Shri Tyagi (Dehra Dun) : I have a request, we want this resolution to be passed unanimously and not that it should be talked out. That would be the opinion of this sovereign body and we want the Government to know our views.

श्री अल्वारेस (पंजिम) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए श्री माथुर को धन्यवाद देता हूँ । यद्यपि इस संकल्प का क्षेत्र केवल तीन मामलों तक सीमित है अर्थात् बिजली, सिंचाई तथा पानी की उपलब्धि । फिर भी यदि यह संकल्प स्वीकार कर लिया तो हमारी अर्थ-व्यवस्था में जो बहुत से असंतुलन उत्पन्न हो गये थे वह ठीक हो जायेंगे । योजना का यह आवश्यक भाग है कि असंतुलन का पता लगाया जाय ।

आजकल के औद्योगिक युग में यह स्वाभाविक है कि नगरों की ओर जायें तथा ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करें । सारे संसार में ऐसा हो रहा है । इस संकल्प में इसे भी दूर करने का प्रयत्न किया गया है ।

गत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र की बहुत उपेक्षा की गई है । यदि हम यह अनुभव करें कि न केवल इस देश की आधी से अधिक आय गाँवों से प्राप्त होती है बल्कि 70 प्रतिशत लोग वहाँ रहते हैं, तब हम इसके महत्व को समझेंगे ।

कोई अर्थ-व्यवस्था तब तक आत्म-निर्भर नहीं बन सकती जब तक उसका ग्रामीण क्षेत्र आत्म-निर्भर नहीं है । हमारे देश का उत्पादन इतना कम है कि यदि हम वहां थोड़ा-सा प्रयत्न भी करें तो हमारी राष्ट्रीय आय में दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ोतरी होगी ।

गत तीन योजनाओं से हम लोगों से कह रहे हैं कि अभी वह इन्तजार करें और उनकी स्थिति ठीक हो जायगी । इस प्रकार उन्हें अधिक दिन तक टाल नहीं सकते । अब वह सीमा आ गई है कि हमें लोगों को तत्काल सहायता देनी होगी ।

पानी की समस्या भी बहुत कठिन है । हमें वर्षा पर न केवल अपनी खाद्य समस्या के लिए आधारित रहना पड़ता है बल्कि बिजली के लिए भी । मुझे विश्वास है कि बार बार सूखा ने हमें

यह सिखा दिया है कि हमें सिचाई के पानी तथा बिजली के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए सरकार को चौथी योजना में इतना व्यय करना चाहिए जिससे वर्षा पर निर्भर न रहना पड़े। साथ ही पीने के पानी की समस्या भी हल होनी चाहिये। मुझे विश्वास है पानी का मिलना इतना ही आवश्यक है जितना कपड़े तथा मकान का होना।

मेरा दूसरा प्रश्न बिजली के बारे में है। बिजली से अर्थ व्यवस्था का भी विकेन्द्रीयकरण होता है। यदि हमने अधिक बिजली दे दी तो हम अधिक सहायक उद्योग आरम्भ करके नगरों की ओर जो दौड़ हो रही है उसे रोक सकेंगे।

तीसरा प्रश्न सिंचाई का है। गत कुछ वर्षों में हमने खाद्यान्न के आयात में बहुत धन लगा दिया है। विदेशों पर आश्रित रहने का दुःखद अनुभव हमें उस समय हुआ जब 1962 में चीन ने तथा 1965 में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया। उस समय न केवल विदेशी सहायता बन्द हो गई बल्कि खाद्यान्न का संभरण भी बहुत कम हो गया। इसलिए आत्म-निर्भरता के मामले में हमें पहले खाद्यान्न में ही आत्म-निर्भर होना चाहिए। बाकी वस्तुओं के बिना तो काम चल सकता है परन्तु खाने के बिना काम नहीं चलेगा।

यह स्पष्ट है कि साधनों के फिर से बंटवारे से विशेष रूप से सिंचाई, बिजली तथा पानी देने के बारे में जो राशि रखी है उसके फिर से निर्धारित करने से न केवल हम विदेशी साधनों से मुक्त होंगे बल्कि हम ग्रामीण तथा नगरों के क्षेत्र में जो बड़ा अन्तर है उसे भी समाप्त कर सकेंगे।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : While moving an amendment to a resolution of Shri Mathur, I would like to tell that irrigation works should be production-oriented and not revenue-oriented. Government should see that water is supplied on no-profit no-loss basis. Its rates should be subsidized at least for ten years. Unless it will be done agricultural production will not increase. This point has also been made clear in All-India Review of Minor Irrigation Works based on State-wise Field Studies, June, 1966. This report further states that in our country irrigation is being managed on defensive basis in accordance with the principles laid down in Indian Irrigation Commission's Report of 1901-03. Now Irrigation should be based on offensive basis and not on defensive basis. Government should take initiative of constructing wells, canals and nullahs on large scale not only to save people from drought etc. but to extend irrigation facilities where necessary with a view of having increased production. The rate of irrigation have also gone up. Now it is Rs. 14/- per acre.

The Planning Minister has stated the lack of foreign exchange as the reason for failure in supplying water by tubewells and pumping-sets. We earn foreign exchange of 175 crores of rupees by exporting Jute alone. Our per-acre yield of jute at present is 15 maunds, which can be doubled, if water is adequately available. I know people in Bihar have got sunk tubewells but they are not getting electricity. If electricity is there, it goes off every now and then. Thus water is not available for irrigation, though there are rich water resources. It has been recommended in the same report that Govt. should set up an Irrigation Commission which should study the availability of water resources throughout the country and should suggest how soon and how far they can be utilized. Government have neither so far appointed an Agricultural Commission or Irrigation Commission, which is the necessity of the time.

I would like to draw attention to the difference in rates of electricity. In North Bihar the rate of electricity is 23 paise per unit, while in South Bihar it is 18 paise, in Mysore 6 paise, in Madras and Andhra Pradesh 8 paise only. There should be uniformity in rates of electricity throughout the country.

In the end I request the Planning Minister and Agriculture Minister to pay more attention to irrigation, because water is life-blood for agriculture. If water is not made available for agricultural purposes, the production will not increase.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : योजना के आकार का प्रश्न एक महत्वपूर्व प्रश्न है, यह एक बड़े और छोटे के बीच अन्तर का प्रश्न है जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Hon. Members should know that two hours have been allotted for discussing this resolution, which has further been increased by fifteen to twenty minutes.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जैसा मैंने अभी कहा है कि यह प्रश्न छोटे और बड़े लोगों के बीच विद्यमान खाई को पाटने का प्रश्न है। देखना तो यह है कि योजना में छोटे लोगों को प्राथमिकता दी जाती है अथवा नहीं। हमारा यह प्रयास रहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे, किन्तु बार बार इसके लिए वायदे करने के बाद भी सरकार इनकी अवहेलना ही करती रही। जब तक सरकार यह अनुभव न करेगी कि बड़ी योजना लोगों को अपनी ओर आकर्षित न करके उन्हें भयभीत करती है तब तक योजना से कोई लाभ न होगा। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की भी यही राय थी कि छोटे लोगों और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में हों औद्योगिक क्षेत्र में, अथवा शहरी क्षेत्र में।

कृषि क्षेत्र में कार्य बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारा लक्ष्य देश में 128 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचाई योग्य भूमि बनाने का था जबकि हम केवल 75 लाख एकड़ भूमि को ही सिंचाई योजनाओं के माध्यम से पानी दे पाये हैं। यदि प्रति एकड़ उपज बढ़ानी है तो सिचाई और विद्युतीकरण को सरकार द्वारा अवश्य ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभा को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इन तीन मुख्य क्षेत्रों पर अधिक खर्च करने के सरकार के बचनों के बावजूद हमारी आर्थिक प्रगति की क्या गति रही है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मुद्रा-स्फीति, अवमूल्यन अथवा देश के आर्थिक संकट के बारे में विवरण देने का अब कोई लाभ नहीं है। वर्तमान स्थिति में तो इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि देश में उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग किया जा रहा है या नहीं, और हमारी योजना में निर्धारित प्राथमिकताएं उचित हैं या नहीं। सिंचाई, विद्युतीकरण और पीने के पानी की सप्लाई की ओर सरकार ने यथोचित ध्यान नहीं दिया है। इन तीनों ही क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। मेरे विचार से इन क्षेत्रों के परिव्यय पर जितना जोर दिया जाता है उतना प्रयास निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता।

चौथी योजना में तो वित्तीय परिव्यय और भौतिक लक्ष्य दोनों ही कम रखे गये हैं। योजना मंत्री इसका कारण संसाधनों का सीमित होना बतलाते हैं। यदि बात ऐसी है तो हमारा भविष्य अंधकारमय है और हम 10, 15 या 20 वर्ष के अन्दर अर्थव्यवस्था की स्वजनित अवस्था में न पहुँच सकेंगे।

अवमूल्यन के उपरान्त विदेशी मुद्रा का अपव्यय बड़ी ही लापरवाही से किया जा रहा है। क्या अवमूल्यन विदेशी मुद्रा को फिजूल खर्च करने के लिए ही किया गया था। साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि उपलब्ध विदेशी मुद्रा में से कितना कृषि क्षेत्र पर खर्च किया जाता है।

योजना के 23,500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 16000 करोड़ रुपये सरकारी औद्योगिक क्षेत्र के लिए निर्धारित किये गये हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कृषि क्षेत्र के लिये बचा ही क्या है, जिसे सरकार प्राथमिकता देने का दावा करती है। यह सरकार देश में सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के पक्ष में है। किन्तु इस क्षेत्र के उत्पादन की मात्रा बहुत ही कम है। अतः इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाया, उसका उत्पादन बढ़ाया जाय और साथ ही कृषि पर भी यथावश्यक ध्यान दिया जाय। मैं यह चाहता हूँ कि प्रस्तुत संकल्प पर मतदान होने से पहले मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन दें कि इन नीतियों को आवश्यकतानुसार ढाला जायेगा।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : प्रस्तुत संकल्प बड़े ही उचित समय पर लाया गया है जिसमें योजना मंत्री का ध्यान सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और विद्युतीकरण की ओर दिलाया गया है। कृषि से न केवल हमें अन्न ही मिलेगा बल्कि उसमें महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये कच्चा माल भी प्राप्त होगा और इस प्रकार उन पर खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकता है। जूट, कपास, चाय तथा अन्य वस्तुओं की उपज बढ़ाकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। अतः कृषि विकास पर समुचित ध्यान देना चाहिए ताकि देश आत्म-निर्भर बन जाय।

विद्युत-निर्माण पर अपार धनराशि खर्च की गयी है किन्तु विद्युत के वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं है। बिजली है किन्तु किसानों को उसकी सप्लाई नहीं की जा रही है। प्रत्येक स्थान से सिंचाई-साधन के लिये बिजली के कनक्शन की मांग की जा रही है। किन्तु उपलब्ध बिजली का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाना देश के हित में है। मूल्यों को भी तब तक स्थिर नहीं किया जा सकता जब तक उत्पादन न बढ़ेगा और उत्पादन तब तक न बढ़ेगा जब तक सरकार इस सम्बन्ध में उचित कदम न उठायेगी। औद्योगिक क्षेत्र में भी खर्च अधिक होता है और उत्पादन कम। यही कारण है कि वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही है। हमारा खर्च उत्पादन-अभिमुख होना चाहिए। जिन उद्योगों को थोड़ी पूंजी से पूरा किया जा सकता है, और जिनमें उत्पादन शीघ्रता से हो सकता है, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो उद्योग अधूरे हैं उन्हें पहले पूरा किया जाना चाहिए और उन उद्योगों को स्थगित कर देना चाहिए जिनमें उत्पादन देर में शुरू होगा।

सार्वजनिक उपक्रमों पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उनमें उत्पादित यंत्रों से कृषि और विद्युतीकरण के क्षेत्र के विकास में बहुत सहयोग मिलता है। अतः यह प्रयास करना चाहिए कि इन उपक्रमों में अधिक और तेजी से उत्पादन हो। सार्वजनिक उपक्रमों में कुप्रबन्ध का एक रोग लगा हुआ है जिस कारण से उनका उत्पादन संतोषजनक नहीं हो पा रहा है। अतः यह प्रयास किया जाना चाहिए कि उन्हें ठीक प्रकार से चलाया जाय और उनका उत्पादन उनकी लागत के अनुरूप हो। यदि ऐसा हुआ तो स्थिति सुधरेगी और कीमतों को भी स्थिर किया जा सकेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The plan should be production-oriented; priority should be given to rural or urban areas, heavy or small-scale industries. There will be no use of discussing all these matters unless the plan is honestly-oriented. I have been recently intimated of a such big scandle. Rice is being imported from Burma through ships. The quantity of rice unloaded in Indian ports was much less than what it was at the time of loading the ships. When the Govt. asked the Shipping Company concerned for compensation of such loss, it invented a novel way of avoiding such claims. On the way empty bags of the same brand were intentionally put in different parts of the ship. A letter in this respect was addressed to the Captain of the ship by a proprietor-partner of the Shipping Company. This letter somehow reached Indian Embassy in Rangoon, which was further transmitted to Indian Govt. No action has so far been taken on that letter by the Government. It is a case of dishonesty. It is a fraud.

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा योजना के पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में हो रही है। कृपया प्रस्तुत संकल्प से सम्बन्धित विषय का उल्लेख कीजिये।

Dr. Ram Manohar Lohia : The letter in original is with our Government and no Minister has taken up that matter. No action has been taken against the Shipping Company. I would like to impress that the matter should be taken up, responsibility should be fixed and the guilty should be punished. Here I would suggest that a standing commission should be set up for investigating into such cases which happened during last 19 years, and accordingly responsible persons should be made to task. No plan should be successful unless it is based on honesty and truth. A plan based on dishonesty is bound to fail.

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। श्री भागवत झा आजाद।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर) : मेरा यह निवेदन है कि उक्त पत्र सभा-पटल पर रखा जाये। वह इसे प्रमाणित करें और सभा-पटल पर रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह इसे प्रमाणित करते हैं तो वह इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : I lay it on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T.-7018/66]**

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : इसे परिचालित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह परिचालित नहीं किया जायेगा। जो सज्जन इसे देखना चाहते हैं, वे सभा-पटल पर इसे पढ़ सकते हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : The resolution, which is before the House, lays stress on the fact that there is lack of proper arrangement of irrigation, electrification and drinking water in rural sector. It was moved with the object of bringing this fact into light that due emphasis has not been laid on agriculture in Fourth Five Year Plan. The resolution is simple one.

If there is anything in this country which requires special attention, that is agriculture. What is required to improve agriculture and to increase agricultural production is water, electricity and manure. But the main necessity is that of water.

Some big people, officers and advisers, who are American-oriented, are of the opinion that Indian farmers do not know how to cultivate and they require technical know-how. They ask people to grow more food. In my opinion nothing more than water at proper time is required for agriculture in India. If water is made available for agriculture, agricultural production can be increased by hundred per cent. Here we do not require technical know-how, American fertilizers or personnel of American Peace Corps. Manure or fertilizer is required in Madras, Andhra Pradesh and Kannad area where adequate water has been made available for irrigation purposes. In some districts of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Punjab we require water for irrigation. The soil we till requires more water than fertilizers.

In the present plan outlay for every sector has been doubled, but in respect of irrigation instead of doubling the outlay, it has been increased to only 750 crores from 550 or 650 crores. It is absolutely insufficient for 500 minor irrigation projects under construction in the country. It is asserted that irrigational potential in the country will be increased to 3 crores of acres. How this amount of 750 crores will help irrigation schemes in the country, how it will solve food problem or in being self-dependent in matter of food. If sufficient allotment is made for irrigation we will soon be self-dependent in respect of food.

Govt. should also pay attention towards its administrative machinery. It fits in absolute police state. It is not suitable for welfare state. All the last three plans show that we have sufficient resources. We have anyhow managed the outlays required for all the Plans. Though we achieved financial targets of the Plans yet badly failed in achieving physical targets. There has not been any increase in national income. People speak against Public Sector but what are the returns received from Private Sector, though we have given too much to it. The main point which should be well understood is that every Plan in our country must be village-oriented. We should never forget it.

स्वर्ण नियंत्रण में ढील देने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : RELAXATION OF GOLD CONTROL

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमान्, संसद के पिछले अधिवेशन में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान स्वर्ण नियंत्रण का प्रश्न उठाया गया था। इस समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार करने के लिए एक अनौपचारिक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने एक अन्तरिम प्रतिवेदन दिया है।

समिति का मुख्य निष्कर्ष यह है कि जब से संसद ने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1965

बनाया है, तब से ऐसी कोई महत्वपूर्ण आर्थिक तथा वित्तीय बात नहीं हुई है जिसके कारण मूल स्वर्ण नीति में कोई परिवर्तन किया जा सके ।

सरकार समिति के निष्कर्ष से सहमत है परन्तु वह समझती है कि सामाजिक—आर्थिक सुधार के लिए किये गये वे उपाय, जिनसे कई शताब्दी पुरानी प्रणाली तथा रीतियों में परिवर्तन करना हो, कुछ ही वर्षों में प्रभावी नहीं हो सकते । धीरे धीरे परन्तु लगातार देश में स्वर्ण के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रतिबन्ध लगाना होगा । इन मूल बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निश्चय किया है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अधीन 14 कैरेट से अधिक के सोने के आभूषण बनाने पर लगे प्रतिबन्ध हटाये जायें । इससे बहुत से स्वर्णकारों को लाभ होगा और सभा में और सभा के बाहर जो सुझाव रखे गये हैं और जो आलोचना की गई है, उनको काफी हद तक तुष्ट किया जा सकेगा । यह निश्चित करने के लिए कि इस ढील से स्वर्ण का तस्कर व्यापार न बढ़े, हमारी स्वर्ण नीति के दीर्घकालीन उद्देश्य पूरे करने के लिये कुछ अन्य उपाय करना अनिवार्य होगा ।

सरकार का विचार है कि स्वर्ण को मूल भूत रूप में अर्थात छड़ें, सिलें, पटिया, बिलेट, गोलियां, शलाकायें, राड और तार रखने को निषिद्ध किया जाये । जिन लोगों के पास मूलभूत रूप से स्वर्ण वैध रूप में है या जिन्होंने स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अधीन सोने के सम्बन्ध में घोषणा कर दी है और जिनके पास छूट दी हुई सीमा के अन्दर सोना है, उनको उचित समय दिया जायेगा ताकि वे या तो उसे लाइसेंसदार व्यापारियों को बेच दें या आभूषणों में परिवर्तित कर दें । इस प्रकार आभूषण बनाने के लिये बाजार में अधिक स्वर्ण उपलब्ध हो सकेगा ।

सोना साफ करने वाले कारखानों को सरकारी नियंत्रण में लाया जायेगा और बाद में उन्हें राज्य के स्वामित्व में लाया जायेगा । यह सुनिश्चित करने के लिये कि तस्कर रूप में लाया हुआ स्वर्ण अबाध रूप से आभूषणों में परिवर्तित न किया जा सके, उन लोगों को यह घोषणा करनी होगी, जिनके पास उस सीमा से अधिक, जो निर्धारित की जायेगी, स्वर्ण आभूषण हैं । वह सीमा इस प्रकार निश्चित की जायेगी जिससे ऐसे अधिकांश लोगों को ऐसी घोषणा न करनी पड़े जिनके पास उचित मात्रा में स्वर्ण आभूषण हैं ।

राजकोषीय नीतियां और सार्वजनिक शिक्षा इस प्रकार बनाई जायेगी कि लोगों को स्वर्ण के प्रयोग करने की आदत छुड़ाई जा सके क्योंकि इसके कारण हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है । सरकार इन परिवर्तनों को आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं करने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र लागू करना चाहती है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मेरा सुझाव है कि सरकार सभी स्वर्णकारों की रिहाई के लिये तुरन्त कार्यवाही करे ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : विभिन्न राज्यों में तथा दिल्ली में भी दस भूख हड़ताली अभी तक जेलों में हैं । उन सभी को रिहा किया जाना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रधान मंत्री को अपने वक्तव्य के अन्त में उन सभी स्वर्णकारों के बारे में कहना चाहिये था जिन्हें आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और अवैध रूप से अवरुद्ध किया गया था ।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : मैं माननीय सदस्यों के इन विचारों का समर्थन करता हूं कि गिरफ्तार किये गये सभी स्वर्णकार रिहा किये जायें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : All those goldsmiths should be released. The jail authorities have not behaved properly with the persons arrested day before yesterday. A person named Jaswant Singh was beaten. Should such a behaviour be meted out to the demonstrators.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम स्वर्णकारों की रिहाई के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे । मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे भूख-हड़ताल छोड़ दें ।

योजनाओं के पुनर्विन्यास के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : REORIENTATION OF PLANS—Contd.

Shri Sheo Narain (Bansi) : I should be given an opportunity to speak on this resolution. I move that the time for this resolution may be extended by one hour.

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें ।

Shri Sheo Narain : My motion should be put to vote.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं । वह कृपया बाहर चले जायें ।

Shri Sheo Narain : I am entitled to move a motion.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें अथवा सभा से उठकर बाहर चले जायें ।

श्री शिव नारायण : मैं बाहर चला जाऊंगा ।

[**श्री शिव नारायण सभा भवन से चले गये**
Shri Sheo Narain left the House]

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं इस संकल्प से सहमत हूं । सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की लगातार उपेक्षा करती रही है । उसने सिंचाई, ग्रामों में जल व्यवस्था करने की योजना और वहां विद्युत देने की ओर बहुत कम ध्यान दिया है ।

हमारे देश के बहुत से भागों में कई सप्ताह तथा कई मास तक कोई जल नहीं मिलता और लोगों को जल के लिये मीलों तक जाना पड़ता है । सदन को रायलसीमा और राजस्थान

की स्थिति के बारे में जानकारी दें। देश के प्रत्येक भाग में जल की व्यवस्था करने के प्रश्न को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये।

इसकी बजाय कि कृषकों को और अधिक धन दिया जाये, सरकार अधिक करों द्वारा उनके साधन ले रही है। कर का भार अधिक और कुचल देने वाला होता जा रहा है। सरकार भूमि के लगानों की दरों में पुनरीक्षण करके अथवा विशेष कर या वाणिज्यिक फसलों पर अधिभार लगा कर साधनों में वृद्धि करना चाहती है। ग्रामीण लोगों के लिये चतुर्थ योजना आशाजनक नहीं है, निर्धारित की गई राशि का तीन चौथाई भाग तो केवल नगरों पर व्यय होगा।

चतुर्थ योजना का प्रारूप आशाओं का एक बड़ा दस्तावेज है जिसके द्वारा सत्तारूढ़ दल लोगों के मत प्राप्त करना चाहता है। परन्तु उनकी आशायें पूरी नहीं हो सकेंगी। वह मत नहीं प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि पहले से ही असन्तुष्ट लोग अब उन पर विश्वास नहीं करते। मुझे आशा है कि वे लोगों को धोखा देने में असफल नहीं होंगे।

योजना तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अशोक मेहता) : चौथी योजना का प्रारूप संसद में पेश किया गया है और उसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सदस्यों के सुझावों तथा विचारों पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा। हमें आशा है कि संसद समितियां स्थापित करेगी जैसे उसने पहले भी किया है और अन्तर्सत्रावधि में यह समितियां योजना के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करेंगी।

विभिन्न पहलुओं से योजना पर विचार करना होगा और जब तक उन पर पूर्णतया विचार नहीं किया जायेगा तब तक कोई निर्णय करने से पूर्व हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। यदि हम विद्युत लगाना चाहते हैं तो हमें अल्युमिनियम उद्योग का विकास करना होगा। यदि हम उर्वरक उद्योग का विकास करना चाहते हैं तो हमें अनेक उद्योगों, शोधक कारखानों और तेल की खोज आदि से सम्बन्धित कार्य स्थापित करने होंगे। अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर अनेक बातें आवश्यक हैं। हमने इन बातों पर बहुत सावधानी से और बहुत सचाई से विचार किया है। संसद में विभिन्न दलों के समक्ष यह बातें रखने के अवसर का हम स्वागत करेंगे।

हमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। योजना आयोग ने ग्रामों में विद्युत लगाने से सम्बन्धित राज्यों की 1966-67 की योजनाओं के सम्बन्ध में कार्यकारी दलों द्वारा की गई छानबीन को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है। सम्भव है कि कुछ राज्यों में नई मांगें पैदा हो जायें। उन पर भी विचार करना होगा जैसा कि प्रति वर्ष किया जाता है।

छोटी सिंचाई के सम्बन्ध में कई राज्यों ने अनुपूरक आवश्यकतायें प्रस्तुत की हैं। विभिन्न दलों ने इनकी छानबीन की है। कृषि मंत्रालय ने भी यह सुझाव दिया है कि 24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। योजना आयोग ने इस सुझाव का समर्थन किया और वित्त मंत्रालय के साथ इस सम्बन्ध में बात करनी है। हमने कुछ राज्यों के साथ चर्चायें आरम्भ कर

दी हैं। इन विषयों पर विचार अवश्य करना होगा। इसलिए, हमने कहा है कि परिणामों के आधार पर प्रति वर्ष योजना में परिवर्तन करना होगा।

हमें आवश्यक मुख्य संसाधन कृषि से प्राप्त होने की आशा है। कृषि में बहुत बड़ी राशियां लगाये बिना हम यह आशा नहीं कर सकते कि विकास कार्य आगे बढ़ेगा। छोटी सिंचाई के लिए तृतीय योजना में 177 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी। चौथी योजना में यह राशि 520 करोड़ रुपये रखी गई है। ग्रामों में विद्युत लगाने के बारे में तृतीय योजना में 105 करोड़ रुपये और चतुर्थ योजना में 250 करोड़ रुपये रखे गये हैं। ग्रामों में जल की व्यवस्था के लिए अब 150 करोड़ रुपये रखे गये हैं जबकि तृतीय योजना में 80 करोड़ रुपये रखे गये थे। कृषि के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 300 करोड़ रुपये की धनराशि की तुलना में चौथी योजना में 920 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सही है कि हमें वास्तविक परिणाम देखने होंगे और हम ठीक वही कार्य कर रहे हैं।

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। पिछली योजना के दौरान बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 2,300 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे, जिसमें से केवल 1300 करोड़ रुपये व्यय किये गये। क्या आपने यह कमी पूरी की है ?

श्री अशोक मेहता : मैं इस सम्बन्ध में किसी भी वर्ग के साथ बैठकर बातचीत करने के लिये तैयार हूं। परन्तु अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर भी विचार करना होगा न कि किसी विशेष क्षेत्र के बारे में ही।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : तीनों योजनाओं तथा सरकार की कार्य प्रणाली से जो अनुभव हुआ है उससे और विशेषतया चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष में किये गये उपबन्धों से हमें यह कहना पड़ता है कि सरकार तृतीय योजना में किये गये दावों के उलटे चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की व्यवस्था करने और सिंचाई के लिये इस वर्ष जुटाये जाने वाले अतिरिक्त धन के सम्बन्ध में सरकार को सितम्बर में कुछ निर्णय करने हैं। हमें चालू अधिवेशन में ही यह बताया जाना चाहिये कि मंत्री महोदय कितने अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने जा रहे हैं और वह उस सभा में व्यक्त की गई भावनाओं को कितना महत्व देते हैं। आशा है मंत्री महोदय इस मामले की ओर उचित ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री यशपाल सिंह का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री श्रीनारायण दास का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं। से मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं।

प्रश्न यह है :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"इस सभा की राय है कि सरकार को सिंचाई, विद्युतीकरण और पानी की सप्लाई के लिये ग्रामीण क्षेत्रों को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : स्थानापन्न प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के कारण मूल प्रस्ताव तथा अन्य संशोधन अब नहीं लिये जा सकते ।

मद्रास के लिए पीने के पानी सम्बन्धी योजना के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : SCHEME FOR DRINKING WATER FOR MADRAS

श्री सेझियान (पैरम्बलूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सभा की राय है कि सरकार को चाहिये कि वह मद्रास शहर को पीने के पानी की समुचित सप्लाई की व्यवस्था करने के हेतु एक योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये मद्रास की राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार 3 सितम्बर, 1966/12 भाद्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, September 3, 1966/Bhadra 12, 1888 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—12-1-68—565